

आर्थिक समीक्षा 2021-22



www.visionias.in



8468022022, 9019066066

Delhi | Jaipur | Ahmedabad | Hyderabad | Pune | Lucknow | Chandigarh | Guwahati

आर्थिक समीक्षा का सारांश

2021-22

विषय सूची

अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति (State of the Economy)	2
अध्याय 2: राजकोषीय घटनाक्रम (Fiscal Developments).....	17
अध्याय 3: वैदेशिक क्षेत्र (External Sector).....	29
अध्याय 4: मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता (Monetary Management and Fiscal Intermediation).....	38
अध्याय 5: कीमतें और मुद्रास्फीति (Prices and Inflation)	50
अध्याय 6: संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन (Sustainable Development and Climate Change)	57
अध्याय 7: कृषि और खाद्य प्रबंधन (Agriculture & Food Management).....	70
अध्याय 8: उद्योग और अवसंरचना (Industry and Infrastructure).....	83
अध्याय 9: सेवाएं (Services).....	95
अध्याय 10: सामाजिक अवसंरचना और रोजगार (Social Infrastructure and Employment)	101
अध्याय 11: उपग्रह से प्राप्त छवियों और मानचित्रण द्वारा विकास की निगरानी (Tracking Development Through Satellite Images & Cartography).....	112

नोट: प्रत्येक अध्याय से सीखने और समझ को बढ़ाने के लिए, अध्यायों के अंत में एक क्विज जोड़ा गया है। क्विज के उत्तर इस डॉक्यूमेंट के अंत में दिए गए हैं।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति (State of the Economy)

परिचय

- कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण विगत दो वर्षों के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक अनिश्चितता वाली स्थिति से प्रभावित रही है। यह प्रभाव संक्रमण की नई लहरों, आपूर्ति-शृंखला से संबंधित व्यवधानों और उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न हुआ है।
- इस संदर्भ में, संवृद्धि में पुनः सुधार की गति और समष्टि-आर्थिक (मैक्रो-इकोनॉमिक) स्थिरता संबंधी संकेतकों की क्षमता, दोनों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, टीकाकरण की प्रगति का मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है। ये सभी उपाय एक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी प्रतिक्रिया हैं। इसके अतिरिक्त, इस वैश्विक महामारी की बार-बार आने वाली लहरों के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक बाधाओं के विरुद्ध प्रतिरोधक भी हैं।

अर्थव्यवस्था की वैश्विक महामारी से पहले के स्तरों पर पुनर्बहाली

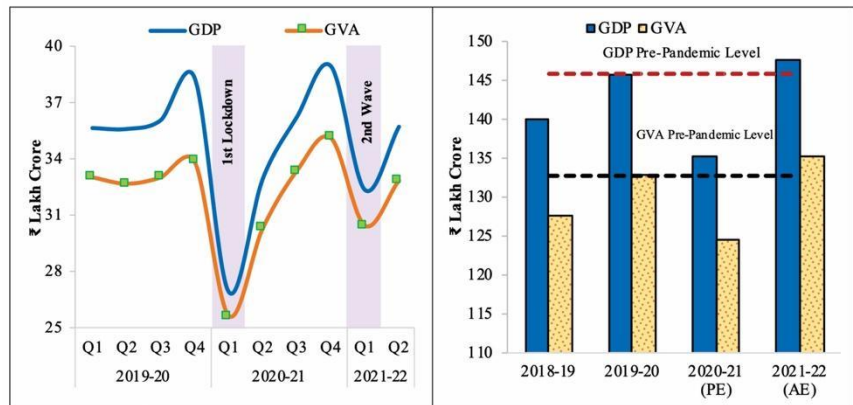
- जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार हो रहा है। हालांकि, पिछले वर्ष के राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की तुलना में अप्रैल-जून 2021 में वैश्विक महामारी की दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव सीमित रहा था। साथ ही, अग्रिम अनुमान यह दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

क्षेत्रवार रुझान (Sectoral Trends)

कृषि

- कृषि क्षेत्र, वैश्विक महामारी जनित बाधाओं से सबसे कम प्रभावित रहा था।
- कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर रहने का अनुमान है। पिछले दो वर्षों में क्रमशः अधिकतम 3.6 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

Gross Domestic Output (Constant Prices, Base Year:2011-12)



Source: National Accounts Statistics (NSO), MoSPI

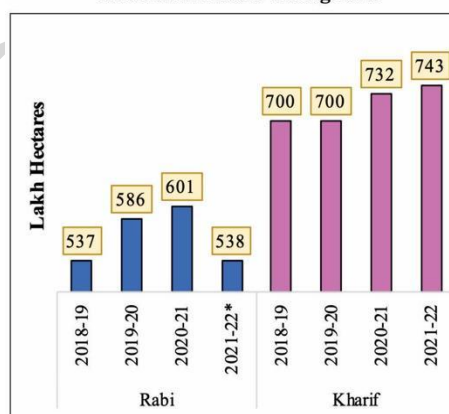
Share of Sectors in Nominal GVA (per cent)

Sectors	2019-20 (1st RE)	2020-21 (PE)	2021-22 (1st AE)
Agriculture & Allied Sectors	18.4	20.2	18.8
Industry	26.7	25.9	28.2
Mining & quarrying	1.9	1.6	2.3
Manufacturing	14.7	14.4	15.4
Electricity, gas, water supply & other utility services	2.6	2.7	2.5
Construction	7.4	7.2	8.0
Services	55.0	53.9	53.0
Trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting	18.9	16.4	16.9
Financial, real estate & professional services	21.2	22.1	20.9
Public administration, defence and Other Services	14.9	15.4	15.2
GVA at basic price	100.0	100.0	100.0

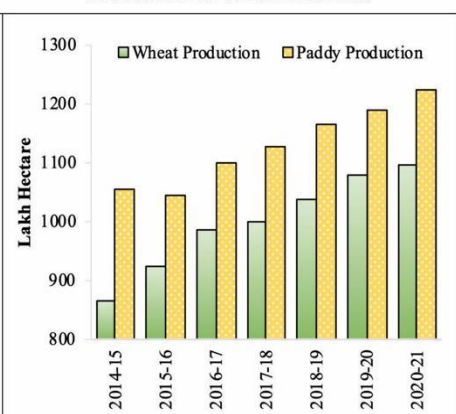
Source: NSO

Note: RE: Revised Estimates, PE: Provisional Estimates, AE: Advance Estimates

Area Sown under Foodgrains



Production of Wheat and Rice



Source: M/o Agriculture & Farmers Welfare; *till 31st December 2021

- इस क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धन¹ में लगभग 18.8% की हिस्सेदारी है।
- पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के खरीफ फसली मौसम में बोया गया क्षेत्र फिर से अधिक था।
 - चालू वर्ष में, खरीफ फसली मौसम में खाद्यान्न उत्पादन 150.5 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।
 - बेहतर मानसूनी वर्षा से भी इसमें मदद मिली है। इससे जलाशयों के जल स्तर में विगत 10 वर्ष के औसत से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

उद्योग

- औद्योगिक क्षेत्र में वित्त वर्ष 2020-21 में 7% की सीमित बढ़ोतरी के साथ इस वित्तीय वर्ष (2021-22) में 11.8% तक की वृद्धि हुई है।
- विनिर्माण, निर्माण और खनन उप क्षेत्रों में भी इसी गति से वृद्धि हुई है। GVA में उद्योगों की वर्तमान भागीदारी अनुमानित 28.2 प्रतिशत रही।
- जनवरी 2021 से, क्रय प्रबंधकों का विनिर्माण सूचकांक² एक महीने (अर्थात् दूसरी लहर के कारण आर्थिक गिरावट वाले अप्रैल 2020) को छोड़कर विस्तारवादी स्तर (अर्थात् सूचकांक में 50 से अधिक के स्तर पर) पर बना हुआ था।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक³ और कोर उद्योग सूचकांक दोनों में एक समान रुझान देखा गया है। साथ ही, ये नवंबर 2021 में, अपने पूर्व-वैश्विक महामारी स्तर (वर्ष 2019 के नवंबर माह की तुलना में) को भी पार कर गए हैं।
- अवसंरचना पर सरकार द्वारा बढ़ता पूंजीगत व्यय और आवास चक्र (आवास निर्माण) में तेजी के कारण निर्माण क्षेत्र पुनर्जीवित हुआ है।
 - इससे स्टील और सीमेंट की खपत एवं उत्पादन का स्तर फिर से पूर्व-कोविड स्तर पर आ गया है।

सेवाएं

- भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की आधे से अधिक की हिस्सेदारी रही है। साथ ही, यह कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित भी हुआ है।
- वर्ष 2020-21 में इस क्षेत्र में समग्र रूप से 8.4% की कमी आई है। वर्ष 2021-22 में इसमें 8.2% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि, विभिन्न उप-क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शन में भी व्यापक अंतर रहा है।
 - हालांकि, वित्त/रियल एस्टेट और लोक प्रशासन क्षेत्र अब पूर्व-कोविड स्तरों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में हैं। इसके विपरीत, वैश्विक महामारी की बार-बार आने वाली संक्रमण लहरों के कारण यात्रा, व्यापार और होटल जैसे क्षेत्र अभी भी पूर्ण रूप से बहाल नहीं हो पाए हैं।
- हालांकि, अगस्त 2021 से क्रय प्रबंधकों के सेवा सूचकांक⁴ में अत्यधिक सुधार हुआ है। साथ ही, खुदरा और मनोरंजन (यानी, रेस्तरां, कैफे, शॉपिंग सेंटर आदि), ट्रांजिट स्टेशन (सार्वजनिक परिवहन केंद्र जैसे मेट्रो, बस एवं ट्रेन स्टेशन) तथा होटल व्यवसाय के लिए गूगल गतिशीलता संकेतकों (Google mobility indicators) में भी समान रूप से सुधार देखा गया है।
- संपर्क-आधारित सेवाओं के विपरीत, दूरस्थ-सक्षम सेवाओं की सकल मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी बढ़ी है। यह मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्य, शिक्षा और यहां तक कि चिकित्सा सेवाओं में दूर से परस्पर संपर्क/क्रिया की बढ़ती प्राथमिकता के कारण हुई है। इस प्रकार, सॉफ्टवेयर और आई.टी. संचालित सेवाओं के निर्यात में तेजी आई है।

मांग संबंधी रुझान (Demand Trends)

- निजी खपत को छोड़कर, नवीनतम अग्रिम अनुमान वस्तुतः वित्त वर्ष 2021-22 में मांग पक्ष के तहत शामिल सभी घटकों की पूर्ण बहाली (recovery) को व्यक्त करते हैं।

Annual Real growth in demand side of GDP and its components (per cent)

Components	2019-20 (1st RE)	2020-21 (PE)	2021-22 (1st AE)	Recovery over 2019-20
Total Consumption	5.9	-7.3	7.0	99.2
Government Consumption	7.9	2.9	7.6	110.7
Private Consumption	5.5	-9.1	6.9	97.1
Gross Fixed Capital Formation	5.4	-10.8	15.0	102.6
Exports	-3.3	-4.7	16.5	111.1
Imports	-0.8	-13.6	29.4	111.8
GDP	4.0	-7.3	9.2	101.3

Source: NSO

Note: RE - Revised Estimates, PE - Provisional Estimates, AE - Advance Estimates

¹ Gross Value Added: GVA

² Purchasing Managers' Index-Manufacturing

³ Index of Industrial Production: IIP

⁴ Purchasing Managers' Index-Services

निर्यात, सरकारी खपत, सकल अचल पूंजी निर्माण और आयात में बहाली सबसे अधिक रही है।

उपभोग (Consumption)

- वर्ष 2021-22 में कुल उपभोग में 7% की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें सरकारी खपत की हिस्सेदारी सर्वाधिक है।
 - पूर्व-महामारी के स्तर को पार करते हुए सरकारी उपभोग में 7.6% की भारी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।
 - निजी उपभोग में भी उल्लेखनीय रूप से सुधार होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह पूर्व-महामारी उत्पादन स्तर के 97% तक हो सकती है।
- तीव्र टीकाकरण और आर्थिक गतिविधियों के तेज गति से सामान्य होने के कारण निजी खपत में उल्लेखनीय सुधार देखे जा सकते हैं।
- वाहन पंजीकरण में हालिया गिरावट उपभोग की मांग में कमी होने की बजाये, सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के कारण सतत आपूर्ति-पक्ष संबंधी कमी को दर्शाती है।

निवेश (Investment)

- निवेश को सकल स्थायी पूंजी निर्माण⁵ के माध्यम से आकलित किया गया है। निवेश में वित्त वर्ष 2021-22 में 15% की भारी वृद्धि होने और इसके यथाशीघ्र महामारी पूर्व-स्तर तक पूर्ण वापसी होने की उम्मीद जताई गई है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और अवसंरचनात्मक व्यय में बढोतरी हुई है। इससे वित्त वर्ष 2021-22 में निवेश-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़कर लगभग 29.6 प्रतिशत हो गया है। यह विगत सात वर्षों में सबसे अधिक रहा है।
- हालांकि, निजी निवेश की पुनर्वापसी अभी भी प्रारंभिक अवस्था में ही है। ऐसे कई संकेत/उदाहरण मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत मजबूत निवेश के लिए तैयार है। एक मजबूत और स्वच्छ छवि वाला बैंकिंग क्षेत्र निजी निवेश को पर्याप्त रूप से समर्थन देने के लिए तैयार है।

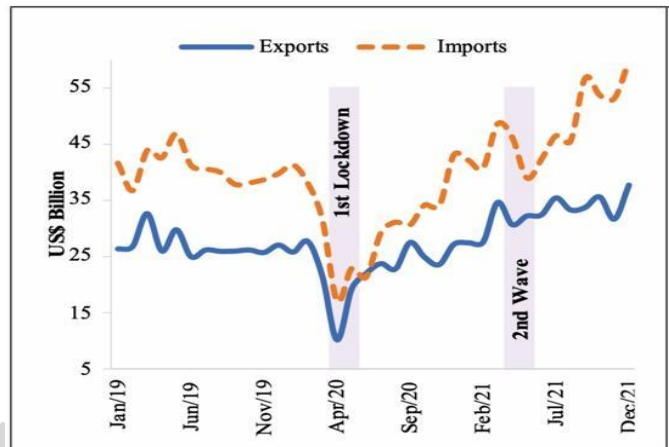
निर्यात और आयात (Exports and Imports)

- वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के कुल निर्यात में 16.5 प्रतिशत बढोतरी होने की संभावना प्रकट की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में आयात में 29.4 प्रतिशत बढोतरी होने की उम्मीद है, ये दोनों ही महामारी पूर्व स्तर को पार कर गए हैं।
- भारत का निवल निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 की इसी अवधि के अधिशेष की तुलना में, वित्त वर्ष 2021-22 की पहली

छमाही में नकारात्मक हो गया है। पहली छमाही में चालू खाते में मामूली घाटा (सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत) दर्ज किया गया है।

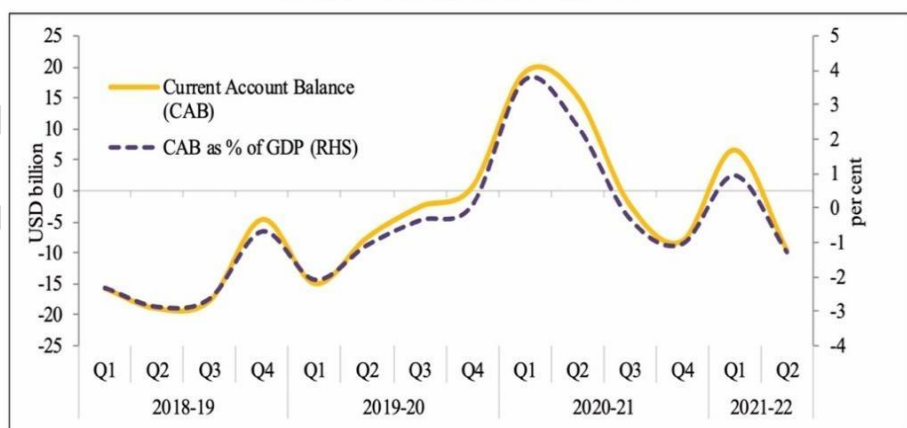
- वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि, घरेलू मांग में बढोतरी तथा पूंजी प्रवाह को लेकर बढ़ती अनिश्चितता वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान चालू खाता घाटे को और बढ़ा सकते हैं।

Foreign Trade



Source: Ministry of Commerce

India's Current Account Balance



Source: RBI

⁵ Gross Fixed Capital Formation: GFCF

बारबेल रणनीति, सुरक्षा जाल और सुदृढ़ प्रतिक्रिया (Barbell Strategy, Safety Nets & Agile Response)

- भारत सरकार ने विगत दो वर्षों में उत्परिवर्तित वायरस की नई लहरों के साथ अनिश्चितताओं का सामना किया है। इस संदर्भ में सरकार ने एक "बारबेल रणनीति" को अपनाया है। इसके अंतर्गत सूचना के बायसेन अपडेट⁶ के आधार पर एक लचीली नीतिगत प्रतिक्रिया के साथ एक सुरक्षा-जाल का गठन किया गया है। इसकी मदद से समाज/ व्यवसाय के कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
- यह वित्तीय बाजारों के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य रणनीति है। इसका प्रयोग दो अलग-अलग प्रतिक्रियाओं को मिलाकर अत्यधिक अनिश्चितता से निपटने के लिए किया जाता है।
- इस रणनीति का पुनरावृत्त चरण "एजाइल/सक्रिय" दृष्टिकोण के समान है। यह फीडबैक-लूप और रीयल-टाइम समायोजन के उपयोग पर आधारित है।
 - फीडबैक-लूप आधारित नीति-निर्माण रीयल-टाइम डेटा की उपलब्धता की स्थिति में अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। हालांकि, पिछले दो वर्षों में, सरकार ने अनेक उच्च आवृत्ति संकेतकों⁷ का उपयोग किया है। इनमें GST संग्रह, विद्युत की खपत, गतिशीलता संकेतक, डिजिटल भुगतान, जहाजी माल की आवाजाही, राजमार्ग टोल संग्रह आदि शामिल हैं।
 - एक अनिश्चित परिवेश में, एजाइल/सक्रिय ढांचा, लघु पुनरावृत्तियों में परिणामों का आकलन करके तथा इन आकलनों को सतत वृद्धिशील रूप से समायोजित करके प्रतिक्रिया करता है। यह "वाटरफॉल" ढांचे से भिन्न है। इसका भारत और विश्व के अधिकांश हिस्सों में नीति तैयार करने हेतु एक पारंपरिक तरीके के रूप में प्रयोग किया जाता है।
 - वाटरफॉल दृष्टिकोण के अंतर्गत समस्या के विस्तृत विश्लेषण व प्रारंभिक मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इसके बाद कार्यान्वयन के लिए एक सुदृढ़ अग्रिम योजना तैयार की जाती है। यह पद्धति इस आधार पर कार्य करती है कि सभी आवश्यकताओं को शुरुआत से ही समझा जा सकता है। इस प्रकार इसकी मदद से कार्रवाई के एक निश्चित मार्ग को पहले ही तैयार किया जा सकता है। ये विचार पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं और मजबूत शहरी मास्टर-प्लान में देखे जा सकते हैं।
- एजाइल/सक्रिय कार्यप्रणाली की लोचशीलता, प्रतिक्रियात्मकता में सुधार लाती है। साथ ही, इसे और बेहतर बनाने में मदद करती है। लेकिन यह भविष्य के परिणामों का पूर्वानुमान करने में असमर्थ है। इस प्रकार, बारबेल रणनीति का दूसरा तरीका सुरक्षा जाल प्रदान करके अप्रत्याशित नकारात्मक परिणामों को कम करने में सहयोग करता है। यह वर्ष 2020-21 में सरकार के शुरुआती उपायों को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को आपातकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना आदि।

कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए सुरक्षा जाल का उपयोग किया गया

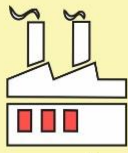
- प्रत्येक सदी में एक बार उत्पन्न होने वाली महामारी से जुड़ी गंभीर अनिश्चितता को देखते हुए, सरकार ने महामारी जनित प्रतिकूल प्रभावों से निपटने हेतु आपातकालीन सहायता और आर्थिक नीतिगत कार्यवाहियों के उचित विकल्पों को अपनाया है।
- वर्ष 2020 की शुरुआत में, जब पूरा विश्व महामारी की पहली लहर से प्रभावित था, तब सरकार ने अपना संपूर्ण ध्यान आपातकालीन नीतिगत कार्यवाहियों के माध्यम से लोगों की जान बचाने पर केंद्रित किया था। इन कार्यवाहियों में कठोर लॉकडाउन एवं टेस्टिंग जैसे उपाय शामिल थे।
- सरकार ने देखा कि लॉकडाउन और क्वारंटाइन आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर रहे हैं। इसलिए, सरकार ने यथाशीघ्र आर्थिक सुरक्षा तंत्र (तालिका देखें) उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास किए थे। इसके साथ ही, टीकाकरण कार्यक्रम को भी तीव्र गति से संचालित किया गया था।

⁶ Bayesian updating

⁷ High Frequency Indicators: HFI

कोविड-19 के दौरान तनाव को रोकने के लिए किए गए प्रमुख सुरक्षा उपाय

आधार	रक्षोपाय
 नकद अंतरण	- महिला जन धन खाताधारकों को 3 महीने के लिए 500 रुपये / माह - सुभेद्य वर्गों (विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग) को 1,000 रुपये - प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) – तीन किस्तों में 6,000/- रुपये प्रति वर्ष
 खाद्य सुरक्षा	- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के माध्यम से वितरित किए जाने वाले नियमित मासिक खाद्यान्न के अलावा NFSA के 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। - रोजगार के लिए लगातार स्थान परिवर्तित करने वाले लोगों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना, जो उनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभ सुनिश्चित करेगा। - उज्ज्वला के तहत रसोई गैस सिलेंडर का वितरण।
 रोजगार	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - मनरेगा मजदूरी में वर्ष 2019-20 की मजदूरी दर से 20 रुपये की वृद्धि 100 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों में 15,000 रुपये से कम आय वाले 90 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत 6 महीने के लिए 12 प्रतिशत नियोक्ता का और 12 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान निर्धारित किया गया। - नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने तथा उन्हें और अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) की शुरुआत की गयी है। इसे EPFO द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
 आवास	- प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) - प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)
 कौशल विकास	- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) – ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम 6 राज्यों में वापस आये प्रवासी कामगारों को नए कौशल सिखाने और उनके कौशल का उन्नयन करने करने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)

- RBI द्वारा सभी सावधि ऋणों के लिए 6 महीने की अधिस्थगन अवधि और ब्याज भुगतान को टालना
- MSMEs के डिफॉल्ट ऋणों का पुनर्गठन – अगस्त 2020 और मई 2021, RBI की योजनाएं
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
- MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGS)



ऋण

- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया शुरू करने पर एक वर्ष के लिए रोक; और न्यूनतम सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया।
- RBI द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये की आवधिक नकदी सुविधा।
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) को ऋण देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- MSME और व्यक्तियों को नए ऋण देने के लिए NBFC, HFC और MFI के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0
- लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो संचालन
- लघु वित्त बैंकों (SFB) द्वारा MFI को दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधारी (PSL) के रूप में वर्गीकृत किया जाना
- नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी निधि
- राष्ट्रव्यापी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम
- किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान – 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रोत्साहन
- पी.एम. स्वनिधि योजना
- स्वयं सहायता समूह (SHG)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- NBFC, HFC और MFI के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी योजना कोविड प्रभावित क्षेत्रों, जैसे- स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, पर्यटन, आदि के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना

मौद्रिक और वित्तीय सहायता (Monetary and Financial Support)

- मौद्रिक नीति समिति⁸ ने फरवरी से मई 2020 के दौरान नीतिगत रेपो दर में 115 आधार अंकों (basis points) की कटौती की थी। इस प्रकार, पिछले बारह महीनों में 135 आधार अंकों की कटौती हुई। हालांकि तब से, MPC ने नीतिगत रेपो दर को यथावत और इसे 4 प्रतिशत पर स्थिर बनाए रखा है। साथ ही सीमांत स्थायी सुविधा⁹ दर और बैंक दर को भी 4.25 प्रतिशत पर स्थिर बनाए रखा गया है। इसी तरह रिवर्स रेपो दर को भी 3.35 प्रतिशत पर यथावत बनाए रखा है।

उच्च आवृत्ति संकेतक (High Frequency Indicators: HFIs)

- पिछले दो वर्षों में, सरकार ने वास्तविक समय के आधार पर अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित स्थिति के आकलन हेतु उद्योग, सेवाओं, वैश्विक रुझानों एवं समष्टि-आर्थिक स्थिरता संकेतकों पर आधारित 80 HFIs की एक श्रृंखला का उपयोग किया है। इन संकेतकों में विद्युत उत्पादन, अनुसूचित घरेलू उड़ानें, वित्तीय लेन-देन की मात्रा / मूल्य, पूंजी प्रवाह आदि शामिल हैं।
- भले ही HFIs को वास्तविक समय के आधार पर और बारंबार प्रयोग किया जा सकता है, फिर भी उन्हें सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि इसमें मौजूद प्रत्येक संकेतक विकास का आंशिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसके अलावा, वांछित और गैर-वांछित अनुपात (Signal to Noise Ratio) राष्ट्रीय खातों और अन्य मंद गति के प्रगतिशील डेटा की तुलना में अधिक हो सकता है। इस प्रकार, अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए HFIs का उपयोग करना विज्ञान के समान एक कला है।

⁸ Monetary Policy Committee: MPC

⁹ Marginal Standing Facility: MSF

टीकाकरण

- टीकाकरण ने जीवन संबंधी क्षति को कम करने, गतिविधियों को पुनः तीव्र गति से संचालित करते हुए अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाने और दूसरी लहर के कारण उत्पादन में क्रमिक गिरावट को रोकने आदि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समष्टि-आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability)

- यह खंड सभी मोर्चों/पक्षों यथा विदेशी क्षेत्र, राजकोषीय संकेतक, वित्तीय क्षेत्र और मुद्रास्फीति पर समष्टि आर्थिक स्थिरता संकेतकों का विश्लेषण करता है।

वैदेशिक या बाह्य क्षेत्र (External sector)

- विगत दो वर्षों के दौरान भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष की स्थिति में रहा है। इसने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का अवसर प्रदान किया है। 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब रहा है। यह 13.2 महीने के आयात के बराबर है और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। नवंबर 2021 के अंत तक,

भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक रहा है।

- भारत के विदेशी क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करने वाले संकेतक मजबूत और बेहतर रहे हैं। ये संकेतक वैश्विक वित्तीय संकट या वर्ष 2013 के टेपर ट्रेंडम (मौद्रिक तरलता की निकासी) की घटना के दौरान जो वे थे, उनकी तुलना में मजबूत और बेहतर हैं।

- फेडरल रिजर्व ने मात्रात्मक सुगमता (Quantitative

Easing: QE) के तहत परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम शुरू किया था। यह वर्ष 2007-08 के

वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए व्यापक

नीतिगत प्रतिक्रिया का एक हिस्सा था।

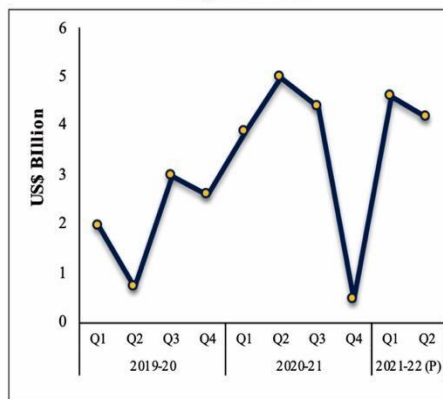
Comparison of Macroeconomic Indicators during Global Financial Crisis, Taper Tantrum and COVID-19

	Global Financial Crisis	Taper Tantrum	COVID-19 Pandemic
Macroeconomic Indicators	2008-09	2012-13	2021-22
CPI inflation	9.1	9.4	5.2 Apr-Dec 2021
India's Gross Fiscal Deficit as % of GDP	8.3	6.9	10.2 2021-22 (BE)
Fiscal Deficit of EMDEs (Asia) as % of GDP	1.6	1.7	7.8 2021
Current Account Balance as % of GDP	-2.3	-4.8	-0.2 Apr-Sept 2021
External Debt as % of GDP	20.7	22.4	20.2 June 2021
Forex Reserves (US\$ billion)	252	292	634 31 st Dec 2021
Govt Bond Yields 10-year	7.3	8.0	6.4 11 th Jan 2022
Total FDI inflows (US\$ billion)	8.3	34.0	48.4 Apr-Oct 2021
SCBs Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)	13.2	13.9	16.5 Sept 2021
SCBs Provision Coverage Ratio	-	47.6	68.1 Sept 2021

Source: NSO, MoSPI, RBI, CGA, CDSL, Ministry of Finance, IMF.

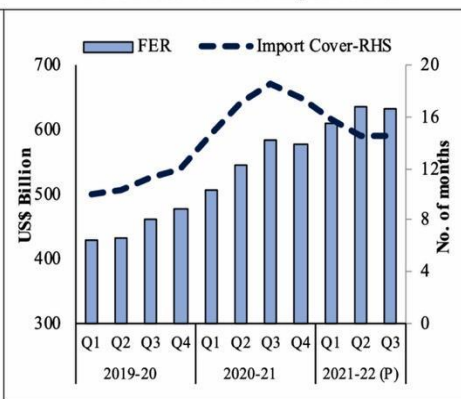
Note: The taper tantrum happened in 2013. In the table above, 2012-13 is used to show the position just prior to taper tantrum as this is analogous to the present situation prior to withdrawal of liquidity in financial markets.

Surplus in BoP

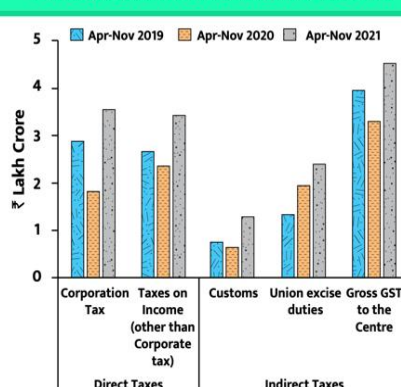


Source: RBI

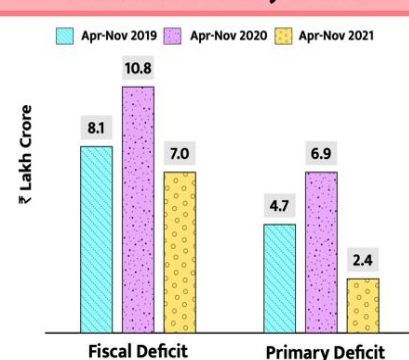
Forex reserves and Import Cover



Direct and indirect tax revenue



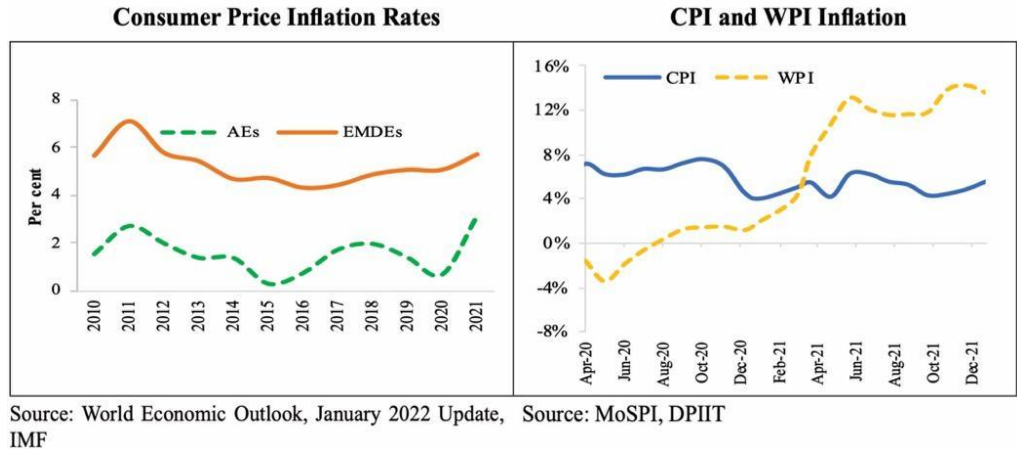
Fiscal and Primary Deficit



- अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से प्रभावित हो गई थी। इस दौरान, QE के माध्यम से मंदी के प्रभाव को कम करने के प्रयास किये गए थे। इस प्रयास में, 22 मई 2013 को, फेडरल रिज़र्व ने घोषणा की थी कि भविष्य में संपत्ति की खरीद को कम किया जाएगा। इससे बॉण्ड प्रतिफल में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई और अन्य देशों से मुद्रा का बहिर्वाह शुरू हो गया। परिणामस्वरूप, भारत को भी विदेशी मोर्चे पर बाधाओं का सामना करना पड़ा।
- फिर भी, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की एक स्थायी स्थिति और बढ़ती निर्यात आय के चलते आगे वर्ष 2022-23 में किसी भी संभावित वैश्विक तरलता की कमी के विरुद्ध आवश्यक बफर/सुरक्षा प्राप्त होगा।

राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance)

- हालांकि, वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण में वृद्धि हुई थी, लेकिन अब तक वर्ष 2021-22 में सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- साथ ही, अप्रैल-नवंबर 2021 में राजकोषीय घाटा, बजट अनुमानों में 46.2 प्रतिशत रहा है। यह पिछले दो वर्षों की इसी अवधि के दौरान प्राप्त अनुपात का लगभग एक तिहाई है।



वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector)

- प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर 2021 में अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। अप्रैल-नवंबर 2021 में 75 IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफर) के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपये जुटाये गए थे। यह पिछले दशक के किसी भी वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है।
- बैंकिंग तंत्र अच्छी तरह से पूंजीकृत है। साथ ही, वर्ष 2018-19 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों¹⁰ के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति¹¹ अनुपात और निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति¹² अनुपात में गिरावट जारी है।
 - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात सितंबर 2020 के अंत के 7.5% से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9% हो गया है।
 - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का NNPA अनुपात भी वर्ष 2017-18 के अंत के 6% से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 2.2% हो गया है।
 - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात¹³ सितंबर 2020 के अंत के 15.84% से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 16.54% हो गया है।

मुद्रास्फीति (Inflation)

- भारत में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक¹⁴ मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में घटकर 5.2% हो गई है। यह वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर की अवधि) में 6.6% थी।
- हालांकि, थोक मूल्य सूचकांक¹⁵ मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में जारी है। WPI के 'ईंधन और विद्युत्' मद में मुद्रास्फीति 20% से अधिक थी। यह उच्च अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतों को दर्शाती है।

¹⁰ Scheduled Commercial Banks: SCBs

¹¹ Gross Non-Performing Assets: GNPA

¹² Net Non-Performing Assets: NNPA

¹³ Capital to risk-Weighted Asset Ratio: CRAR

¹⁴ Consumer Price Index: CPI

वैश्विक आपूर्ति-पक्ष बाधाएं (Global Supply-Side Disruption)

- ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था फिर से बहाल होने लगी थी। किंतु फिर भी इसे वितरण में देरी, कंटेनर की कमी और सेमीकंडक्टर चिप के अभाव से लेकर गंभीर आपूर्ति-पक्ष से जुड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

शिपिंग कंटेनर की कमी और बढ़ती व्यापार लागत

- कंटेनरों की कमी के कारण समुद्री माल भाड़ा में 300 प्रतिशत से 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इसके अलावा, वर्ष 2019 के बाद से नए कंटेनरों के उत्पादन में गिरावट आई है। साथ ही, कंटेनरों के निपटान में भी वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, जब तक वैश्विक स्तर पर उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तब तक यह एक स्थायी समस्या बनी रहेगी।

ऑटोमोबाइल उद्योग पर सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) उद्योग से जुड़ी आपूर्ति संबंधी चुनौतियों का प्रभाव

- रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर उद्योग संबंधी आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं से लगभग 169 से अधिक उद्योग प्रभावित हुए हैं।
- सेमीकंडक्टर (अर्धचालकों) के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसकी उत्पादन पूर्व तैयारी अवधि 6-9 महीने की होती है। इसका लगभग 18-20 सप्ताह का उत्पादन चक्र होता है। इसलिए, आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं की समाप्ति में अधिक समय लग सकता है और उल्लेखनीय व्यय करना पड़ सकता है।
- ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा वर्धित मूल्य में माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की हिस्सेदारी लगभग 4.7 प्रतिशत है। आपूर्ति में विलंब होने के साथ, वर्ष 2021 में ऑटोमोबाइल उद्योग का औसत लीड टाइम वैश्विक स्तर पर लगभग 14 सप्ताह रहा है।

आपूर्ति पक्ष सुधार(Supply Side Reforms)

- आपूर्ति-पक्ष सुधारों में अनेक क्षेत्रों का विनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, 'भूतलक्षी कर' (retrospective tax) आदि जैसे पुराने मुद्दों का निपटान, निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।
- हालांकि, विनियमन प्रक्रिया की जगह **प्रक्रियागत सुधारों** पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। **विनियमन प्रक्रिया** किसी विशेष गतिविधि से सरकार की भूमिका को कम करने या हटाने से संबंधित है। **प्रक्रियागत सुधार** मोटे तौर पर उन गतिविधियों के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण और सुगमता से संबंधित है। यहां सरकार की भूमिका एक सुविधाकर्ता या विनियामक के रूप में होती है।
- भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया में आपूर्ति पक्ष पर दिया गया जोर मुख्यतः **दो महत्वपूर्ण विचारों** से प्रेरित रहा है। **प्रथम**, आरोपित यात्रा प्रतिबंधों, लॉकडाउन और आपूर्ति-श्रृंखला के बाधित होने के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को अर्थव्यवस्था के आपूर्ति-पक्ष में रुकावट के रूप में देखा गया है। **दूसरा**, कोविड के बाद की वैश्विक स्थिति कई तरह के कारकों से प्रभावित रही है। इनमें प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, उपभोक्ता व्यवहार, भू-राजनीति, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं।
- **भारत की आपूर्ति-पक्ष रणनीति में दो सामान्य विषय शामिल रहे हैं।**
 - **पहला**, वे सुधार जो कोविड के बाद के विश्व में दीर्घकालिक अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए **लचीलेपन और नवाचार में सुधार** करते हैं। इसमें फैक्टर मार्केट सुधार शामिल हैं। उदाहरण के लिए- अंतरिक्ष व ड्रोन जैसे क्षेत्रों का विनियमन।
 - **दूसरा**, वे जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधार पर केंद्रित हैं। इसके तहत जलवायु/पर्यावरण संबंधी नीतियों से लेकर सामाजिक आधारभूत संरचना (जैसे कि नल आधारित पेयजल, शौचालय, बुनियादी आवास आदि) की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- **लचीलापन (flexibility) और सुनम्यता (resilience)** के दो आयामी दृष्टिकोण महामारी के विरुद्ध अल्पकालिक प्रतिक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली बारबेल रणनीति के अनुरूप हैं।

आपूर्ति पक्ष से जुड़े प्रमुख उपाय/सुधार

क्षेत्र	उपाय/सुधार
उद्योग	• 13 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इनमें ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्युटिकल ड्रग्स आदि शामिल हैं। • कर निश्चितता और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूतलक्षी कर को समाप्त कर दिया गया है।
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) क्षेत्र	अन्य सेवा प्रदाताओं (Other Service Providers: OSPs) के लिए उदारीकृत दिशा-निर्देश: • OSP की स्पष्ट परिभाषा: नए दिशा-निर्देश उन संस्थाओं पर लागू हैं, जो अपने ग्राहकों को "आवाज आधारित BPO सेवाएं" प्रदान करते हैं।

¹⁵ Wholesale Price Index: WPI

	• भारत में OSP केंद्रों के लिए पंजीकरण आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। • इन दिशा-निर्देशों के तहत किसी सुविधा या व्यवस्था के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है। • घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय OSP के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। • घर और दूरस्थ स्थानों से कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। • एक ही या असंबंधित कंपनी के दो या दो से अधिक OSP केंद्रों के बीच इंटरकनेक्शन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। • अब OSP के बीच अवसंरचना साझा करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है।
दूरसंचार क्षेत्र	संरचनात्मक सुधार • समायोजित सकल राजस्व का युक्तिकरण: गैर-दूरसंचार राजस्व को समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। • बैंक गारंटी को युक्तिसंगत बनाना: लाइसेंस शुल्क और अन्य समान शुल्कों के लिए बैंक गारंटी आवश्यकताओं में उल्लेखनीय रूप से कमी की गई है। • व्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है और लाइसेंस शुल्क या स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क¹⁶ के विलंबित भुगतान पर आरोपित दंड को हटा दिया गया है। • दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। • भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान प्राप्त किए जाने वाले स्पेक्ट्रम पर कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) आरोपित नहीं किया जाएगा। • स्पेक्ट्रम साझाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रक्रियागत सुधार • वायरलेस उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क क्लियरेंस (समाशोधन) की आवश्यकता को हटा दिया गया है। इसकी जगह स्व-घोषणा के प्रावधान को लागू किया गया है। • टावरों को स्थापित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति की मंजूरी प्रक्रिया दूरसंचार विभाग के सरल संचार पोर्टल पर स्व-घोषणा / स्वचालित समयबद्ध अनुमोदन के माध्यम से संचालित होगी। • स्व-केवाईसी (KYC) की अनुमति प्रदान की गई है। • पेपर कस्टमर एंक्विजिशन फॉर्म को डेटा के डिजिटल स्टोरेज से प्रतिस्थापित किया जाएगा। • नीलामी कैलेंडर को निर्धारित किया गया है। स्पेक्ट्रम नीलामी सामान्यतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाती है। • दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपाय किए गए हैं। इनमें बकाया भुगतान पर अधिस्थगन/स्थगन (moratorium/ deferment) आदि शामिल हैं।
सार्वजनिक खरीद नीति	अक्टूबर 2021 में खरीद और परियोजना प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की गई थी। • कार्यों और गैर-परामर्श सेवाओं से संबंधित बोलीदाताओं के चयन के लिए गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन की अनुमति दी गई है। • भुगतान करने के लिए निश्चित समय सीमा: इसके तहत बिल जमा करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर 75 प्रतिशत या उससे अधिक बिलों के भुगतान को समय पर जारी करने का प्रावधान किया गया है। शेष राशि का भुगतान 28 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम जांच के बाद किया जाएगा। • मध्यस्थता और विवाद समाधान: खरीद अधिकारी किसी भी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने से पहले मामले की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन कर सकते हैं। ○ सरकार ने उन मामलों में जहां एक खरीद एजेंसी ने एक मध्यस्थ पंचाट को चुनौती दी गई हो, वहां बैंक गारंटी के खिलाफ ठेकेदारों को 75 प्रतिशत राशि जारी करने की अनुमति दी है।
विमानन क्षेत्र	• ड्रोन नियम (अगस्त 2021 में घोषित)।

¹⁶ Spectrum Usage Charge: SUC

वित्तीय क्षेत्र	बैंकिंग: बैंक जमा बीमा में सुधार - प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता हेतु निर्धारित बैंक जमा बीमा राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसकी मदद से मार्च 2021 के अंत में कुल खातों में से 98.1 प्रतिशत खातों को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। साथ ही, कुल जमा राशि के 50.9 प्रतिशत हिस्से को बीमाकृत कर लिया गया है। अंतरिम भुगतान की शुरुआत: जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम¹⁷ उन बैंकों के जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान करेगा, जिनके लिए RBI ने कोई प्रतिबंध / स्थगन लगाया है। - जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान प्रदान करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। फैक्टरिंग इकोसिस्टम में विस्तार: जिन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का मुख्य व्यवसाय फैक्टरिंग था, उनकी पहले की स्थिति को हटा दिया गया है और अब सभी NBFCs को फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises: MSMEs)	MSMEs की परिभाषा को संशोधित कर सरल बनाया गया है: - विनिर्माण और सेवा MSMEs के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया गया है। - उद्योग और सेवा क्षेत्र से संबद्ध MSMEs की परिभाषा को संशोधित (उर्ध्वगामी) किया गया है। - MSMEs के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। - सार्वजनिक खरीद नीति के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। - MSEs से खरीद अनिवार्यता को लागू किया गया है। इसके तहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को अपनी वस्तु और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत MSEs से क्रय करना अनिवार्य है। 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा जारी नहीं की जाएगी।
अंतरिक्ष और भू-स्थानिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र की भागीदारी में बढ़ोतरी की गई है। - मानचित्रों सहित भू-स्थानिक डेटा के निर्माण, अधिग्रहण और उपयोग के लिए दिशा-निर्देशों को उदार बनाया गया है। - भू-स्थानिक डेटा एवं मानचित्रों के उपयोग हेतु पूर्व अनुमोदन या लाइसेंस प्राप्त करने की जगह अब सभी संस्थाओं को स्व-प्रमाणन प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्रों में छूट: अत्यधिक संवेदनशील स्थानों की अनूठी विशेषताओं के लिए ही मानचित्रण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। निर्यात प्रतिबंधों पर छूट: संशोधित दिशा-निर्देश के तहत 1:100 तक रिज़ॉल्यूशन वाले मानचित्रों के निर्यात को अनुमति प्रदान की गई है। पहले 1:250000 तक रिज़ॉल्यूशन वाले मानचित्र निर्यात किये जा सकते थे। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित डेटा तक प्रत्यक्ष पहुंच: सार्वजनिक धन का उपयोग करके उत्पादित किये गए सभी भू-स्थानिक डेटा को सभी भारतीय संस्थाओं के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ कराया जाएगा।
विनिवेश	नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति और संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति - इस नई नीति को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश के लिए अधिसूचित किया गया है। - सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण की नीति और रणनीतिक क्षेत्रों में भी न्यूनतम उपस्थिति के साथ इसे वर्गीकृत किया गया है। - चिन्हित रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं: (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; (ii) परिवहन और दूरसंचार; (iii) बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; तथा (iv) बैंकिंग,

¹⁷ Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation: DICGC

	बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। ○ एयर इंडिया का निजीकरण किया गया है। ● राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन का गठन: ○ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक की चार वर्ष की अवधि में केंद्र सरकार की मूल संपत्ति से 6 लाख करोड़ रुपये के बराबर मुद्राकरण किया जा सकता है। ○ इसमें सड़क, रेलवे, बिजली, तेल एवं गैस पाइपलाइन और दूरसंचार सहित शीर्ष 5 क्षेत्र समग्र मूल्य के लगभग 83 प्रतिशत हेतु उत्तरदायी हैं।
श्रम सुधार	केंद्र सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया गया है।
रक्षा क्षेत्र	● आयुध निर्माणी बोर्ड¹⁸ के निगमीकरण को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही, 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की गई है। ● रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत तक और सरकारी मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अवसर प्रदान किए गए हैं।

संवृद्धि आउटलुक

- वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3 प्रतिशत के संकुचन के बाद, वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप से 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। व्यापक वैक्सीन कवरेज, आपूर्ति-पक्ष में सुधार और नियमों में ढील, मजबूत निर्यात वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु राजकोषीय उपलब्धता आदि को सुनिश्चित करते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में संवृद्धि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक रूप से 8.0-8.5 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है।
- विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के अलावा विश्व आर्थिक मंच (IMF) के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) के संवृद्धि संबंधी पूर्वानुमानों के अनुसार, भारत इन तीनों वर्षों (वर्ष 2021-23) में विश्व की सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

शब्दावली	
क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index)	● यह व्यावसायिक गतिविधियों का संकेतक है। इसके अंतर्गत विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ● यह एक सर्वेक्षण-आधारित उपाय है। इसमें प्रतिक्रियादाताओं / संगठनों से एक माह पूर्व के कुछ प्रमुख व्यावसायिक चरों से संबंधित उनकी धारणा में बदलाव को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। ● 50 से ऊपर का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार को दर्शाता है। 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)	● यह एक निर्धारित अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों से संबंधित संवृद्धि दर को दर्शाता है। ● इसकी गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन¹⁹ मासिक आधार पर करता है।
मात्रात्मक सुगमता (Quantitative easing: QE)	● QE तब परिलक्षित होती है जब कोई केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों से दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियां का क्रय करता है। इन प्रतिभूतियों का क्रय कर, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा का विस्तार करता है। इसके परिणामस्वरूप, व्याज दरें कम हो जाती हैं और लोगों के लिए उधार लेना आसान हो जाता है।
टैपेरिंग (Tapering)	● टैपेरिंग एक केंद्रीय बैंक की मात्रात्मक सुगमता की रणनीति की विपरीत स्थिति है। यह आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने का एक तरीका है। टैपेरिंग तब होती है, जब केंद्रीय बैंक परिसंपत्ति या प्रतिभूतियों की खरीद कम कर देता है। ऐसा अर्थव्यवस्था के पर्याप्त रूप से सामान्य होने और प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में किया जाता है।

अध्याय एक नज़र में

- कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण विगत दो वर्षों के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक अनिश्चितता वाली स्थिति से प्रभावित रही है। यह प्रभाव संक्रमण की नई लहरों, आपूर्ति-शृंखला से संबंधित व्यवधानों और उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न हुआ है।

¹⁸ Ordnance Factory Board: OFB

¹⁹ Central Statistical Organisation: CSO

सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया के तहत कमजोर वर्गों को मदद प्रदान करने के लिए सुरक्षा जाल का उपयोग तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि आदि जैसे प्रयास शामिल रहे हैं।
भारतीय प्रतिक्रिया की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि मांग प्रबंधन पर पूर्ण निर्भरता की जगह भारत ने कई क्षेत्रों के विनियमन, प्रक्रियाओं के सरलीकरण आदि जैसे आपूर्ति-पक्ष सुधारों पर जोर दिया है।
अग्रिम अनुमान दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए संकुचन के बाद वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक GDP विस्तार 9.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अधिकांश आबादी को शामिल कर लिया गया है, आर्थिक गति वापस सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर है और आपूर्ति-पक्ष सुधारों के संभावित दीर्घकालिक लाभ आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.0-8.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है।
समग्र रूप से, समष्टि आर्थिक स्थिरता संकेतक दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।



फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक को विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसेट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसेट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

Scan the QR CODE to
download VISION IAS app



DELHI: 5 APR | 1 FEB

LUCKNOW: 12 APR | 9 AM

JAIPUR: 15 FEB

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

अध्याय-1



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. भारत में कृषि क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चावल और गेहूं का उत्पादन क्षेत्र पिछले पांच वर्षों में स्थिर रहा है।
2. खरीफ चक्र के दौरान खाद्यान्न के तहत बोया गया क्षेत्र, रबी चक्र के दौरान बोए गए क्षेत्र से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Q2. औद्योगिक क्षेत्रों के निम्नलिखित घटकों को जी.वी.ए. में उनके भाग के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए?

1. निर्माण
2. विनिर्माण
3. खनन एवं उत्खनन
4. विद्युत और उपयोगिता सेवा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) 1-4-3-2
- (b) 4-3-1-2
- (c) 3-4-1-2
- (d) 4-3-2-1

Q3. निम्नलिखित में से कौन भारत के चालू खाता घाटे को बढ़ा सकता है?

1. वैश्विक पण्य की बढ़ी हुई कीमतें
2. उच्चतर घरेलू मांग
3. प्रेषण में वृद्धि

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 1 और 2

Q4. भारत के बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है।
2. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश के विदेशी ऋण से अधिक है।
3. भारत का भुगतान संतुलन पिछले दो वर्षों से अधिशेष में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 1 और 2

Q5. क्रय प्रबंधक सूचकांक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विनिर्माण और सेवाओं दोनों में व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक है।
2. इसकी गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. पूर्व-महामारी के स्तर के बाद क्षेत्रवार आर्थिक पुनर्बहाली का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

Q2. कोविड-19 महामारी से अनिश्चितताओं का परिवेश उत्पन्न हुआ है, जिससे सुभेद्य वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा महामारी जनित आघातों के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए अपनाई गई रणनीति पर चर्चा कीजिए।

“You are as strong as your Foundation”

FOUNDATION COURSE

GENERAL STUDIES

PRELIMS CUM MAINS 2023

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
- Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2022

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE to download **VISION IAS** app

ONLINE Students

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.

DELHI: 23 MAR, 9 AM | 1 MAR, 9 AM
9 MAR, 1 PM | 11 JAN, 5 PM

LUCKNOW: 9th Feb | **JAIPUR:** 15th Feb | **PUNE:** 7th Mar
HYDERABAD: 15th Feb | **CHANDIGARH:** 15th Feb

अध्याय 2: राजकोषीय घटनाक्रम (Fiscal Developments)

परिचय

- भारत ने महामारी से निपटने के लिए एक कैलिब्रेटेड राजकोषीय नीति व दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थिति के अनुरूप समाज के कमजोर वर्गों /फर्मों को ऊपर उठाने की बात कही गयी थी। भारत सरकार कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक भिन्न चुस्त नीति (agile policy) को अपनाया है। यह नीति वॉटरफॉल रणनीति से भिन्न है। इस तरह के एक समावेशी दृष्टिकोण को अब नीतिगत हलकों में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।
- यह अध्याय महामारी के प्रकोप के बाद भारत में राजकोषीय घटनाक्रम या विकास की समीक्षा करता है। यह अध्याय सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ाने के लिए नीतिगत उपायों पर चर्चा के साथ समाप्त होता है।

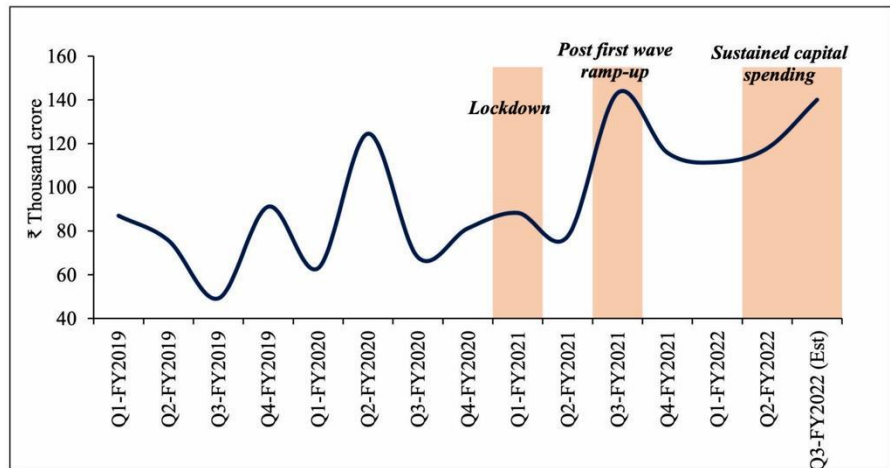
महामारी के बाद राजकोषीय नीति से जुड़ी रणनीति

- महामारी के प्रारंभिक चरण में, राजकोषीय नीति के जरिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे खराब स्थिति के परिणामों से बचाने के लिए सुरक्षा-जाल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके तहत कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, छोटे व्यवसायों को आपातकालीन ऋण जैसे प्रोत्साहन उपायों के द्वारा भरपूर मदद की गयी। आर्थिक गतिविधियों की बहाली के साथ ही राजकोषीय नीति का फोकस उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों²⁰ जैसे निवेश बढ़ाने वाले उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने पर था।
- कंटेनमेंट क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध और ठेकेदारों एवं श्रमिकों की अनिच्छा या काम करने में असमर्थता के कारण, तिमाही पूंजीगत व्यय को वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान रोक दिया गया था। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में आवाजाही और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, पूंजीगत व्यय वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में पूंजीगत व्यय में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा।
 - इसके अलावा 6,835 परियोजनाओं को कवर करने वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार 7,400 परियोजनाओं तक कर दिया गया। 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 13 क्षेत्रों के लिए PLI योजनाएँ शुरू की गई थीं। इन सभी प्रयासों से सामूहिक रूप से रोजगार पैदा होने और मध्यम से लंबी अवधि में गुणक-प्रभावों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करने की नीति चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखी गयी है, क्योंकि पूंजीगत व्यय 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राजकोषीय संकेतकों का प्रदर्शन

- केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा नवंबर 2021 के अंत में बजट अनुमान²¹ का 46.2

Trends in quarterly capital expenditure



Source: CGA Monthly Accounts

Note: The estimate for Q3 FY2021-22 uses flash figures for Dec 2021.

Composition of Taxes in Gross Tax Revenue in 2021-22 BE



²⁰ Production Linked Incentives: PLIs

²¹ Budget Estimate: BE

प्रतिशत था, जो 2020-21 में इसी अवधि के दौरान 135.1 प्रतिशत था।

राजस्व संग्रह

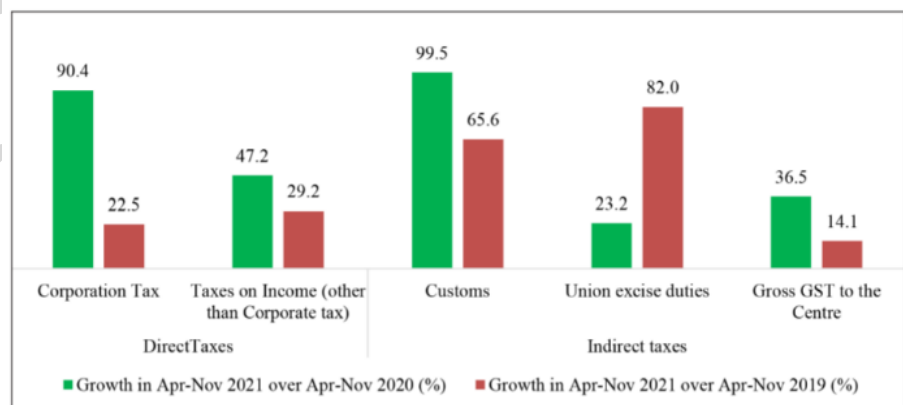
- चालू वित्त वर्ष (अप्रैल से नवंबर 2021) के दौरान पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में बहुत अधिक गति से वृद्धि हुई है। यह प्रदर्शन कर और गैर-कर राजस्व, दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण संभव हुआ है।
- अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान निवल कर राजस्व में अप्रैल से नवंबर 2020 की तुलना में 64.9% की वृद्धि हुई, जो सभी प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों द्वारा दिखाई गई उच्च वृद्धि के कारण है।

संपत्ति मुद्रिकरण (Asset Monetization)

- केंद्रीय बजट 2021-22 ने भी देश में उन्नत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए तीन स्तंभों में से एक के रूप में संपत्ति के मुद्रिकरण पर जोर दिया।
- केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत संपत्ति मुद्रिकरण के लिए जनादेश के आधार पर, बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े मंत्रालयों के परामर्श से नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय मुद्रिकरण पाइपलाइन²² विकसित किया गया है।
 - इसकी परिकल्पना सड़कों, रेलवे, शिपिंग, विमानन, विद्युत, दूरसंचार, तेल और गैस तथा बेयरहाउसिंग क्षेत्रों में विभिन्न ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रिकरण के लिए एक आवश्यक रोडमैप के रूप में की गई है।
- NMP का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक, चार साल की अवधि में केंद्र सरकार के पास मुख्य संपत्ति के माध्यम से 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रिकरण क्षमता होगी।
 - चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) में 0.88 लाख करोड़ रुपये के सांकेतिक मूल्य वाली लगभग 15% संपत्ति की परिकल्पना की गई है।
- NMP के तहत चिन्हित संपत्ति और लेन-देन को कई प्रकार के उपकरणों के माध्यम से शुरू किए जाने की उम्मीद है। इनमें प्रत्यक्ष संविदात्मक साधन जैसे कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी रियायतें और पूंजी बाजार के साधन जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvIT) शामिल हैं।
- जहाँ मूल संपत्तियों का मुद्रिकरण नीति आयोग द्वारा संचालित है, वहीं गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रिकरण की पहल अब तक निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग²³ द्वारा संचालित की गई है।
 - अब तक, CPSEs ने मुद्रिकरण के लिए 3,400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को DIPAM / वित्त मंत्रालय को सौंपित किया है।
- बजट 2021-22 में एक कुशल और विवेकपूर्ण तरीके से भूमि तथा अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रिकरण करने के लिए क्षमता और विशेषज्ञता के साथ प्रचलित सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक विशेष प्रयोजन वाहन²⁴ स्थापित करने की घोषणा की गई है। अतः राष्ट्रीय भूमि मुद्रिकरण निगम (NLMC) को भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपये और अभिदत्त शेयर पूंजी²⁵ 150 करोड़ रुपये है।

- कॉर्पोरेट आयकर में अप्रैल-नवंबर 2020 की तुलना में 90.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि कॉर्पोरेट्स की लाभप्रदता में सुधार, अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण और कर सुधारों के कारण बेहतर अनुपालन की वजह से हुई है।
- अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों ने चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में सालाना आधार पर 38.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

Figure 5: Growth in major direct and indirect taxes during April-November 2021



²² National Monetisation Pipeline: NMP

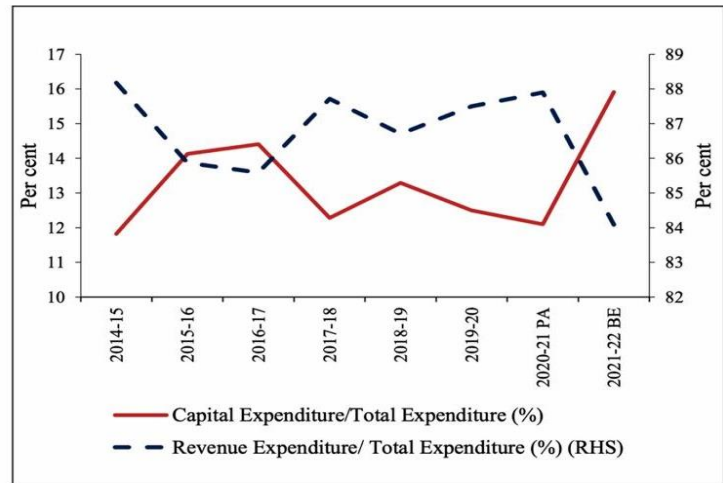
²³ Department of Investment and Public Asset Management: DIPAM

²⁴ Special Purpose Vehicle: SPV

²⁵ subscribed share capital

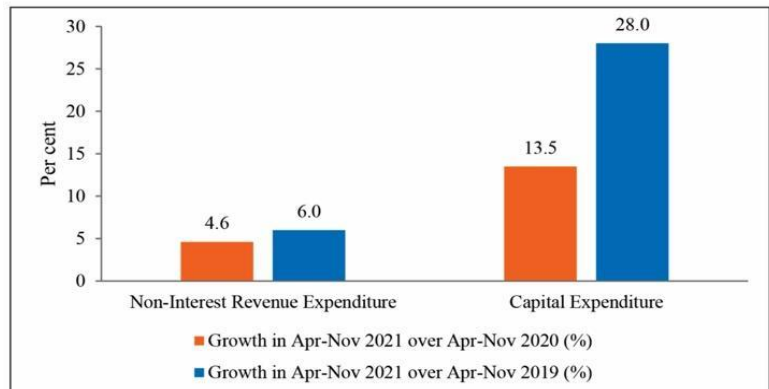
- **सीमा शुल्क से राजस्व संग्रह** में अप्रैल से नवंबर 2020 की तुलना में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
 - सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया था। उस समय कोविड-19 के कारण अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। साथ ही, वैश्विक पेट्रोलियम की कीमतों में कमी ने भी पेट्रोलियम पर कर बढ़ाने का अवसर दिया था।
 - केंद्र और राज्यों को मिलाकर अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान सकल जी.एस.टी. संग्रह अप्रैल से दिसंबर 2020 की तुलना में **61.5 प्रतिशत अधिक** था।
 - पिछले 4 वर्षों में, जी.एस.टी. राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है और मासिक जी.एस.टी. संग्रह का वार्षिक औसत 2017-18 के 0.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 1.19 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
 - जी.एस.टी. संग्रह में यह सुधार महामारी के बाद तेजी से आर्थिक सुधार, जी.एस.टी. चोरी को रोकने और नकली बिलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के कारण हुआ है। इसके अलावा हाल ही में शुरू किए गए प्रणालीगत परिवर्तनों और जी.एस.टी. परिषद द्वारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए किए गए दर युक्तिकरण उपायों के संयुक्त प्रभाव ने भी जी.एस.टी. संग्रह में सुधार किया है।
 - नवंबर 2021 तक गैर-कर राजस्व संग्रह में सालाना आधार पर 79.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि लाभांश और मुनाफे से प्रेरित थी, जिसमें प्रमुख घटक आर.बी.आई. से केंद्र सरकार को 0.99 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष अंतरण था।
 - बजट 2021-22 में इस साल विनिवेश से हुई आय से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की गई थी।
 - 24 जनवरी 2022 तक सरकार विनिवेश से केवल 9,330 करोड़ रुपये जुटा पाई है। सरकार ने नई सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम नीति और संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति²⁶ प्रस्तुत की और एयर इंडिया का निजीकरण किया।
- व्यय**
- सरकार का कुल खर्च अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 8.8 प्रतिशत बढ़ गया और यह बजट अनुमान का 59.6 प्रतिशत रहा।
 - महामारी के मद्देनजर, अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं ने सरकार के राजस्व व्यय में सालाना 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की।
 - 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि प्रमुख सब्सिडी में वृद्धि के कारण हुई।
 - अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान प्रमुख सब्सिडी पर व्यय 2.31 लाख करोड़ रुपये रहा।
 - पूंजीगत व्यय में अप्रैल से नवंबर 2020 की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
 - बजट अनुमान 2021-22 में पूंजीगत व्यय के GDP के 2.5% तक पहुंचने की परिकल्पना की गई है जो 2019-20 में GDP का 1.6% था।

Share of Revenue and Capital Expenditure in Total Expenditure



Source: Union Budget Documents & O/o CGA
BE: Budget Estimate, PA: Provisional Actuals,

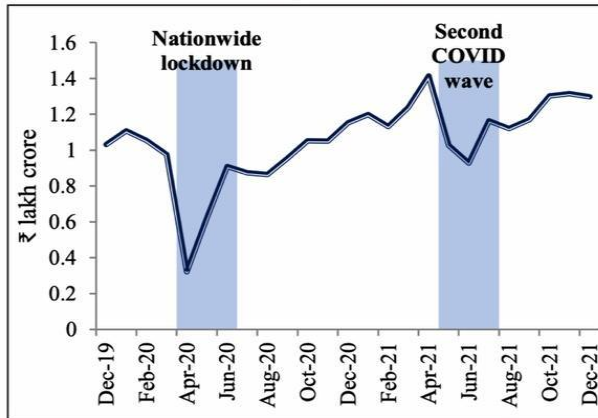
Growth in expenditure components during April to November 2021



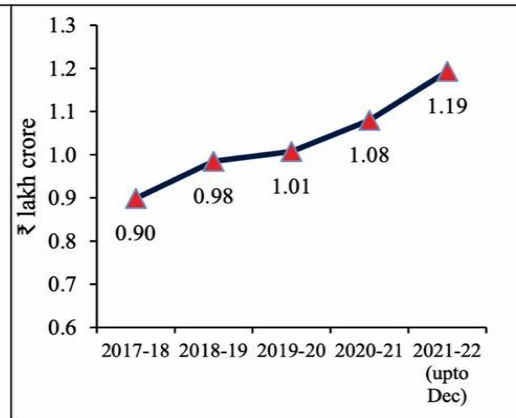
Source: CGA Monthly Accounts

²⁶ New Public Sector Enterprise Policy and Asset Monetisation Strategy

Buoyant GST collections during 2021-22



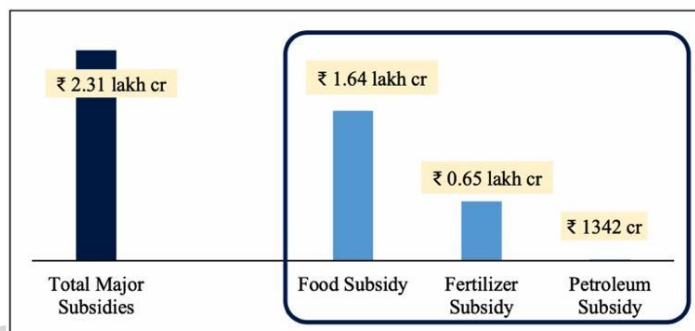
Rising year-average of monthly Gross GST collections



Source: Department of Revenue

- सड़कों और राजमार्गों, रेलवे, आवास जैसे अवसंरचना-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्र ने राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं।

Expenditure on Subsidies during April to November 2021



Source: CGA Monthly Accounts

- एक मजबूत आर्थिक वृद्धि का मार्ग और पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न कर उन्मुख नीतिगत और प्रशासनिक सुधार, मध्यम अवधि में उछाल वाले राजस्व को बनाए रखने में आधारभूत सिद्ध होंगे। इस प्रकार, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीतिगत व्यौरा²⁷ द्वारा राजकोषीय नीति का अनुपालन किया जाएगा।
- सरकार ने 2016-17 से 2020-21 तक 6.04 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय संसाधन²⁸ जुटाया है। इसमें से 1.43 लाख करोड़ रुपये सरकार द्वारा पूरी तरह से सर्विस्ड बॉण्ड्स से जुटाए गए हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फण्ड (NSSF) से ऋण के रूप में 4.61 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

भारत सरकार की विनिवेश नीति का विकास

- संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के पारित होने के साथ, सरकार द्वारा निजी फर्मों का राष्ट्रीयकरण एक मानक नीतिगत उपकरण बन गया। यह अधिनियम किसी भी व्यवसाय में राज्य द्वारा राष्ट्रीयकरण या व्यापार की अनुमति देता है।
 - वायु निगम अधिनियम, 1953²⁹ के तहत, सरकार ने नौ एयरलाइन्स का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद वर्ष 1956 में जीवन बीमा और वर्ष 1972 में सामान्य बीमा व्यवसाय³⁰ का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
 - इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली में, सरकार ने वर्ष 1969 में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के माध्यम से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद वर्ष 1980 में बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर शुरू हुआ। वर्ष 1971-1975 की अवधि के दौरान कोयला खदानों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर भी, राष्ट्रीयकरण का मुद्दा हमेशा एक अत्यधिक बहस का मुद्दा रहा है।
- वर्ष 1991 के सुधारों के बाद, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में सोच में बदलाव आया। वर्ष 1991 के अंतरिम बजट में पहली बार 'विनिवेश' (disinvestment) शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, विनिवेश संबंधी नीति ने तब जोर पकड़ी, जब वर्ष 1999 में एक नया विनिवेश विभाग बनाया गया, जो वर्ष 2001 में एक पूर्ण मंत्रालय बन गया।
 - सार्वजनिक क्षेत्र की 12 कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेची गई, जिनमें मारुति उद्योग, हिंदुस्तान जिंक, इत्यादि शामिल हैं।

²⁷ Medium-Term Fiscal Policy Statement

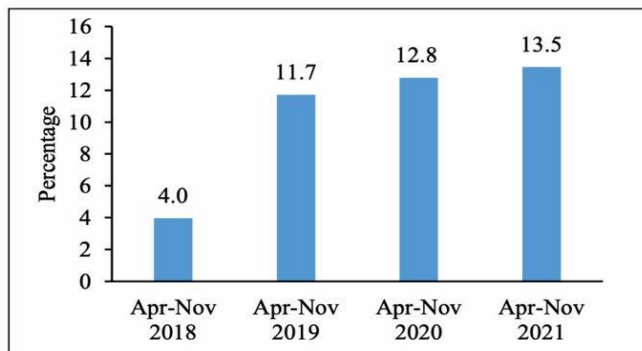
²⁸ Extra Budgetary Resources: EBR

²⁹ Air Corporations Act, 1953

³⁰ General Insurance Business

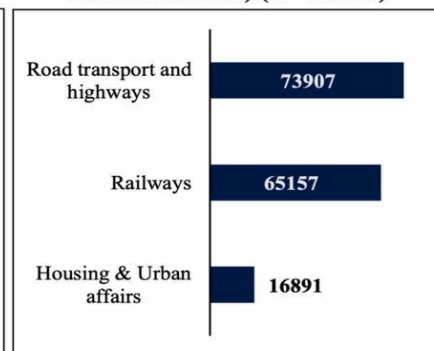
- विनिवेश की प्रक्रिया अगले दशक 2004-2014 तक रुक-रुक कर जारी रही। वर्ष 2014 के बाद, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (REC) जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री के साथ विनिवेश नीति का नवीनीकरण किया गया।
- नए, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को साकार करने के लिए, व्यावसायिक उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को फिर से परिभाषित करने और सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में आत्मनिर्भर भारत के लिए न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (PSE) नीति को 4 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया गया था।
- नई PSE नीति के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित चार व्यापक रणनीतिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; (ii) परिवहन और दूरसंचार; (iii) विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; तथा (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएँ।
- वर्ष 2016 से, सरकार ने 35 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों³¹ और/या सहायक कंपनियों / इकाइयों / CPSEs के संयुक्त उद्यमों और IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है।

YoY growth in Capital Expenditure during April to November over the years



Source: CGA Monthly Accounts

Emphasis sectors for Capital expenditure (April to November 2021) (In ₹ crore)



Source: CGA Monthly Accounts

राज्यों को अंतरण (Transfer to States)

- केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसमें राज्यों को 2,33,233 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान (grants-in-aid) देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा इसमें 2021-22 के दौरान राज्य को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान भी सम्मिलित हैं।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में सामान्य अंतरण के बाद भी 17 राज्यों को 1.18 लाख करोड़ रुपये के कुल राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से 6 जनवरी 2022 तक 98,710 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
- स्थानीय निकायों को अनुदान के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि शहरी क्षेत्रों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जाए:
 - श्रेणी-1 शहर: दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समूह/शहर; और
 - श्रेणी-II शहर: दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को छोड़कर अन्य शहर।

Debt Position of the Central Government (in ₹ lakh crore)

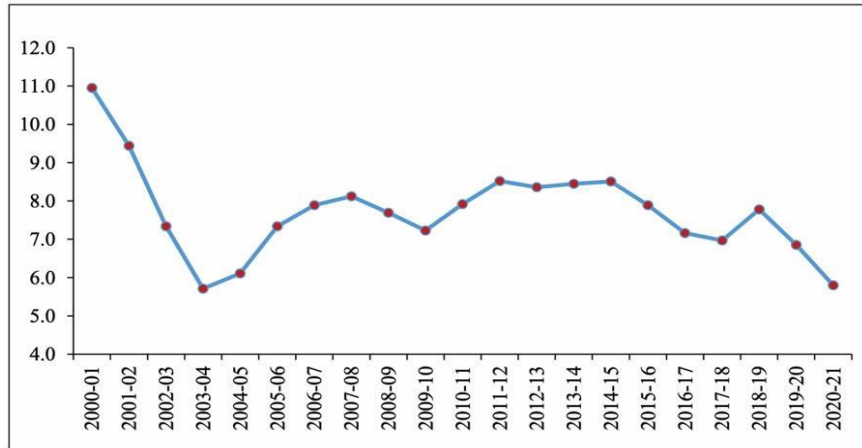
Components	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 PA
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Public Debt (A1+A2)	51.05	57.11	61.50	68.45	75.49	85.65	105.24
A1. Internal Debt (a+b)	47.38	53.05	57.42	64.01	70.75	80.20	99.09
a. Marketable Securities	43.08	47.28	50.49	55.10	59.69	65.60	78.60
b. Non-marketable Securities	4.29	5.77	6.93	8.91	11.06	14.60	20.50
A2. External Debt	3.66	4.07	4.08	4.45	4.74	5.44	6.15
B. Public Account - Other Liabilities	7.62	8.16	8.57	9.15	9.96	13.70	12.74
C. Extra-Budgetary Resources (EBRs)	-	-	0.09	0.24	0.99	1.12	1.43
D. Total Liabilities (A+B+C)	58.66	65.27	70.16	77.85	86.35	99.91	117.04

Source: Union Budget and Finance Accounts (Various Issues); Provisional Accounts, CGA.

³¹ Central Public Sector Enterprises: CPSEs

- आयोग ने सिफारिश की है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (मिलियन प्लस शहरों) को अच्छा प्रदर्शन करने पर 100 प्रतिशत अनुदान मिलियन-प्लस सिटीज चैलेंज फंड³² के माध्यम दिया जाएगा अर्थात् अनुदान प्रदर्शन से जुड़ा होगा।
- आयोग ने सिफारिश की है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों और गैर-मिलियन-प्लस शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का 60 प्रतिशत हिस्सा बुनियादी सेवाओं की दो श्रेणियों को समर्थन और मजबूत करने के लिए दिया जाना चाहिए:
 - स्वच्छता, ODF स्थिति को बरकरार रखने (ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग की प्राप्ति (गैर-मिलियन से अधिक शहरों / श्रेणी-II शहरों / कस्बों के लिए);
 - पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण (ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए)।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए 13,192 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

Weighted average interest rate on Central Government Securities (Per cent)



Source: RBI

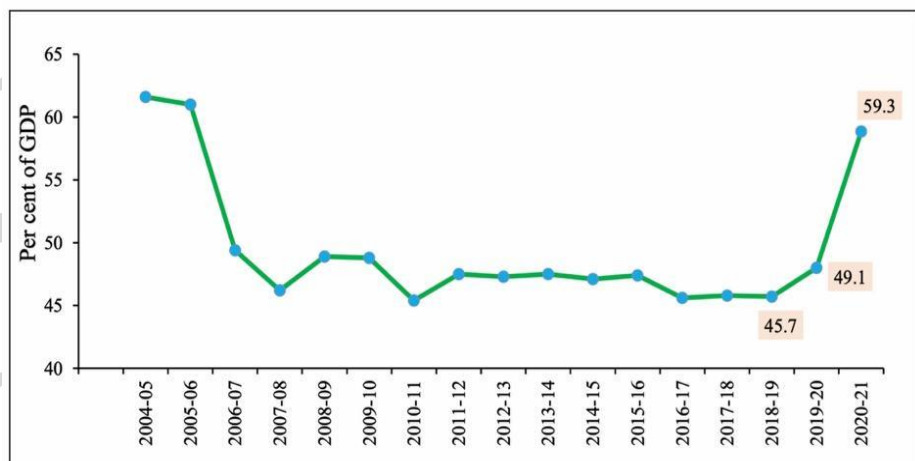
- आपदा प्रबंधन अनुदान के संबंध में आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष³³ को कुल आवंटन का 80 प्रतिशत और राज्य आपदा शमन कोष³⁴ को 20 प्रतिशत मिलना चाहिए।

- इसी तरह, आयोग ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष³⁵ को राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के कुल आवंटन का 80 प्रतिशत मिलना चाहिए और शेष 20 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा शमन कोष³⁶ के लिए मिलना चाहिए।

केंद्र सरकार के ऋण

- वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों पर सरकार की भारित औसत लागत निवल बाजार उधार में 141.2 प्रतिशत की उछाल के बावजूद, 17 साल के निचले स्तर 5.79 प्रतिशत पर थी।
- मार्च 2021 के अंत में केंद्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां 117.04 लाख करोड़ रुपये थी।

Trend in Centre's Debt-GDP ratio



Source: Various issues of Status Paper on Government Debt

Note: The figures for 2020-21 are Provisional

- सार्वजनिक ऋण कुल देनदारियों का 89.9

प्रतिशत था, जबकि सार्वजनिक खाता देयताएं शेष 10.1 प्रतिशत में शामिल हैं।

³² Million-Plus Cities Challenge Fund: MCF

³³ State Disaster Response Fund: SDRF

³⁴ State Disaster Mitigation Fund: SDMF

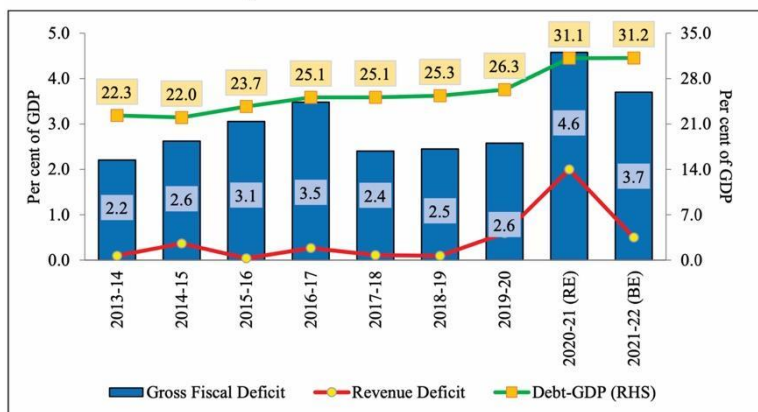
³⁵ National Disaster Response Fund: NDRF

³⁶ National Disaster Mitigation Fund: NDMF

- सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां, जो पिछले एक दशक में अपेक्षाकृत स्थिर थीं, 2020-21 में तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि, आगामी वर्षों में ऋण-GDP अनुपात में गिरावट की संभावना है।
- सार्वजनिक ऋण पोर्टफोलियो बाह्य उधार पर कम निर्भरता और निश्चित कूपन पर अधिकांश प्रतिभूतियों को जारी करने के कारण कम मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।
 - सार्वजनिक ऋण बड़े पैमाने पर बैंकों, बीमा कंपनियों, प्रोविडेंट फंड आदि जैसे संस्थागत क्षेत्रों के स्वामित्व में है। मार्च 2021 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 37.77 प्रतिशत थी।
 - इसके अलावा, अधिकांश बाह्य उधार आधिकारिक स्रोतों से हैं जो दीर्घकालिक और रियायती प्रकृति के हैं। सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता मार्च 2010 के अंत में 9.7 वर्ष थी। यह बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 11.31 वर्ष हो गई है, जिससे रोलओवर जोखिम कम हो गया है।
- RBI द्वारा हाल ही में शुरू की गई खुदरा प्रत्यक्ष योजना³⁷ मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायियों और वरिष्ठ नागरिकों की बचत को सीधे जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में बदलने में सहायक होगी।

- इस योजना के तहत, खुदरा निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट³⁸ खाता खोलने में सक्षम होगा। इसके माध्यम से वह सीधे हरेक प्रतिभूति में न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपये निवेश कर सकता है।
- खुदरा निवेशक सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों जैसे कि ट्रेजरी बिल और बॉण्ड के प्राथमिक निर्गम में एक गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकते हैं। साथ ही, वे RBI की ट्रेडिंग प्रणाली, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग (NDS OM) के माध्यम से द्वितीयक बाजार तक भी पहुंच सकते हैं।

Major deficit and debt indicators of States



Source: RBI State Finances: A Study of Budget; RE: Revised Estimates; BE: Budget Estimates
Note: States include 29 states and 2 Union Territories with legislatures.

राज्य वित्त (State Finances)

- यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2020-21 में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा, उनके सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा को पार कर जाएगा। ज्ञातव्य है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून³⁹ में इसे GDP के 3 प्रतिशत से नीचे रखने का प्रावधान है।
 - राज्यों का राजस्व घाटा भी 2018-19 में GDP के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में GDP का 2 प्रतिशत हो गया।
 - राज्यों की निवल उधार सीमा को बढ़ाकर वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के GSDP⁴⁰ के 5 प्रतिशत और 2021-22 के लिए राज्यों के GSDP के 4 प्रतिशत कर दिया गया था।

Fiscal Indicators of States

Items	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(RE)	2021-22 BE
(in ₹ lakh crore; Numbers in parenthesis are growth rates)						
Own Tax Revenue	9.46 (11.3)	11.3 (19.5)	12.15 (7.5)	12.24 (0.7)	12.41 (1.4)	15.95 (28.5)
Own Non-Tax Revenue	1.7 (14.0)	1.8 (5.3)	2.19 (21.7)	2.61 (19.2)	2.11 (-19.2)	2.87 (36.0)
Revenue Expenditure	21.22 (15.3)	23.4 (10.3)	26.38 (12.7)	27.92 (5.8)	31.86 (14.1)	35.72 (12.1)
Capital Expenditure	5.17 (23.1)	4.31 (-16.6)	4.87 (13.0)	4.6 (-5.5)	5.54 (20.4)	7.23 (30.5)

Source: Source: RBI State Finances: A Study of Budget for 2020-21, RE: Revised Estimates; BE: Budget Estimates;
Note: States also includes 2 UTs (Delhi and Puducherry) from 2017-18

³⁷ Retail Direct Scheme

³⁸ Retail Direct Gilt: RDG

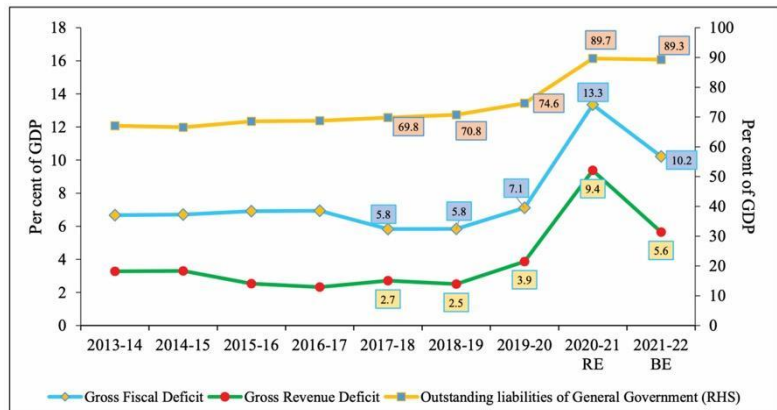
³⁹ Fiscal Responsibility Legislation: FRL

⁴⁰ सकल राज्य घरेलू उत्पाद / Gross State Domestic Product

- राज्यों के लिए निर्धारित निवल उधार सीमा के अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने विद्युत क्षेत्र में राज्यों को GSDP के 0.50 प्रतिशत के प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त उधार की सिफारिश की थी।

- अतिरिक्त उधार का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य बिजली की खपत के लिए भुगतान करने की प्रवृत्ति को निरंतर बढ़ावा देना है।
- राज्य सरकारों के 2021-22 के बजट अनुमानों के अनुसार, राज्यों का अपना स्वयं का कर राजस्व और गैर-कर राजस्व 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः 28.5 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था।
- 2021-22 के बजट अनुमान में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में यह परिकल्पना की गई थी कि ये 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 30.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगे।
- पूंजीगत व्यय के प्रति राज्यों की राजकोषीय नीति के महत्व पर जोर देने के क्रम में केंद्र सरकार ने 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना⁴¹ जारी रखी है।

Trends in General Government Debt and Deficits (as a per cent of GDP)



Source: RBI Handbook of Statistics for Indian Economy;
BE: Budget Estimates; RE: Revised Estimates

सामान्य सरकारी वित्त

- केंद्र और राज्यों द्वारा लिए गए अतिरिक्त उधार के कारण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामान्य सरकारी देनदारियां 2020-21 के दौरान तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि, 2021-22 के बजट अनुमान में, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राजकोषीय संकेतकों में सुधार होने की उम्मीद है और सामान्य सरकार से राजकोषीय समेकन के मार्ग का अनुसरण करने की उम्मीद है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों को समर्थन देने के लिए केंद्र द्वारा किये गए उपाय

- राज्यों के लिए उधार लेने की सीमा में बढ़ोतरी
 - वित्त वर्ष 2020-21: आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, कुछ शर्तों के आधार पर राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GSDP के 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी।
 - इसमें से 0.5 प्रतिशत उधार की पहली किस्त सभी राज्यों के लिए थी।
 - GSDP के 1 प्रतिशत के बराबर उधारी निम्नलिखित चार विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के बाद लिया जाना था। प्रत्येक सुधार का भार GSDP का 0.25 प्रतिशत है। ये हैं:
 - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;
 - ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार;
 - शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता (यूटिलिटी) सुधार; तथा
 - विद्युत क्षेत्र में सुधार।
 - वहीं दूसरी ओर, GSDP का शेष 0.5 प्रतिशत जी.एस.टी. के लागू होने से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए ऑप्शन 1 चुनने वाले राज्यों के लिए था। GSDP का यह 0.5 प्रतिशत पहले ऊपर उल्लिखित 4 सुधारों में से कम-से-कम 3 को पूरा करने से जुड़ा था।
 - वित्त वर्ष 2021-22: वर्ष 2021-22 में राज्यों की निवल उधारी राज्यों के GSDP के 4% पर 8,46,922 करोड़ रुपये पर निर्धारित की गई है। इसका 0.50 प्रतिशत 2021-22 के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया था।
- GST क्षतिपूर्ति या मुआवजे की कमी के एवज में राज्यों को ऋण:
 - राज्यों को भुगतान किए जाने वाले GST क्षतिपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2020-21 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से एक विशेष उधार विंडो के माध्यम से 1,10,208 करोड़ रुपये उधार लिए गए थे।

⁴¹ Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure

- पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure):
 - इसके तहत राज्य सरकारों को वर्ष 2020-21 के दौरान 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 11,830 करोड़ रुपये की विशेष सहायता को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना वर्ष 2021-22 में भी जारी रहेगी तथा इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना के तीन भाग हैं:
 - **भाग-I:** यह 8 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा और दो पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के लिए है। इस भाग के लिए आवंटित राशि 2,600 करोड़ रुपये है।
 - **भाग-II:** यह अन्य सभी राज्यों के लिए है जो भाग-1 में शामिल नहीं हैं। इस भाग के लिए 7,400 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
 - **भाग-III:** यह राज्य सरकारों को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (SPSEs) के निजीकरण / विनिवेश और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण / पुनर्चक्रण के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। इस भाग के तहत राज्यों को स्कीम के भाग-I / भाग-II के तहत उनके आवंटन के अलावा अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। योजना के इस हिस्से के लिए 5,000 करोड़ रुपये रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ाने संबंधी नीतिगत उपाय

- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):** सरकार ने वर्ष 2016 में एक ई-मार्केट की स्थापना की थी जो कुछ मानक दैनिक उपयोग के वस्तुओं के क्रय के लिए समर्पित है। सामान्य वित्तीय नियमावली⁴², 2017 में यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी मंत्रालय और विभाग GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को GeM के माध्यम से ही खरीदेंगे।
- इस ई-मार्केटप्लेस के उपयोग के परिणामस्वरूप पहले की तुलना में कीमतों में काफी कमी आई है। औसत कीमतों में कम-से-कम 15-20% की कमी दर्ज की गई है, जबकि कुछ मामलों में कीमतों में 56% तक की गिरावट दर्ज की गई।

सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधारों के लिए नए दिशा-निर्देश (New guidelines for reforms in Public Procurement and Project Management)

- सरकार गैर-नियमित वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की भी क्रय करती है, जैसे- राजमार्गों व भवनों का निर्माण, सलाहकारों को काम पर रखना आदि। यह GFR, 2017 के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल का उपयोग करके किया जाता है। GFR, 2017 के तहत दिशा-निर्देशों में क्रय की विविध श्रेणियों हेतु बोली लगाने वालों के चयन और मूल्यांकन के लिए तीन तरीके उपलब्ध कराए गए हैं:
 - न्यूनतम लागत प्रणाली (Least Cost System)
 - गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (Quality-cum-Cost Based Selection: QCBS)
 - एकल स्रोत चयन (Single Source Selection: SSS)
- ज्यादातर मामलों में, न्यूनतम लागत प्रणाली का सिद्धांत, जिसे आमतौर पर 'L1' के रूप में जाना जाता है, सबसे प्रचलित है। L1 प्रणाली नियमित कार्यों और गैर-परामर्श सेवाओं की क्रय के लिए अच्छी हो सकती है, किन्तु यह विधि उच्च प्रभाव, जटिल और प्रौद्योगिकी-गहन क्रय के लिए नवाचार, गुणवत्ता, गति और कार्यक्षमता की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है।
 - केंद्रीय सतर्कता आयोग और नीति आयोग सहित विभिन्न संगठनों ने पिछले कई वर्षों में मौजूदा क्रय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता की वकालत की है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल L1 पर निर्भर रहना अच्छी तरह से काम नहीं करता है और "सभी के लिए एक मानक"⁴³ के बजाय "उद्देश्य के लिए उपयुक्त"⁴⁴ दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। गैर-मूल्य विशेषताओं पर विचार करने के लिए 'वैल्यू फॉर मनी' रेटेड मानदंड जैसे विभिन्न विकल्पों को क्रय के तरीकों में शामिल किया जा सकता है।
- पूर्व की क्रय रणनीति की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अक्टूबर 2021 में खरीद और परियोजना प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:

⁴² General Financial Rules: GFR

⁴³ one size fits for all

⁴⁴ fit to purpose

- कार्य और गैर-परामर्श सेवाओं के लिए QCBS की अनुमति है (पहले, केवल परामर्श सेवाओं के लिए अनुमति थी)।
- कार्य और गैर-परामर्श सेवाओं के लिए QCBS के तहत मूल्यांकन / योग्यता और स्कोरिंग मानदंड का निर्धारण: क्रय करने वाली संस्थाओं को अब उन विशिष्टताओं में संशोधन करने की स्वतंत्रता है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। इसके अलावा, बोलीदाता द्वारा समान प्रकृति की पिछली परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वेटेज भी दिया जा सकता है।
- भुगतान करने के लिए निर्धारित समय सीमा: नए दिशा-निर्देश बिल जमा करने के 10 कार्य दिवसों के अंदर 75 प्रतिशत या उससे अधिक के भुगतान को समय पर जारी करने का प्रावधान करते हैं। शेष बिल भुगतान 28 कार्य दिवसों के अंदर अंतिम जाँच के बाद किया जाएगा।
- एकल बोली की अस्वीकृति: एकल बोली को वैध माना जा सकता है बशर्ते कि क्रय को संतोषजनक ढंग से विज्ञापित किया गया हो और बोली लगाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया हो।
- परामर्श सेवाओं के लिए निर्धारित बजट आधारित चयन: इस पद्धति के तहत, परामर्श सेवाओं की लागत को निविदा दस्तावेज में ही नियत बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

शब्दावली	
सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation: GFCF)	इसे 'इन्वेस्टमेंट या निवेश' भी कहा जाता है। इसका आशय उत्पादित संपत्तियों (सेकेंड-हैंड संपत्ति सहित) की खरीद से है। इसमें उत्पादकों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऐसी संपत्ति का उत्पादन भी शामिल है, हालाँकि उसमें से स्थायी पूंजी निपटान को घटा दिया जाता है।
विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDR)	- यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, जिसे IMF द्वारा वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाया गया था। - SDR का मूल्य पांच मुद्राओं- यू.एस. डॉलर, यूरो, चीनी रेंमिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की एक बास्केट पर आधारित है। - SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर कोई वित्तीय दावा है।

अध्याय एक नज़र में
- वर्ष 2020 में महामारी के प्रकोप के चलते जहां अधिकांश अन्य देशों ने अग्रिम आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों की शुरुआत की थी, वहीं भारत सरकार ने कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक भिन्न चुस्त नीति को अपनाया। - चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में उछाल के साथ, अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 67.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बढ़ी हैं। - सरकार द्वारा शुरू की गई नई सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम नीति और संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। - बजट 2021-22 ने न केवल व्यय अनुमानों को बढ़ाया बल्कि उन्हें अधिक उत्पादक पूंजीगत व्यय की ओर भी निर्देशित किया। - कोविड-19 के कारण बढ़ी हुई उधारी के साथ, केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 49.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 59.3 प्रतिशत हो गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें कमी आने की उम्मीद है।

अध्याय-2



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. निम्नलिखित में से कौन-से कर की सकल कर राजस्व 2021-22 में सर्वाधिक हिस्सेदारी थी?

- (a) निगम कर
- (b) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- (c) सीमा शुल्क
- (d) वस्तु और सेवा कर

Q2. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

- 1. एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण
- 2. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम
- 3. भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) 1-3-2
- (b) 2-1-3
- (c) 3-1-2
- (d) 1-2-3

Q3. वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार के ऋण या कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. जी.डी.पी. के अनुपात में केंद्र सरकार की कुल देनदारियों में तेजी से वृद्धि हुई है।
- 2. इस अवधि के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों पर सरकार की भारित औसत लागत में गिरावट आई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Q4. खुदरा प्रत्यक्ष योजना (रिटेल डायरेक्ट स्कीम) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. इस योजना को व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए तैयार किया गया था।
- 2. इस योजना के तहत, खुदरा निवेशक केवल द्वितीयक बाजार में प्रवेश कर सकते हैं।
- 3. इस योजना को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा आरंभ किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 2

Q5. वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों के वित्त के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. राज्यों के ऋण-जी.डी.पी. अनुपात में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- 2. राज्यों की निवल उधार सीमा को बढ़ाकर राज्यों की जी.एस.डी.पी. के 10% तक कर दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

- Q1. विगत दो वर्षों में राजकोषीय नीति भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गिरावट का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण रही है। इस संदर्भ में, कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति का विश्लेषण कीजिए।
- Q2. कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से राज्य के वित्त के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, इस अवधि के दौरान राज्यों को सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए।

अभ्यास 2022

ऑल इंडिया प्रीलिम्स

(GS+CSAT)

मॉक टेस्ट सीरिज

3 टेस्ट | 17 अप्रैल | 1 मई | 15 मई

- भारतीय स्तर की प्रतिशतक संख्या।
- व्यापक रूप से चैकिंग, फीडबैक, और संशोधन की युक्तियाँ।
- हिन्दी | English में उपलब्ध।

ऑफलाइन* मोड
100+ शहरों में

***सरकार के नियमों और छात्रों की सुरक्षा के अधीन**

पंजीकरण करें
www.visionias.in/abhyaas

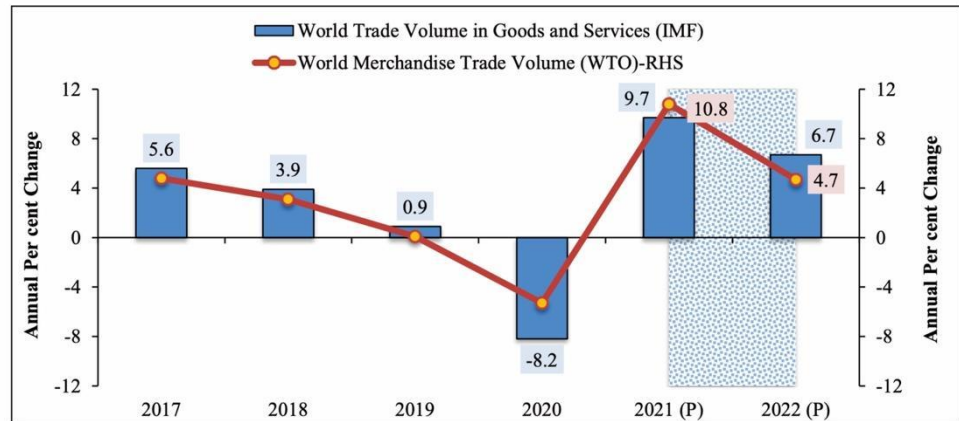
AGARTALA | AGRA | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | AURANGABAD | BAREILLY | BENGALURU | BHAGALPUR | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR | COIMBATORE | CUTTACK | DEHRADUN | DELHI MUKHERJEE NAGAR | DELHI RAJINDER NAGAR | DHANBAD | DHARWAR | DIBRUGARH | FARIDABAD | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GREATER NOIDA | GUNTUR | GURUGRAM | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU JAMSHEDPUR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KANPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLKATTA | KOTA | KOZHIODE (CALICUT) | KURNOOL | KURUKSHETRA | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MORADABAD | MUMBAI | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NASIK | NAVI MUMBAI | NOIDA | ORAI | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUNE | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | ROHTAK | ROORKEE | SAMBALPUR | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THIRUVANANTHAPURAM | TIRUCHIRAPALLI | UDAIPUR | VADODARA | VARANASI | VIJAYAWADA | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

अध्याय 3: वैदेशिक क्षेत्र (External Sector)

परिचय

पिछले वर्ष की महामारी जनित मंदी के बाद वर्ष 2021-22 में विदेशी व्यापार में मजबूती से सुधार हुआ है। इसके कारण मजबूत पूंजी अंतर्वाह से विदेशी मुद्रा भंडार में भी तीव्र वृद्धि हुई है। हालांकि, वर्ष 2022-23 के दौरान, कोविड-19 के नए संक्रामक रूपों के कारण वैश्विक तरलता उपलब्धता में बाधा, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर अस्थिरता, और माल ढुलाई की उच्च लागत, भारत के लिए चुनौती सिद्ध हो सकती है।

Projection for World Trade Volume Growth



Source: IMF and WTO

Note: Projections. The shaded area represents projected growth.

वैश्विक आर्थिक परिवेश

- कैलेंडर वर्ष 2021 की पहली छमाही (H1) में वैश्विक आर्थिक गतिविधि में तेजी देखी गई, जिसने पण्य या वस्तु व्यापार को अपने महामारी-पूर्व के सर्वोच्च स्तर से भी ऊपर उठा दिया। इसे दर्शाते हुए, वर्ष 2021 में

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि का अनुमान लगाया। विश्व व्यापार संगठन ने अपनी अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट में, वर्ष 2021 में वैश्विक पण्य व्यापार की मात्रा में वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 10.8 प्रतिशत कर दिया।

- वर्ष 2021 की पहली दो तिमाहियों के दौरान विकास दर में तेजी देखी गई। डेल्टा वेरिएंट के तीव्र प्रसार और नए वेरिएंट के खतरों के कारण विकास दर तीसरी तिमाही (Q3) से फिर से कमजोर हो गयी। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण कड़ियाँ टूट गयीं, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षा से अधिक समय तक आपूर्ति बाधित हुई। इस प्रकार कोविड-19 से उबरने के वैश्विक प्रयासों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- मूल्य के संदर्भ में अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं के व्यापार पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न प्रभाव दिखता है। प्राकृतिक गैस की कीमतों में चार गुना वृद्धि से ईंधन और खनन उत्पादों के व्यापार-मूल्य में वृद्धि हुई। विनिर्मित वस्तुओं में, कुछ क्षेत्रों ने वर्ष-दर-वर्ष मजबूत वृद्धि दिखाई, जिसमें लौह और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक घटक और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। हालांकि, अन्य वस्तुओं जैसे मोटर वाहन उत्पाद और दूरसंचार के उपकरणों ने अर्धचालकों (सेमीकंडक्टर्स) की हालिया कमी के कारण ठहराव या गिरावट दर्शाई है।
- वर्ष 2021 में, वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में तेजी आई, क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के साथ ही आर्थिक गतिविधियाँ फिर से शुरू हुईं। इन गतिविधियों को वैश्विक तरलता या चलनिधि उपलब्धता में बाधा और वैश्विक मुद्रा में विनिमय दर की अस्थिरता, दोनों से खतरा है।
- वैश्विक व्यापार के लिए अन्य जोखिमों में बंदरगाहों पर विलंब, माल ढुलाई की उच्च दर, शिपिंग कंटेनरों की कमी, अर्धचालक जैसे इनपुट की कमी आदि शामिल हैं।
- भारत के वैदेशिक क्षेत्र या बाह्य क्षेत्रक ने वर्ष के दौरान अत्यधिक लचीलापन दिखाया है। यह अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुद्धार के लिए शुभ संकेत है।

भारत के पण्य व्यापार की प्रवृत्ति (Developments in India's Merchandise Trade)

पण्य निर्यात (Merchandise Export)

- वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, पण्य निर्यात में 49.7 प्रतिशत हुई और यह बढ़कर 301.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, जो महामारी से पहले के स्तर से भी अधिक था।

- प्रमुख बाजारों में तेज रिकवरी; उपभोक्ता खर्च में वृद्धि; प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा के कारण बचत और डिस्पोजेबल या प्रयोज्य आय में वृद्धि; वैश्विक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और सरकार द्वारा एक आक्रामक निर्यात नीति ने 2021-22 में निर्यात को बढ़ावा दिया है।

- पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक⁴⁵ निर्यात (कुल निर्यात का लगभग 15 प्रतिशत) के साथ-साथ गैर-POL निर्यात में उच्च वृद्धि ने निर्यात-वृद्धि में योगदान दिया है। यह विस्तार की व्यापक-आधार वाली प्रकृति को दर्शाता है। वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान गैर-POL निर्यात

257.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

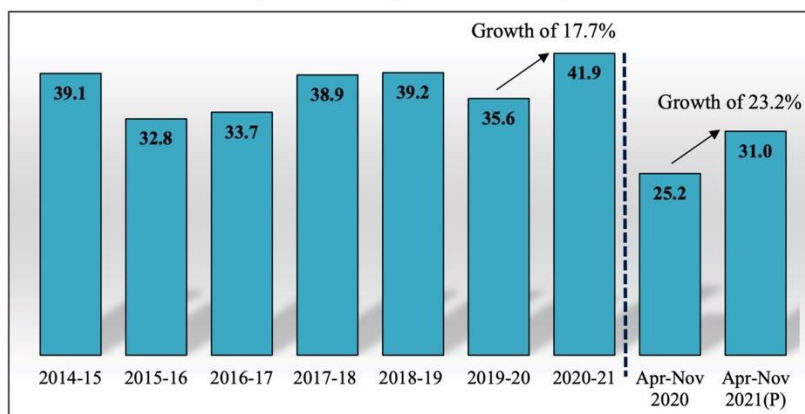
- निर्यात निरीक्षण परिषद⁴⁶ तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण⁴⁷ जैसी सक्रिय सहायता एजेंसियां कार्यरत हैं। निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी करने, परिवहन और विपणन सहायता के तहत सहयोग राशि की बड़ी हुई दरों तथा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए अगस्त 2020 में आरम्भ की गई कृषि उड़ान (उड़ें देश का आम नागरिक) योजना जैसे उपायों से कृषि निर्यात के विकास में सहायता मिली है।

- चालू वित्त वर्ष के दौरान समुद्री उत्पादों, भैंस के मांस, चाय, कॉफी और डेयरी उत्पादों जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। यह आने वाले वर्षों में कृषि निर्यात के और अधिक विविधीकरण और सुदृढीकरण के लिए शुभ संकेत है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल-नवंबर, 2021 में शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और चीन का स्थान रहा। मलेशिया की जगह बेल्जियम ने भारत के शीर्ष दस प्रमुख निर्यात गंतव्यों में प्रवेश किया।

- भारत के निर्यात का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अब भी केवल सात देशों पर निर्भर है।

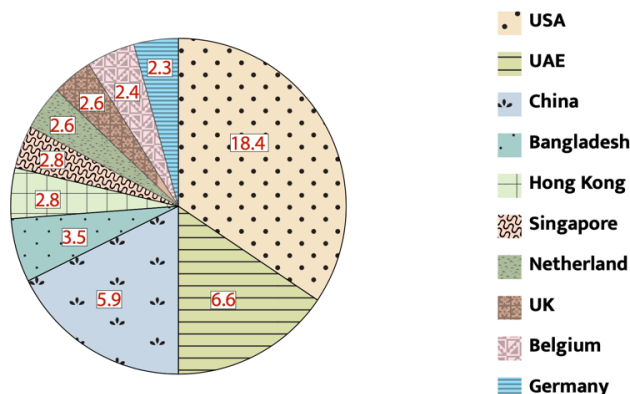
Agricultural Exports (US\$ Billion)



Source: Department of Commerce

Note: P: Provisional

Top ten Export Destinations in 2021-22 (April-November) | By Share in Per cent



Export commodities		
commodity	US\$Billion (2021-22(P))	Share in Percent
Petroleum products	39.5	14.9
Pearl, precious, semiprecious stones	18.1	6.8
Iron and steel	15.9	6
Drug Formulations, Biological	12.4	4.7
Gold and other precious metal jewellery	7.6	2.8

Import commodities		
commodity	US\$Billion (2021-22(P))	Share in Percent
Petroleum crude	73.3	19.2
Gold	33.2	8.7
Petroleum Products	24.1	6.3
Pearl, Precious, Semiprecious Stones	19.2	5.0
Coal, Coke and Briquettes, etc.	18.9	4.9

⁴⁵ Petroleum, Oil and Lubricants: POL

⁴⁶ Export Inspection Council: EIC

⁴⁷ Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority: APEDA

व्यापार समझौतों पर प्रगति (Progress on Trade Agreements)

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत ने अपनी व्यापार समझौता वार्ता शुरू की है और कई देशों के साथ मौजूदा समझौतों की समीक्षा की है। इस व्यापार वार्ता में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता⁴⁸, यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA), कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता⁴⁹ शामिल हैं। भारत अपने मौजूदा व्यापार समझौतों, जैसे कि सिंगापुर और आसियान आदि के साथ CECA की समीक्षा कर रहा है।
- भारत ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ जनवरी, 2022 में यू.के. के साथ FTA वार्ता शुरू की।
- भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (मंत्रिस्तरीय) के तहत, सामाजिक सुरक्षा समझौते, नर्सिंग सेवाओं और लेखा सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौते⁵⁰ और भारतीय पेशेवरों के आवागमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं और पहल

- निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना⁵¹:** यह WTO के अनुरूप एवं विश्व स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित योजना है। इस सिद्धांत के अनुसार, निर्यात पर करों और प्रशुल्कों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस नई योजना के तहत निर्यात किए गए उत्पादों के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया में आरोपित एवं रिफंड नहीं किए गए केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति या वापसी की जाती है। इन शुल्कों में विद्युत शुल्क, परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (वैट) आदि शामिल हैं।
- जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करना:** इस पहल के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में जिला निर्यात संवर्धन समिति⁵² स्थापित की गई है। देश भर के सभी 739 जिलों में संभावित निर्यात क्षमता वाले उत्पादों (कृषि, GI टैग किए गए उत्पाद) से संबंधित क्षेत्र और खिलौना क्लस्टर से संबंधित क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive: PLI) योजना:** इस योजना से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (CoO):** कोविड-19 संकट को देखते हुए, भौतिक संपर्क से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति देने के लिए यह पहल आरंभ की गयी है।
- एक्जिम बैंक में पूंजी का प्रवाह:** चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) में 750 करोड़ रुपये की पूंजी डाली गई है।
- भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ECGC):** यह निर्यात उधारकर्ताओं को निर्यात ऋण देने में शामिल जोखिमों के विरुद्ध बैंकों को बीमा कवर प्रदान करता है। ECGC लिमिटेड के लिए पांच वर्ष की अवधि में 4,400 करोड़ रुपये के पूंजी प्रवाह को मंजूरी दी गई थी। इसके चलते यह अगले पांच वर्ष की अवधि में 5.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निर्यात का समर्थन करेगा।
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु⁵³ योजना:** इस योजना के तहत मशीनरी और पुर्जों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गयी है, लेकिन शर्त यह कि एक फर्म निर्धारित समय के भीतर एक निर्दिष्ट मात्रा का निर्यात करेगी। अब स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद बढ़ाने के लिए, सरकार ने विशिष्ट निर्यात दायित्वों को 90 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया है।
- अन्य योजनाओं में शामिल हैं,** निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES), बाजार पहुंच पहल (MAI), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) और अग्रिम अनुमोदन योजना।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक दक्ष लॉजिस्टिक्स प्रणाली को सक्षम करना

- “डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन” पर UNESCAP⁵⁴ के नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को वर्ष 2021 में 90.3 प्रतिशत

⁴⁸ Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA

⁴⁹ Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA

⁵⁰ Mutual Recognition Agreements: MRA

⁵¹ Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP

⁵² District Export Promotion Committees: DEPCs

⁵³ Export Promotion Capital Goods: EPCG

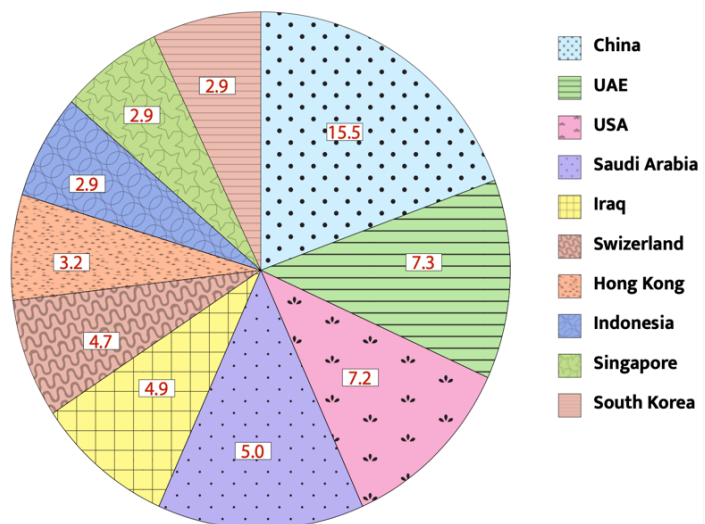
अंक प्राप्त हुए। वर्ष 2019 में 78.5 प्रतिशत अंकों की तुलना में यह उछाल पांच प्रमुख संकेतकों के स्कोर में सुधार के कारण हुआ है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।

- पारदर्शिता सूचकांक को वर्ष 2021 में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, जबकि कागज रहित व्यापार और औपचारिकताओं को 96 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए।
- प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP): इसका उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही हेतु बुनियादी ढांचे को समग्र रूप से एकीकृत करना है।
 - यह बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।
 - यह इसरो इमेजरी के साथ स्थानिक योजना उपकरणों (spatial planning tools) सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे।
- लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए उठाए गए अन्य कदम हैं: फास्टैग (FASTag), तुरंत कस्टम्स, सभी आयात-निर्यात कंटेनरों में अनिवार्य रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग (RFID), ई-संचित, इंडियन कस्टम्स ट्रेड असिस्टेंस इन्कार्री फॉर ट्रेड असिस्टेंस एंड नॉलेज (ICETRAK), इंडियन कस्टम्स EDI डैशबोर्ड (ICEDASH), सिक्वोर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज (SLDE), इम्पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम, जी.एच.जी. कैलकुलेटर आदि।
- समुद्री व्यापार को आसान बनाने के लिए बंदरगाह-विशिष्ट मास्टर प्लान के विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए एक समन्वय तंत्र भी तैयार किया जा रहा है जिसमें चुनिंदा भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) का एकीकृत जांच चौकियों (ICP) में उन्नयन, मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों को बढ़ावा देना आदि सम्मिलित होगा।

पण्य या वस्तु आयात (Merchandise Imports)

- अप्रैल-दिसंबर, 2021 में वस्तु आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 68.9 प्रतिशत बढ़कर 443.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का हो गया।
 - कच्चे पेट्रोलियम का आयात पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-नवंबर, 2021 में दोगुना से अधिक बढ़कर 73.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह सबसे अधिक आयातित वस्तु बना हुआ है।
- आयात के स्रोत के शीर्ष दस देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल-नवंबर, 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत थे। इसमें चीन की हिस्सेदारी एक वर्ष पहले की इसी अवधि में 17.7 प्रतिशत से घटकर 15.5 प्रतिशत हो गई। इंडोनेशिया, जो कि कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, भारत के शीर्ष दस आपूर्तिकर्ताओं में से एक बना हुआ है।

Top ten Import Sources in 2021-22 (April-November) | By Share in Per cent



वस्तु (पण्य) व्यापार संतुलन (Merchandise Trade Balance)

- वस्तु व्यापार घाटा अप्रैल-दिसंबर, 2021 में 142.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह घाटा 61.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

54 एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग / United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

- भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। इसके बाद बांग्लादेश और नेपाल का स्थान था।

सेवा व्यापार (Trade in Services)

सेवा निर्यात

- वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भारत का सेवा निर्यात 18.4 प्रतिशत बढ़कर 177.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष की इसी अवधि की तुलना में महामारी-पूर्व स्तरों को पार कर गया।
- शीर्ष तीन क्षेत्रों- कंप्यूटर, व्यवसाय और परिवहन सेवाओं का कुल सेवा निर्यात में 80% से अधिक हिस्सा है।

सेवा आयात

- वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में सेवा आयात 21.5 प्रतिशत बढ़कर 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष की इसी अवधि से पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया।
- व्यापार, परिवहन, यात्रा और कंप्यूटर सेवाओं के लिए भुगतान, कुल मिलाकर सेवाओं के आयात का 75% से अधिक है।

निजी अंतरण (Private Transfers)

- वित्त वर्ष 2021-22 की प्रथम छमाही में, निवल निजी अंतरण - जो मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषण (रेमिटेंस) को दर्शाता है, एक वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.2 प्रतिशत बढ़कर 38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह पूर्व-महामारी के स्तर से अधिक था।
- भारत वर्ष 2021 में विश्व में सबसे बड़ा विप्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है (वर्तमान अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) और वर्ष 2008 से ऐसी ही स्थिति रही है।

अदृश्य मदें (Invisibles)

- निवल अदृश्य मदों का मूल्य पिछले वर्ष के 60.1 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में 72.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। यह मूल्य कोविड-पूर्व स्तरों को पार कर गया था।

चालू खाता शेष (Current Account Balance)

- वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली छमाही में अधिशेष दर्शाने के बाद, भारत का चालू खाता शेष वित्त वर्ष 2021-2022 की पहली छमाही में 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे में चला गया। चालू खाता शेष वित्त वर्ष 2021-2022 की पहली तिमाही में अधिशेष से दूसरी तिमाही में घाटे में बदल गया।

पूंजी खाता / वित्तीय खाता (Capital Account/ Financial Account)

- वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, निवल पूंजी प्रवाह तीन गुना से अधिक अर्थात् 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जी.डी.पी. का 4.5 प्रतिशत) हो गया। यह विदेशी निवेश की आमद, मुख्य रूप से बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) वाले ऋणों में वृद्धि और बैंकिंग पूंजी और अन्य पूंजी (IMF द्वारा 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के SDR आवंटन सहित) के कारण हुआ।

India's Merchandise Trade Balance with Major Countries

(US\$ Billion)							
S. No	Country	Exports		Imports		Trade Balance	
		Apr-Nov 20	Apr-Nov 21 (P)	Apr-Nov 20	Apr-Nov 21 (P)	Apr-Nov 20	Apr-Nov 21 (P)
1	USA	31.3	49.0	16.3	27.4	15.0	21.6
2	Bangladesh	5.1	9.2	0.6	1.3	4.4	7.9
3	Nepal	3.5	6.0	0.4	1.0	3.1	5.0
4	Turkey	2.3	5.1	0.9	1.3	1.4	3.8
5	Netherland	3.8	6.9	1.9	2.8	1.9	4.1
6	U K	4.6	6.8	2.6	4.3	2.0	2.5
7	Italy	2.6	5.4	2.2	3.2	0.4	2.1
8	Korea	2.9	4.8	7.1	11.1	-4.2	-6.3
9	Qatar	0.8	1.2	4.6	7.7	-3.8	-6.5
10	U A E	9.7	17.5	13.1	27.9	-3.4	-10.4
11	Saudi Arab	3.6	5.8	9.2	19.2	-5.6	-13.4
12	Iraq	1.0	1.3	7.6	18.5	-6.6	-17.2
13	Switzerland	0.9	0.9	5.8	17.8	-4.9	-16.9
14	China	13.6	15.6	38.8	59.0	-25.2	-43.4

Source: Department of Commerce
Note: P: Provisional

- वित्त वर्ष 2021-22 की दोनों तिमाहियों में निवल पूंजी प्रवाह अस्थिर रहा, फिर भी वर्ष-दर-वर्ष और क्रमिक आधार पर वृद्धि देखी गई।
- विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश⁵⁵ शामिल हैं, पूंजी खाते का सबसे बड़ा घटक है।

Top Investing countries FDI Equity Inflows					
Rank	Country	USD Billion		Share (in percent)	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	Singapore	14.7	17.4	29.4	25.9
2	U.S.A	4.2	13.8	8.4	14.9
3	Mauritius	8.2	5.6	16.5	13.9
4	Netherlands	6.5	2.8	13.0	6.9
5	Japan	3.2	2.0	6.5	2.6
	Sum of Above	36.9	41.6	73.8	64.1
	All Countries*	50.0	59.6	100	100

- पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान निवल FDI में 24.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कम अंतर्वाह दर्ज किया गया और सकल FDI अंतर्वाह कम होकर 54.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
 - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र ने अप्रैल-सितंबर, 2021 में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया।
 - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह के मामले में सिंगापुर शीर्ष निवेशक देश बना हुआ है जबकि यू.एस.ए. दूसरे स्थान पर है।
- अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए वेरिएंट के डर और मजबूत मुद्रास्फीति दबाव से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण FPI प्रवाह अस्थिर रहा।
- बैंकिंग पूंजी ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 9.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

Sectors attracting highest FDI Equity inflows			
Rank	Country	Share (in percent)	
		2019-20	2020-21
1	Computer software & Hardware	15.4	43.8
2	Automobile Industry	5.7	2.7
3	Services Sector**	15.7	8.5
4	Trading	9.2	4.4
5	Telecommunications	8.9	07
	Total of above	58.8	60.1
	Total FDI	100	100

भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भंडार (BoP Balance and Foreign Exchange Reserves)

- भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 63.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान संतुलन (BoP) अधिशेष दर्ज किया। इससे 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की उपलब्धि प्राप्त हुई। सितंबर 2021 के अंत तक यह 635.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- हालांकि, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर दिसंबर 2021 के अंत में घटकर 13.2 महीने के बराबर हो गया, जो मार्च 2021 के अंत में 17.4 महीने था, क्योंकि घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ व्यापारिक वस्तुओं का आयात बढ़ गया था।

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव (Movement in Exchange Rate)

- वर्ष 2020-21 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 4.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई। हालांकि, रुपये का मूल्यहास (depreciation) उदीयमान बाजारों जैसे कि तुर्की (की लीरा), अर्जेंटीना (की पेसो) की तुलना में मामूली था। यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले रुपया मजबूत (मूल्यवृद्धि) हुआ।
- 6-मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर⁵⁶ (व्यापार-भारित) के संदर्भ में, रुपये में मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में 2.1 प्रतिशत की गिरावट (मूल्यहास) आई, जबकि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर⁵⁷ के संदर्भ में इसमें 0.9 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई।

⁵⁵ Foreign Portfolio Investment: FPI

⁵⁶ Nominal Effective Exchange Rate: NEER

निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति

- सितंबर 2021 के अंत तक भारत की निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति सकल घरेलू उत्पाद का (-) 11.3 प्रतिशत (-332 बिलियन यू.एस. डॉलर) थी। यह मार्च 2019 के अंत से एक निरंतर सुधार दर्शाती है। यह एक उच्च परिसंपत्ति-देयता अनुपात का परिणाम है। इस अनुपात में मार्च 2021 के अंत से सितंबर 2021 के अंत तक 73.6 प्रतिशत का सुधार हुआ।

विदेशी कर्ज (External Debt)

- सितंबर 2021 के अंत में भारत का विदेशी ऋण, 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित था, जो जून 2021 के अंत के स्तर से 22.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (3.9 प्रतिशत) अधिक है।
 - विदेशी ऋण में वाणिज्यिक उधार सबसे बड़ा घटक था और यह 218.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके बाद क्रमशः NRI जमा, अल्पकालिक व्यापार ऋण था।
- अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग का ऋण भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा। सितंबर 2021 के अंत में इसकी 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, इसके बाद भारतीय रुपया का स्थान था।
 - भारतीय रुपये मूल्यवर्ग के विदेशी ऋण में पिछले कुछ वर्षों में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है।
- डेट सर्विस या ऋण सेवा (अर्थात, मूलधन की चुकौती और ब्याज भुगतान) सितंबर 2021 के अंत में कम होकर वर्तमान प्राप्ति के 4.7 प्रतिशत पर पहुँच गई, जबकि मार्च 2021 के अंत में यह 8.2 प्रतिशत थी।
- कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा सितंबर 2021 के अंत में मामूली रूप से गिरकर 17.0 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2021 के अंत में 17.7 प्रतिशत था।
- मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से, भारत का विदेशी ऋण उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्था के लिए इष्टतम होने के अनुमान से नीचे बना हुआ है, जबकि हाल के वर्षों में विभिन्न बाहरी क्षेत्र भेद्यता का आकलन करने वाले संकेतकों में सुधार हुआ है।

External Debt Outstanding				
USD Billion (Percentage change)				
		March-21 PR	June-21 PR	Sep.-21 P
1	Multilateral	69.7 (2.5)	70.2 (0.6)	71.4 (1.7)
2	Bilateral	30.9 (1.3)	30.8 (-0.5)	30.9 (0.5)
3	International Monetary Fund	5.6 (-1.6)	5.7 (0.6)	23.3 (310.8)
4	Trade Credit	6.3 (-3.1)	5.7 (-8.8)	5.6 (-1.7)
5	Commercial Borrowings	213.1 (2.5)	213.4 (0.4)	218.8 (2.5)
6	NRI Deposits (above one-year)	141.9 (1.0)	141.5 (-0.3)	141.6 (0.0)
7	Rupee Debt	1.0 (-2.2)	1.0 (-0.8)	1.0 (-1.6)
8	Total long-Term Debt (1 to 7)	468.5 (1.8)	468.3 (-0.1)	492.5 (5.2)
9	Short term Debt	101.1 (-2.4)	102.5 (1.4)	100.6 (-1.9)
9a	Trade related Credits	97.3 (-2.4)	99.2 (2.0)	97.4 (-1.8)
	Total (8+9)	569.6 (1.0)	570.8 (0.2)	593.1 (3.9)

शब्दावली	
निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति	यह एक अर्थव्यवस्था के निवासियों की वित्तीय संपत्ति जो अनिवासियों पर बकाया है और अनिवासियों की वित्तीय संपत्ति जो एक अर्थव्यवस्था के निवासियों पर बकाया है, के बीच का अंतर है। दूसरे शब्दों में, निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश, किसी देश की बाहरी वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर है। यह शेष विश्व के समक्ष किसी देश के निवल बकाया या निवल देयता का को दर्शाता है।
हेडलाइन मुद्रास्फीति	हेडलाइन मुद्रास्फीति बास्केट सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक प्रासंगिक है।
कोर मुद्रास्फीति	कोर मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन वस्तुओं को हेडलाइन मुद्रास्फीति से बाहर करके आंकी जाती है। चूंकि ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और मुद्रास्फीति की गणना में अस्थिरता पैदा होती है, इसलिए कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में कम अस्थिर होती है।

अध्याय एक नज़र में

- पिछले वर्ष की महामारी जनित मंदी के बाद, वर्ष 2021-22 में विदेशी व्यापार में मजबूती से सुधार हुआ। भारत में मजबूत पूंजी अंतर्वाह के साथ, विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई।
- घरेलू गतिविधि में सुधार के साथ वैश्विक मांग में सुधार के कारण, भारत के वस्तु निर्यात और आयात में मजबूत उछाल देखा गया और चालू वित्त वर्ष के दौरान ये कोविड-पूर्व स्तरों को पार कर गए।
- भारत का बाहरी क्षेत्र प्रणालीगत रूप से अमेरिकी फेडरल रिज़र्व सहित महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के तेजी से मानकीकरण की संभावना से उत्पन्न होने वाली वैश्विक तरलता के किसी भी अवांछित मुद्रास्फीति दबाव को सहने में सक्षम है।

अध्याय-3**स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण**

Q1. भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- पिछले पांच वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में लगातार गिरावट आयी है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान यू.एस.ए. शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

Q2. डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण को प्रत्येक दो वर्षों में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है?

- विश्व बैंक
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- विश्व व्यापार संगठन
- एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी.)

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएँ हैं?

- लौह और इस्पात
- वनस्पति तेल
- समुद्री उत्पाद
- प्लास्टिक कच्चा माल

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 4
- केवल 3 और 4
- केवल 1 और 4

Q4. निम्नलिखित में से कौन भारत के पूंजी खाता शेष को प्रभावित कर सकता है?

- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों में वृद्धि
- कोविड महामारी के कारण प्रेषण में गिरावट
- भारत को एस.डी.आर. आवंटन में वृद्धि

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

Q5. भारत के विदेशी ऋण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- एन.आर.आई. जमा विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक है।
- 90% से अधिक ऋण अमेरिकी डॉलर में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

- Q1.** विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महामारी से संबंधित प्रोत्साहन कार्यक्रम ने टेपर टेंड्रम की कुछ आशंकाओं को फिर से उत्पन्न कर दिया है, हालांकि भारत का बाह्य क्षेत्र ऐसे बाहरी आघातों के प्रति लोचशील है। चर्चा कीजिए।
- Q2.** निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लोचशील संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम) महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, भारतीय निर्यात में संभार तंत्र द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित कीजिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा 2021

15
फरवरी

प्रोग्राम की विशेषताएँ

- ★ Vision IAS के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ DAF विश्लेषण सेशन
- ★ पूर्व-प्रशासनिक अधिकारियों/शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन
- ★ विगत वर्षों के टॉपर्स तथा वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद
- ★ प्रदर्शन मूल्यांकन एवं प्रतिक्रिया
- ★ मॉक इंटरव्यू सेशन की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवायी जाएगी



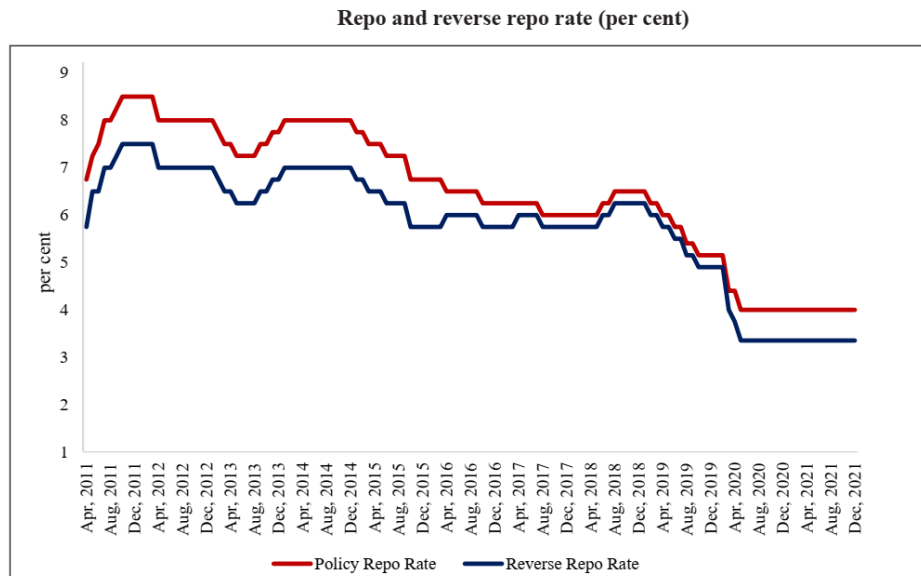
अध्याय 4: मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता (Monetary Management and Fiscal Intermediation)

परिचय

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से, मौद्रिक नीति और तरलता या चलनिधि परिचालनों (liquidity operations) ने अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 2021-22 में मौद्रिक दशाओं में ढील देना जारी है। इसके साथ ही, सामान्य तरलता परिचालन को चरणबद्ध ढंग से दोबारा किया जा रहा है। RBI के कुछ पहले के चलनिधि उपाय पूर्व-निर्धारित समापन तिथियों के निकट पहुंच गए हैं, लेकिन 2021-22 में चलनिधि की स्थिति अधिशेष में बनी रही।

मौद्रिक विकास

- **रेपो रेट:** मई 2020 से, मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो रेट को 4% पर यथावत बनाए रखी है।
 - इसमें **फरवरी 2019** से कुल **250 आधार अंकों** की संचयी कटौती की गयी है।
- MPC ने अकोमोडेटिव स्टैन्स (समायोजन रूख) के साथ बने रहने का निर्णय लिया है। साथ ही, इसमें मुद्रास्फोटिकारी दबाव की निगरानी को जारी रखने की भी बात की गई है ताकि मुद्रास्फोति को लक्षित सीमा (+/- 2% के बैंड के भीतर 4% की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फोति) के भीतर बनाए रखते हुए संधारणीय आधार पर विकास को पुनर्जीवित किया जा सके।



Source: RBI



- **मौद्रिक योग (मॉनेटरी एग्रीगेट):** 2021-22 में, मौद्रिक योग वृद्धि दर {आरक्षित धन (रिजर्व मनी), व्यापक धन (ब्रॉड मनी) सहित} पिछले वर्ष की तुलना में कम था। 7 जनवरी 2022 तक-
 - रिजर्व मुद्रा (M0) ने एक वर्ष पहले 14.3% की तुलना में 13% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें वृद्धि मुख्य रूप से RBI में बैंक की जमा राशि से चालित थी।
 - व्यापक मुद्रा (M3) ने 9.9% की वृद्धि दर्ज की (दिसंबर 2021 तक), जो मुख्य रूप से कुल जमा (घटक पक्ष से) और बैंक ऋण (स्रोतों से) द्वारा चालित थी।
 - धन गुणक (M3/M0 का अनुपात) में 2017-18 से गिरावट जारी है। यह 5.3 (दिसंबर 2021 तक) पर है, जिसमें मार्च 2021 के 5.2 की तुलना में मामूली सुधार हुआ है।

- **मुद्रा संचलन (Currency in Circulation: CIC)** में 7.8% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है।

चलनिधि की स्थितियां और उसका प्रबंधन

- 2019 के मध्य से बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि, RBI के अकोमोडेटिव स्टैन्स और संवृद्धि का समर्थन करने के लिए मौद्रिक दशाओं में ढील दिए जाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- 2021-22 में, RBI ने लक्षित चलनिधि सहायता उपायों का उपयोग किया (चित्र देखें)।
- 2021-22 में, RBI ने चरणबद्ध ढंग से चलनिधि का सामान्यीकरण फिर से शुरू किया। उदाहरण के लिए-
 - इसने निष्क्रिय अवशोषण से चलनिधि को पुनर्संतुलित करने के लिए तरलता समायोजन सुविधा⁵⁸ के तहत 14-दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामियों का उपयोग किया।
 - नकद आरक्षित अनुपात (CRR) भी क्रमिक वृद्धि के माध्यम से मई 2021 (मार्च 2020 के 3% से) तक 4% के अपने महामारी पूर्व स्तर पर पहुंच गया।

सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास

- 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल, जून 2020 में 5.75% से बढ़कर 31 दिसंबर 2021 तक 6.45% हो गया।
- टर्म स्प्रेड (10 वर्षीय और 1 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल के बीच अंतर) भी थोड़ा संकीर्ण हुआ; अभी भी महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में व्यापक है।

बैंकिंग क्षेत्र

ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित उपलब्धियों के साथ बैंकिंग प्रणाली ने महामारी के आर्थिक आघात का सफलतापूर्वक सामना कर लिया:

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि अब 9.2% है (पिछले वर्ष 6.6%)।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात वर्ष 2017-18 के अंत में 11.2% से कम होकर सितंबर 2021 में 6.9% हो गया।
- इसी अवधि में निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NNPA) अनुपात 6% से कम होकर 2.2% हो गया।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्रचित मानक अग्रिम (Restructured Standard Advances: RSA) अनुपात 0.4% से बढ़कर 1.5% तक हो गया।
- कोविड-19 से संबंधित विभिन्न प्रकार के दंड से छूट/अधिस्थगनों के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.9% से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 8.5% हो गया।
 - PSBs के लिए GNPA गिरकर 8.6% हो गया जबकि दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात बढ़कर 10.1% हो गया।
- बाजार से पूंजी जुटाने वाले सरकारी और निजी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) 15.84% से बढ़कर 16.54% हो गया।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वार्षिक रूप से परिसंपत्तियों पर रिटर्न (ROA) और इक्विटी पर रिटर्न (RoI) बढ़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लिए उपर्युक्त दोनों ही मार्च 2016 से नकारात्मक रहने के बाद जून 2020 में सकारात्मक हो गए।

राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) और इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL)

- विभिन्न समाधान तंत्रों (जैसे कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, SARFAESI अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि) और 28 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के बावजूद, पहले से चले आ रहे NPAs के एक बड़े भंडार का समाधान किया जाना बाकी है।

⁵⁸ Liquidity Adjustment Facility: LAF

- पहले से चले आ रहे NPAs का समाधान करने और बैंक की बहियों को साफ करने के लिए, 2021 में दो नई संबंधित कंपनियों (ऋण प्रबंधन समझौते के तहत) का गठन किया गया है:
 - **NARCL:** यह एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) है। इसे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को एकत्र करने और उन्हें निपटाने के लिए जुलाई 2021 में गठित किया गया। इसका स्वामित्व मुख्य रूप से PSBs पास है और केनरा बैंक इसका प्रायोजक है; तथा
 - **IDRCL:** परिसंपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए सितंबर 2021 में एक सेवा कंपनी के रूप में इसका गठन किया गया था। इसका स्वामित्व मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों (51%) के पास है और शेष PSBs के पास।
- NARCL का 5 वर्ष का सीमित कार्यकाल होगा, और IDRCL का कार्यकाल NARCL के साथ समाप्त हो जाएगा।

समाधान प्रक्रिया (Resolution Process)

- NARCL, लीड बैंक को ऑफर देकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करेगा। दूसरी ओर, लीड बैंक NARCL के ऑफर को बेहतर बनाने के लिए स्विच चैलेंज प्रक्रिया के तहत अन्य ARC/बोलीदाताओं को आमंत्रित करेगा। यह सब NARCL को पसंदीदा बोलीदाता घोषित किए जाने से पहले किया जाना है।
- NARCL द्वारा अंतर्निहित ट्रस्टों में परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा जबकि IDRCL इनमें से प्रत्येक के लिए प्रस्तावित पुनर्गठन/समाधान योजना, रणनीतियाँ आदि तैयार करेगा और सुझाव देगा।
- **ARCs के लिए RBI ढांचे के भीतर ही परिसंपत्ति अधिग्रहण और समाधान होगा।**
 - उदाहरण के लिए- 15:85 संरचना (15% नकदी में और 85% सिक्यूरिटी रिसीट या SR में) के तहत RBI के मौजूदा विनियमों के भीतर परिसंपत्ति अधिग्रहण।
- मलेशिया और ब्रिटेन की तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर, NARCL द्वारा जारी किए गए SR को, विश्वसनीयता और आकस्मिक बफर प्रदान करने के लिए, सरकार द्वारा समर्थित (30,600 करोड़ रुपये तक) किया जाएगा।
- सरकार अपने द्वारा गारंटी दी गई राशि पर, जो 5 वर्ष तक वैध होगा, गारंटी शुल्क लगाएगी, जिसमें शीघ्र और समय पर समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए सालाना वृद्धि की जाएगी।

मौद्रिक संचरण- बैंक ऋण और जमा दरें (Monetary Transmission- Bank Lending and Deposit Rates)

- फरवरी 2019 से नवंबर 2021 के दौरान रुपये के नए ऋणों पर भारित औसत उधार दर⁵⁹ में 197 आधार अंकों और बकाया ऋणों पर 133 आधार अंकों की गिरावट आई है।
- निजी बैंकों की तुलना में PSBs ने अधिक ऋण दिए।
- बड़ी अधिशेष प्रणालीगत चलनिधि, अकोमोडेटिव स्टैंड को जारी रखने के फॉरवर्ड गाइडेंस और चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण के मूल्य निर्धारण के लिए बाह्य बेंचमार्क प्रणाली से मौद्रिक संचरण को सहायता मिली।

जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) और DICGC (संशोधन) अधिनियम, 2021

- 1961 के DICGC अधिनियम और 1961 के DICGC सामान्य विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित, DICGC, बीमाकृत बैंक के जमाकर्ताओं को बीमाकृत जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
- इसमें भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकल एरिया बैंक और सहकारी बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं।
- यह बैंकिंग लाइसेंस जारी होने पर तुरंत और स्वचालित रूप से किसी बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत करता है।
- सभी बीमाकृत बैंकों के लिए, DICGC को जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान अनिवार्य है। DICGC ऐसी स्थितियों में जमाकर्ताओं को बीमाकृत जमा राशि का भुगतान करता है, जैसे-
 - परिसमापन (बैंक बंद होने पर सभी परिसंपत्तियों की बिक्री) (ii) किसी योजना के तहत पुनर्निर्माण या कोई अन्य व्यवस्था, या (iii) किसी अन्य बैंक द्वारा विलय या अधिग्रहण।
- पिछले बजट में, जमा बीमा सुरक्षा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता कर दिया गया। मार्च 2021 तक, संरक्षित खातों की संख्या कुल खातों की संख्या (252.6 करोड़) का 98.1% थी। राशि के संदर्भ में, कुल बीमाकृत जमा, कुल निर्धारणीय जमा (Total Assessable Deposits) का 50.9% था।
 - अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के तहत, संख्या के संदर्भ में पूरी तरह से संरक्षित खाते कुल खातों के लगभग 80% हैं, जबकि बीमाकृत जमाराशि, कुल निर्धारणीय जमा राशि की 20-30% है।
 - विभिन्न बैंक-समूह के अनुरूप, कुल जमा की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत RRBs के लिए 84%, सहकारी बैंकों के लिए 70%, SBI के लिए 59%, PSB के लिए 55%, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 40% और विदेशी बैंकों के लिए 9% है।

⁵⁹ Weighted Average Lending Rate: WALR

DICGC (संशोधन) अधिनियम, 2021 की मुख्य विशेषताएँ

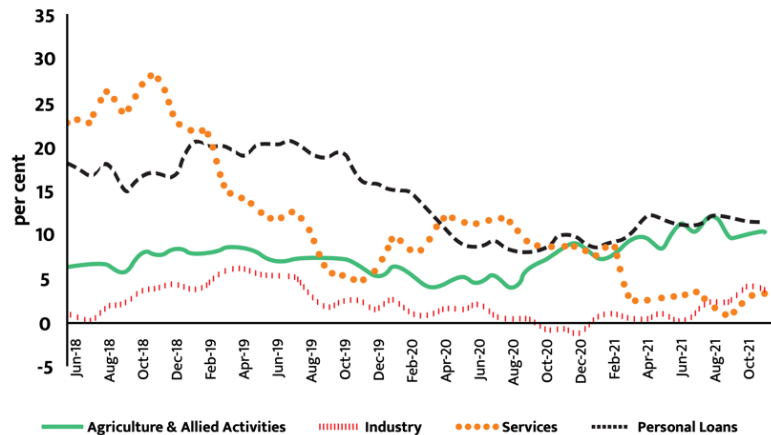
यह विभिन्न प्रतिबंधों, जैसे- RBI द्वारा आरोपित अधिस्थगन के कारण प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा अपने स्वयं के धन तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों और अन्य मुद्दों को संबोधित करता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं-

- अधिकतम 90 दिनों की समय सीमा के साथ इन जमाकर्ताओं को DICGC से अंतरिम भुगतान की शुरुआत करना।
- अपनी शर्तों पर बीमा भुगतान के बाद बीमाकृत बैंकों से देय पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए DICGC बोर्ड को सशक्त बनाना।
- बैंकों से DICGC को समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए देरी की स्थिति में दंडात्मक व्याज का प्रावधान करना।
- प्रीमियम पर 15 पैसे की पूर्ववर्ती सीमा को हटाया जाना और RBI की पूर्व स्वीकृति से DICGC द्वारा प्रीमियम पर उच्चतम सीमा अधिसूचित करना।

बैंक क्रेडिट वृद्धि

- क्रेडिट वृद्धि: अप्रैल 2021 की शुरुआत में 5.3% से 7.3% तक मामूली वृद्धि के बाद दिसंबर में 9.2% तक की दर से तेजी से सुधार हुआ।
- क्षेत्र-वार क्रेडिट वृद्धि (नवंबर 2020-21 में वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि)
 - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत ऋणों में क्रमशः 10.4% और 11.6% की उच्च वृद्धि दर्ज की गई।
 - 2020 में नकारात्मक चरण में प्रवेश करने के बाद, उद्योग ऋण वृद्धि लगातार सुधरकर 3.8% हो गई, जबकि मध्यम उद्योगों में 48.7% की उच्चतम वृद्धि देखी गई।
 - सेवा ऋण वृद्धि 3.6 प्रतिशत पर मंद बनी रही।

Growth (YoY) in Sectoral Credit



डिजिटल भुगतान और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म

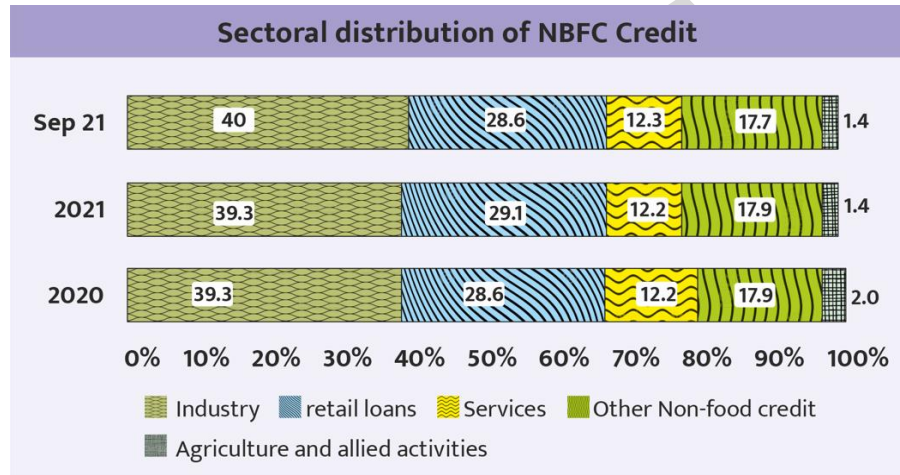
- RBI के डिजिटल भुगतान सूचकांक की उच्च वृद्धि जारी रही। यह सूचकांक देश भर में पाँच मापदंडों पर भुगतानों के डिजिटलीकरण के प्रसार को दर्शाता है। (चित्र देखें...)
- यह मार्च 2018 (आधार अवधि) में 100 से बढ़कर सितंबर 2021 में 304.06 हो गया।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली और डिजिटल भुगतान करने के तरीकों में भी वृद्धि हुई।
- वर्तमान में, यूनिकाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) देश की सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली है, जिसने-
 - अकेले दिसंबर 2021 में 8.26 लाख करोड़ रुपये के 4.6 बिलियन लेनदेन किए, जिसमें लगभग 50% UPI भुगतान 200 रुपये से कम के थे।
 - 44,381 करोड़ रुपये मूल्य के 24.26 मिलियन से अधिक एकमुश्त अनिवार्य (वन टाइम मैन्डेट) लेनदेन को संसाधित किया।
 - हाल ही में, भूटान अपने QR कोड के लिए UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया।



- यह सिंगापुर के बाद मर्चेट लोकेशन पर BHIM-UPI स्वीकार करने वाला दूसरा देश भी है। RBI और सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण जुलाई 2022 तक UPI और PayNow को जोड़ने के लिए भी काम कर रहे हैं।
- तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) 24x7x365 उपलब्ध रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर प्लेटफॉर्म है, जिसने अप्रैल-दिसंबर 2021 में 29,349 बिलियन रुपये के लेनदेनों को संसाधित किया।
- 2021 में e-RUPI को लॉन्च किया गया। यह बेसिक फोन और इंटरनेट कनेक्शन के अभाव वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए एक व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल वाउचर है। इसके लिए ग्राहकों के पास बैंक खाता होने की आवश्यकता नहीं है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) क्षेत्र

- **NBFCs की क्रेडिट वृद्धि:** यह कुल क्रेडिट में मामूली वृद्धि (मार्च 2021 में 27.53 लाख करोड़ रुपये से सितंबर 2021 में 28.03 लाख करोड़ रुपये) के साथ सुस्त बनी रही।
- **NBFCs की क्रेडिट गहनता**
यानी GDP के अनुपात के रूप में
NBFC क्रेडिट: यह लगातार बढ़ रहा है और मार्च 2021 (2013 में 8.6) के अंत में 13.7 तक पहुँच गया। इसमें उद्योग NBFC से सबसे बड़े क्रेडिट प्राप्तकर्ता हैं, जिसके बाद खुदरा ऋण और सेवाओं का स्थान है। (चित्र देखें...)
- **NBFCs की कुल परिसंपत्ति:** यह सितंबर 2020 के 36.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2021 में 42.05 लाख करोड़ रुपये हो गई।
- **बैंक और NBFCs:** NBFCs से बैंकों के संपर्क (बैंक ऋण और निवेश) में वृद्धि 8.5% की सलाना वृद्धि दर पर सितंबर 2021 में 9.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई।
- **बाह्य देयताएँ:** सुरक्षित एवं असुरक्षित उधारियों और सार्वजनिक जमाओं के रूप में NBFCs की बाह्य देयताएँ 7.95% बढ़ गई हैं।
- **GNPA, NPA और CRAR:** GNPA का अनुपात बढ़कर 6.55% हो गया, जबकि NPA का अनुपात सितंबर 2021 के अंत में 2.93% पर समान बना रहा। NBFC का CRAR 15% की नियामकीय आवश्यकता की तुलना में 26.64% था।



भारत में फैक्ट्रिंग {फैक्ट्रिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021}

- फैक्ट्रिंग वह लेन-देन है जिसमें एक इकाई तत्काल फंड के लिए अपनी प्राप्य राशियाँ (किसी ग्राहक द्वारा देय) किसी तृतीय पक्ष (बैंक या NBFC जैसे एक 'फैक्टर') को बेच देती है।
- यह दुनिया भर में, विशेष रूप से चलनिधि की समस्याओं का सामना कर रही MSMEs के लिए चलनिधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 फैक्ट्रिंग पर कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- यह चार प्रकार की इकाइयों को फैक्ट्रिंग व्यवसाय में संलग्न होने की अनुमति देता है, जिसमें बैंक, NBFC, सांविधिक निगम और कंपनियाँ शामिल हैं।
- लेकिन केवल 7 NBFCs (जिन्हें NBFC-फैक्टर कहा जाता है) को मुख्य व्यवसाय के रूप में फैक्ट्रिंग की शर्त के कारण RBI से फैक्ट्रिंग व्यवसाय पंजीकरण प्राप्त हुआ है, अर्थात् NBFC को-
 - फैक्ट्रिंग व्यवसाय में अपनी वित्तीय संपत्ति रखने की आवश्यकता है जो इसकी कुल परिसंपत्ति का कम-से-कम 50% हो और फैक्ट्रिंग व्यवसाय से प्राप्त आय उसकी सकल आय के 50% से कम न हो।
- प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को उदार बनाने और मजबूत नियामकीय क्रियाविधि सुनिश्चित करने के लिए, यह संशोधन अधिनियम लाया गया था, साथ ही RBI ने अपने महत्वपूर्ण नियमों को अधिसूचित किया है। यह अधिनियम यू.के. सिन्हा समिति या MSMEs पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप है।
- इसके द्वारा प्रमुख संशोधन:
 - फैक्ट्रिंग व्यवसाय के लिए पात्र NBFC की संख्या बढ़ाने हेतु प्रमुख व्यवसाय के मानदंड के रूप में फैक्ट्रिंग को हटाना।

- दोहरी वित्तपोषण धोखाधड़ी को रोकने और चालान के पंजीकरण और इस पर प्रभार की संतुष्टि के लिए समयावधि निर्दिष्ट करने हेतु सरकार को सशक्त बनाने के लिए **फैक्टरिंग प्रक्रिया को सुचारू बनाना**।
- **ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म** का उपयोग करने वाले फैक्टर्स की ओर से 'सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटररेस्ट'⁶⁰ के साथ **प्रभार का प्रत्यक्ष पंजीकरण करने हेतु प्लेटफॉर्म को अनुमति देना**।
- इससे प्रक्रिया की परिचालन दक्षता में सुधार आएगा, TReDS को बढ़ावा मिलेगा और फैक्टर्स पर प्रक्रिया संबंधी बोझ कम होगा।
- "असाइनमेंट", "फैक्टरिंग बिजनेस" और "रिसीवेबल्स" की **परिभाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप बनाने के लिए उनमें संशोधन करना**।
- धारा 3 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने और धारा 19 के तहत फैक्टर्स की ओर से TReDS संस्थाओं द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री में लेनदेन के विवरणों को दाखिल करने के तरीके पर **RBI को विनियमन बनाने की शक्ति दी गई है**।

MSCI उभरते बाजारों का सूचकांक और भारत का भारांक

- MSCI, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (Morgan Stanley Capital International) का संक्षिप्त रूप है। यह एक निवेश अनुसंधान फर्म है जो संस्थागत निवेशकों और हेज फंड्स को स्टॉक इंडेक्स, पोर्टफोलियो जोखिम और प्रदर्शन विश्लेषण तथा शासन उपकरण प्रदान करता है।
- वर्ष 2001 में लॉन्च किया गया '**MSCI उभरते बाजारों का सूचकांक**' वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय सूचकांकों में से एक है। यह भारत सहित 25 उभरते बाजार वाले देशों में बड़ी और मध्यम-पूंजी वाली कंपनियों का इक्विटी प्रदर्शन दर्शाता है।
- **MSCI उभरते बाजारों के सूचकांक में भारत का भारांक 106 सूचीबद्ध भारतीय इकाइयों के साथ अगस्त 2020 के 8.3% से बढ़कर दिसंबर 2021 में 12.45% हो गया।**
- अक्सर वैश्विक संस्थागत निवेशकों द्वारा अपनी निष्क्रिय निवेश रणनीति के हिस्से के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भारांक में वृद्धि से इक्विटी बाजारों में FPI निवेश आकर्षित करने में मदद मिलती है।
 - 2020-21 में, भारतीय इक्विटी बाजारों में **₹2.74 लाख करोड़** रूपए से अधिक का FPI प्रवाह देखा गया।

पूंजी बाजार में विकास

- **प्राथमिक बाज़ार (एक्विटी):** अप्रैल-नवंबर, 2021 में 75 कंपनियों के **इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग**⁶¹ को सूचीबद्ध किया गया है। इससे **89,066 करोड़ रुपये जुटाए गए**, जो अप्रैल-नवंबर 2020 में 29 कंपनियों द्वारा जुटाए गए **14,733 करोड़ रुपये** से बहुत अधिक है। यह संसाधनों के संग्रहण में वृद्धि का संकेतक है।
 - राइट्स इश्यू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) द्वारा जुटाई गई राशि में क्रमशः 62.6% और 52.9% की उल्लेखनीय कमी आई।
- **प्राथमिक बाजार (ऋण):** कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के माध्यम से ऋण जुटाने की गति धीमी पड़ गई। इसके तहत अप्रैल-नवंबर 2020 में लगभग **4.92 लाख करोड़ रुपये** की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 में लगभग **3.7 लाख करोड़ रुपये** जुटाए जा सके।
 - हाइब्रिड और कन्वर्टिबल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (INVITs) आदि जैसे नए साधनों के उपयोग से फंड जुटाने में विविधीकरण देखा गया।
- अप्रैल-नवंबर 2021 में लगभग **221 लाख व्यक्तिगत डीमैट खाते** जुड़ने से **खुदरा भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।**
- **द्वितीयक बाजार (म्यूचुअल फंड):** म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधनाधीन निवल परिसंपत्ति⁶² **30.0 लाख करोड़ रुपये** (नवंबर 2020 के अंत) से **24.4% बढ़कर 37.3 लाख करोड़ रुपये** (नवंबर 2021 के अंत) हो गई।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors: FPI) द्वारा निवेश

- अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, भारतीय शेयर में FPIs के निवेश में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में **82.8% तक की कमी दर्ज हुई है**। ज्ञातव्य है कि नवंबर 2021 तक FPIs की ओर से कुल निवेश **288.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था। यह नवंबर 2020 से **9.2% की वृद्धि दर्शाता है**।

⁶⁰ Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest: CERSAI

⁶¹ Initial Public Offering: IPO

⁶² Assets Under Management: AUM

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक

- प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय बाजारों ने अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया (निफ्टी 50 में 18.1% और S&P BSE सेंसेक्स में 17.7% की वृद्धि)।
- अच्छी कॉर्पोरेट आय, कोविड-19 टीकाकरण में तेज वृद्धि और देश भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलने से 18 अक्टूबर, 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी 50 बढ़कर 61,766 और 18,477 के अपने चरम पर पहुंच गए।
- भारत VIX में अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 21.4% की कमी आई। यह निकट अवधि में अर्थात् अगले 30 कैलेंडर दिनों में बाज़ार के उतार-चढ़ाव की संभावना को दर्शाता है।

बीमा क्षेत्र

- बीमा व्यापन और बीमा घनत्व के अंतराष्ट्रीय मानकों के आधार पर, बीमा क्षेत्र की क्षमता और प्रदर्शन का आकलन,-
 - भारत में बीमा व्यापन 2001 में 2.71% से बढ़कर 2020 में 4.2% (जीवन बीमा में 3.2%) और गैर-जीवन बीमा में 1%) तक वृद्धि।
 - विश्व स्तर पर, जीवन बीमा में बीमा व्यापन 3.3% है (भारत लगभग इसके बराबर है) और गैर-जीवन बीमा में यह 4.1% है (भारत पिछड़ रहा है)।
 - भारत में बीमा घनत्व 2001 में \$11.5 से बढ़कर 2020 में \$78 (जीवन बीमा में \$59 और गैर-जीवन बीमा में \$19) हो गया।
 - यह 2020 में क्रमशः जीवन बीमा खंड के लिए \$360 और गैर-जीवन बीमा खंड के लिए \$449 के वैश्विक बीमा घनत्व से बहुत कम है।

पेंशन क्षेत्र

- नई पेंशन योजना (NPA) और अटल पेंशन योजना (APY) के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 374.32 लाख (सितंबर 2020) से 23.7% बढ़कर 463 लाख (सितंबर 2021) हो गई।
- NPS के तहत समग्र योगदान इसी अवधि के दौरान 29% से अधिक बढ़ा, जिसमें अधिकतम योगदान नागरिकों की ओर से तथा उसके बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र से थी।
- NPS और APY के तहत प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति⁶³ भी 34.8% बढ़कर 6.67 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई।
- APY के तहत, युवा वर्ग द्वारा नामांकन में वृद्धि और लैंगिक अंतराल में कमी देखी गई। महिला ग्राहकों की भागीदारी मार्च 2016 में 37% से बढ़कर सितंबर 2021 में 44% हो गई।
- क्षेत्र सुधार: पेंशन फंड में किसी विदेशी कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों की कुल धारिता की सीमा 49% से संशोधित कर 74% कर दी गई है। 60 वर्ष की आयु के बाद शामिल होने वाले NPS ग्राहक 75 वर्ष की आयु (पहले 70 वर्ष) तक निवेशक बने रह सकते हैं। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सरकारी अंशदान को 10% से बढ़कर 14% कर दिया है।

कॉर्पोरेट्स का स्वैच्छिक परिसमापन (Voluntary Liquidation of Corporates)

- स्वैच्छिक परिसमापन का आशय ठीक-ठाक परिचालन के बावजूद कंपनी के बंद होने से है।
- यह व्यक्तिगत कारणों से, अनुषंगिक कंपनियों के विलय आदि के कारण हो सकता है।
- वर्तमान में, यह किया जा सकता है-
 - या तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) के माध्यम से, या
 - IBC, 2016 की धारा 59 के तहत {IBBI (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के साथ}।
- यह दोनों लंबे समय तक लंबित रहते हैं। साथ ही, विभिन्न प्रक्रियात्मक मुद्दों का सामना करने की वजह से, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया जटिल और समयसाध्य बन जाती है।
- व्यवसाय से बाहर निकलने की सुगमता में सुधार लाने के लिए, प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एकल विंडो तथा सभी परिसमापन चरणों का संयोजन करने के लिए एकल पोर्टल के निर्माण के माध्यम से किया जा सकता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)

- IBC ने निम्नलिखित तरीके से एक सुसंगत और व्यापक दिवाला परिवेश का निर्माण किया है:
 - अपीलीय प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण की दो पीठें,

⁶³ Asset Under Management: AUM

- निर्णायक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की 15 पीठें,
- नियामक के रूप में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, और
- दिवाला व्यवसाय व मूल्यांकन व्यवसाय वाले सेवा प्रदाताओं को बढ़ाना, दिवाला सेवाओं को पेशेवर बनाने में मदद करना।
- कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, 25 मार्च 2020 को या उसके बाद होने वाली किसी भी डिफॉल्ट के लिए कॉर्पोरेट देनदार (corporate debtor) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया⁶⁴ की शुरुआत को निलंबित कर दिया गया था। इसके लिए दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया गया था।
 - इसके अलावा, महामारी के कारण तनाव से गुजर रही फर्मों को राहत प्रदान करने के लिए इस संहिता का निलंबन 3 महीने के लिए दो बार बढ़ाया गया।
- लगातार समाधान (resolutions) प्रक्रिया पूर्ण होने और के अन्य छूटों के कारण लंबित मामलों में कमी आई। सितंबर 2021 तक, CIRP मामले बढ़कर 1,640 हो गए, जिसमें लगभग 75% मामले, 270 दिनों से अधिक समय से लंबित थे।
- संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का बचाव: IBC ने समाधान योजनाओं के माध्यम से 421 कॉर्पोरेट देनदारों को (CIRP में प्रवेश करते समय उनकी 1.48 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों के बदले ₹2.55 लाख करोड़ की वसूली कर) राहत पहुंचाई है।
- परिसमापन (कारोबार बंद करना): 1,419 कॉर्पोरेट देनदारों (0.52 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों वाले) को परिसमापन के लिए आदेश दिया गया। इसने 2,025 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति के मुकाबले 1,983 करोड़ रुपये की वसूली करते हुए 264 कॉर्पोरेट देनदारों को परिसमापन का आदेश दिया।
- समय और लागत: जिन CIRPs का समाधान किया जा चुका था, उनकी प्रक्रिया समाप्ति में औसतन 428 दिनों का समय लगा, जबकि परिसमापन के 1,419 आदेशों में औसतन 375 दिन लगे।
- व्यवहार संबंधी परिवर्तन: संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य में क्रमिक गिरावट और समाधान प्रक्रिया के दुष्प्रभावों से बचने के लिए, देनदार अब पहले ही संकट का समाधान करने लगे हैं।

IBC संहिता में संशोधन

- वर्ष 2021 में, कॉर्पोरेट MSMEs के लिए प्री-पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया (PPIRP) प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से IBC संहिता, 2016 में संशोधन किया गया था।



⁶⁴ Corporate Insolvency Resolution Process: CIRP

सीमा-पार दिवाला

- यह ऐसी विशेष स्थितियों को निरूपित करता है जिसमें एक दिवालिए देनदार के पास एक से अधिक देशों में परिसंपत्ति और/या लेनदार होते हैं।
- IBC की धारा 234 और 235 द्वारा विनियमित, ये प्रकृति में तदर्थ हैं और विलंब के प्रति अतिसंवेदनशील हैं।
 - धारा 234 केंद्र सरकार को सीमा-पार दिवाला के बारे में स्थितियों का समाधान करने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने का अधिकार देती है, और
 - धारा 235 अधिनिर्णय प्राधिकरण को धारा 234 के तहत समझौते वाले देशों में IBC के तहत दिवाला कार्यवाहियों के संबंध में साक्ष्य या कार्रवाई के अनुरोध से निपटने के लिए अदालत या सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी करने की अनुमति देती है।
- मानकीकृत सीमा-पार दिवाला ढांचे का अभाव जटिलताओं को जन्म देता है और कई मुद्दों को उठाता है जैसे कि:
 - दिवाला प्रशासक के लिए विदेश में रखी गई परिसंपत्ति तक पहुंच की सीमा,
 - भुगतानों की प्राथमिकता, अर्थात् क्या विदेशी प्रशासन के पास फंड जाने से पहले स्थानीय लेनदारों की स्थानीय परिसंपत्ति तक पहुंच है या नहीं,
 - विदेशी प्रशासन में स्थानीय लेनदारों के दावों की मान्यता,
 - स्थानीय परिसंपत्तियों पर स्थानीय प्रतिभूतियों की मान्यता और प्रवर्तन, कराधान प्रणाली जहाँ विदेशी प्रशासक नियुक्त किया जाता है, आदि।
- 2018 की दिवाला कानून समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय संदर्भ के अनुरूप कुछ संशोधनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग⁶⁵ को अपनाकर मजबूत सीमा-पार दिवाला ढांचे का निर्माण हुआ है।

शब्दावली	
तरलता समायोजन सुविधा (LAF)	यह मुख्य रूप से RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऐसा मौद्रिक नीति उपकरण है, जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों (रेपो) के माध्यम से धन उधार लेने या रिवर्स रेपो समझौतों के माध्यम से RBI को ऋण देने की अनुमति देता है।
परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (Variable Rate Reverse Repo: VRRR)	यह परिवर्तनीय दर या रिवर्स रेपो से बैंकिंग प्रणाली से धन अवशोषित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला रिवर्स रेपो का उप-प्रकार है।
भारित औसत उधार दर (Weighted Average Lending Rate: WALR)	सभी ऋणों पर दिए गए कुल ब्याज की कुल दर को भारित औसत ब्याज दर कहा जाता है। भारित औसत, प्रत्येक ऋण की ब्याज दर को ऋण शेष से गुणा करता है और कुल ऋण शेष से राशि विभाजित करता है।
सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम (G-SAP)	G-SAP वह समर्पित चलनिधि विंडो है जिसके माध्यम से RBI बैंकिंग प्रणाली में नकदी डालने के लिए सॉवरेन पेपर खरीदता है। यह खुले बाजार के परिचालनों से निकटता से संबंधित है। G-SAP में सरकारी प्रतिभूतियों की एक विशिष्ट मात्रा खरीदने के लिए अग्रिम प्रतिबद्धता शामिल होती है, जो यील्ड कर्व का स्थिर और व्यवस्थित क्रमिक विकास संभव बनाती है।
टर्म स्प्रेड	यह अल्पावधिक और दीर्घावधिक सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों के बीच का अंतर है।
व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS)	यह MSMEs द्वारा प्राप्य राशियों की पारदर्शी और ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने वाला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। TReDS पर, विक्रेताओं को विभिन्न ब्याज दरों का विकल्प, और किसी संपार्श्विक के बिना बेचने के लिए चुनने के लिए कई वित्त पोषक मिलते हैं।
बीमा पैठ	बीमा प्रीमियम GDP का कितने प्रतिशत है, इस आधार पर बीमा पैठ मापा जाता है।
बीमा घनत्व	इसका जनसंख्या से प्रीमियम के अनुपात के रूप में मापन किया जाता है (अंतर्राष्ट्रीय तुलना की सुविधा के लिए डॉलर में मापन किया जाता है)।

अध्याय एक नज़र में
मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने उदार मौद्रिक नीति रुख के साथ नीतिगत रेपो दर (4%) पर यथास्थिति बनाए रखी।
बाजार में तरलता अधिक बनी रही। RBI ने आगे तरलता प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए और चरणबद्ध ढंग से इसका सामान्यीकरण फिर से शुरू किया।

⁶⁵ United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL

रिज़र्व मुद्रा (M0) और व्यापक मुद्रा (M3) में क्रमशः 13% और 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 2017-18 से गिरावट के बाद मुद्रा गुणक में मामूली सुधार दर्ज किया गया।
वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली ने बैंक ऋण वृद्धि में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ महामारी का आर्थिक आघात अच्छी तरह से झेला।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए GNPA अनुपात और NNPA अनुपात में गिरावट आई जबकि जोखिम-भारित अस्तियों से पूंजी अनुपात में वृद्धि हुई।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए परिसंपत्तियों पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए धनात्मक बना रहा।
पूंजी बाजार ने फंड जुटाने में उल्लेखनीय प्रगति की है (एक असाधारण वर्ष)। इसने 504.5% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। सेंसेक्स और निफ्टी भी शिखर पर पहुंचने में सफल रहे।
कॉर्पोरेट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के रूप में IBC के तहत प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रदान की गई।

हिन्दी माध्यम
29 March

ENGLISH MEDIUM
22 March

- ✍ संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- ✍ मई 2021 से अप्रैल 2022 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- ✍ प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- ✍ लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग में लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का करेंट अफेयर्स

प्रीलिम्स 2022 के लिए मात्र 60 घंटे में

अध्याय-4



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के प्रसारण में सहायता कर सकता है?

1. अधिशेष तरलता
2. समायोजन वाला कदम
3. ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए बाहरी बेंचमार्क प्रणाली

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

Q2. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. इसे बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए स्थापित किया गया है।
2. NARCL में अधिकांश हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों के पास है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Q3. किसी अर्थव्यवस्था में तरलता या चलनिधि के सामान्यीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस उपाय/किन उपायों का उपयोग किया जा सकता है?

1. केंद्रीय बैंक द्वारा परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (VRRR) नीलामियां।
2. नकद आरक्षित अनुपात को कम करना।
3. आर.बी.आई. द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

Q4. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) (संशोधन) अधिनियम, 2021 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू है।
2. यह अधिनियम जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान का प्रावधान करता है।
3. यह प्रीमियम की अधिकतम सीमा 15 पैसे लागू करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2

Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आढ़त (फैक्टरिंग) एक वित्तीय लेन-देन है, जो किसी व्यवसाय को तत्काल धन प्राप्त करने की अनुमति देता है।
2. भारत में आढ़त व्यवसाय को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत **UNCITRAL** (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग) मॉडल कानून को अपनाने से मानकीकृत सीमा-पार दिवाला ढाँचे की अनुपस्थिति से संबंधित बढ़ती जटिलताओं और मुद्दों का समाधान होगा। चर्चा कीजिए।

Q2. विभिन्न समाधान तंत्रों के बावजूद पुराने एन.पी.ए. के एक बड़े स्टॉक का समाधान किया जाना शेष है। इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) और इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) संस्थाओं की स्थापना इस मुद्दे को कैसे संबोधित करेगी।

लाइव ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

अलटरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023 और 2024

DELHI: 5 अप्रैल | 9 AM | 1 फरवरी | 1 PM

- इसमें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सभी चार प्रश्न पत्रों के सभी टॉपिक, प्रारंभिक परीक्षा (सामान्य अध्ययन) एवं निबंध के प्रश्न पत्र का व्यापक कवरेज शामिल है।
- हमारा दृष्टिकोण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु छात्रों की मौलिक अवधारणाओं एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण करना है।
- सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए हमारी PT 365 और Mains 365 की कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स की कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी (केवल ऑनलाइन कक्षाएं)।
- इसमें सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए ऑल इंडिया जी.एस. मॅस, प्रीलिम्स, सीसेट और निबंध टेस्ट सीरीज शामिल है।
- छात्रों के व्यक्तिगत ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा।



अध्याय 5: कीमतें और मुद्रास्फीति (Prices and Inflation)

परिचय

वर्ष 2021 में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ ही बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बन गई थी। हालांकि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं⁶⁶ में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। लेकिन, भारत में यह एक सीमित दायरे अंतर्गत ही रही।

वैश्विक मुद्रास्फीति

- वर्ष 2021 में, अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई थीं। इससे उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दरों में बढ़ोत्तरी हुई।
- यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 3.1% और EMDEs में 5.7% थी। इसके निम्नलिखित कारक थे:

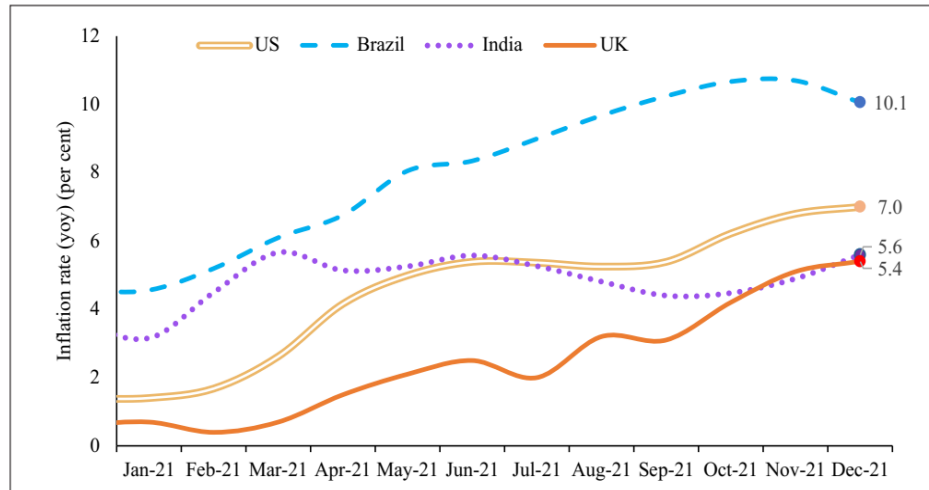
- कोविड-19 संबंधित प्रोत्साहन व्यय, मुख्य रूप से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में परिवारों को विवेकानुदान वितरण/ हैंडआउट्स के रूप में।
- दबी हुई मांग जिसने उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दिया।
- ऊर्जा, खाद्य, गैर-खाद्य वस्तुओं और लागत कीमतों में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं, बढ़ती माल ढुलाई लागत आदि ने विश्व भर में मुद्रास्फीति को बढ़ाया है।

- एक ओर कच्चे तेल की मांग में वृद्धि होने तथा दूसरी ओर 'पेट्रोलियम निर्यातक देशों' के संगठन एवं उसके सहयोगियों' (ओपेक+) द्वारा आपूर्ति में कटौती किए जाने से तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- सरकार ने प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन के लिए सक्रियतापूर्वक निवारक कदम उठाये थे। इसी कारण भारत में कीमतों में हुई वृद्धि तुलनात्मक रूप से सीमित रही।

घरेलू मुद्रास्फीति

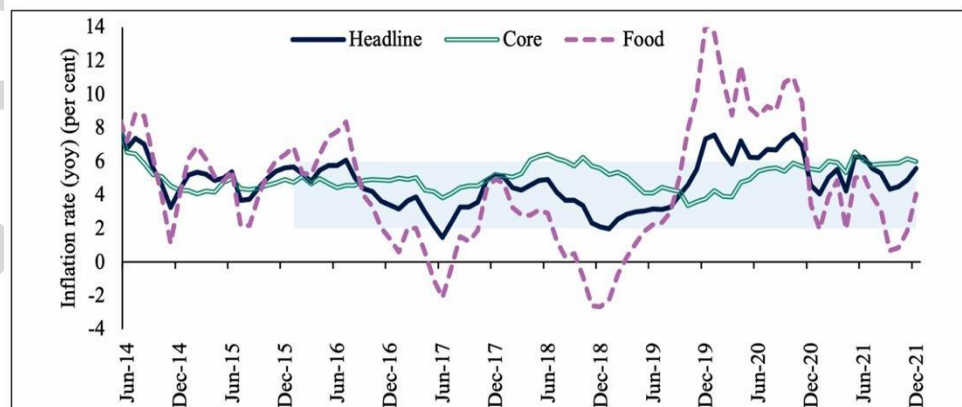
- खुदरा मुद्रास्फीति, को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त⁶⁷ मुद्रास्फीति द्वारा मापा जाता है। यह वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में 5.2% तक सीमित बनी रही। यह वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 6.6% थी।

Consumer Price Inflation in select countries



Source: Organisation for Economic Co-operation and Development; Office for National Statistics, UK

Trends in CPI-C Headline, Core and Food inflation



Source: NSO, MoSPI

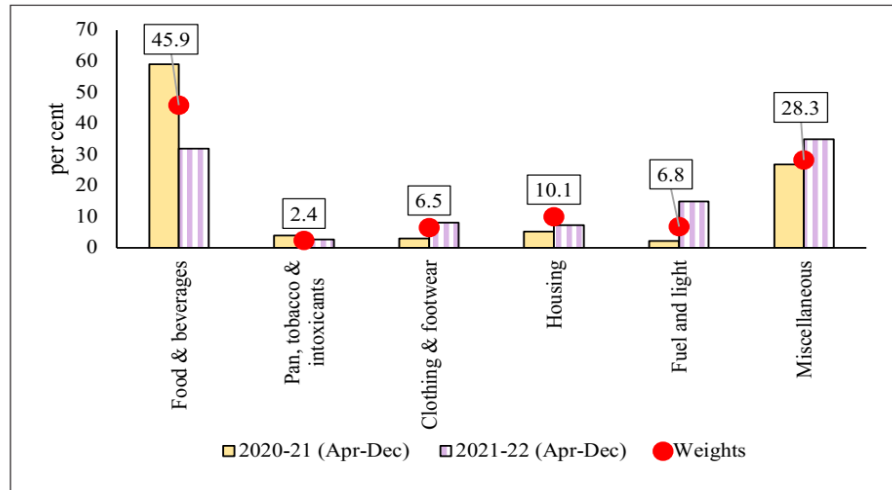
⁶⁶ Emerging Markets and Developing Economies: EMDEs

- इसकी तुलना में, थोक मूल्य सूचकांक⁶⁸ मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि देखी गई है। यह वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 12.5% हो गई। इसके निम्नलिखित कारण रहे:
 - पिछले वर्ष में इसका निम्न आधार पर रहना, आर्थिक गतिविधियों में तेजी, वैश्विक ज़िंसों और अन्य आयातित आदानों की कीमतों में तेज वृद्धि और उच्च माल ढुलाई लागत।

मुद्रास्फीति और उसके चालकों के वर्तमान रुझान

- खुदरा मुद्रास्फीति में हाल के रुझान:
 - जुलाई 2021 से, औसत खुदरा मुद्रास्फीति अपनी 4% (+/- 2%) की लक्षित सीमा के भीतर है।
 - यह गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण हुई है। यह वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में औसतन 2.9% थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 9.1% थी।

Contribution of groups to overall CPI-C inflation in 2020-21 (April-December) and 2021-22 (April-December) in per cent



Source: NSO, MoSPI

- चालू वित्त वर्ष में, औसत कोर मुद्रास्फीति (खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति) ने बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई है।
- ईंधन मर्दों की विसंगतियों को दूर करने के लिए, "रिफाईंड कोर" मुद्रास्फीति का निर्माण किया गया है। इसके लिए हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति से 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' तथा 'ईंधन व प्रकाश' के अलावा, मुख्य ईंधन मर्दों जैसे 'वाहन के लिए पेट्रोल', 'वाहन के लिए डीजल' और 'वाहनों के लिए स्नेहक और अन्य ईंधन' को भी बाहर किया गया था।
 - जून 2020 के बाद से, परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति, पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति से काफी नीचे रही है। यह "पारंपरिक" कोर मुद्रास्फीति माप में ईंधन मर्दों की मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाता है।
- खुदरा मुद्रास्फीति के प्रमुख चालक:
 - वर्ष 2021-22 में मुद्रास्फीति में विविध मर्दों का समग्र योगदान 26.8% से बढ़कर 35% तथा ईंधन और प्रकाश का योगदान 2.9% से बढ़कर 14% हो गया।
 - दूसरी ओर, खाद्य और पेय पदार्थों का योगदान 59% से घटकर 31.9% हो गया।

खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) को प्रेरित करने वाले चालक क्या हैं?

प्रमुख समूह	मुद्रास्फीति चालक
खाद्य और पेय पदार्थ	तेल और वसा के चलते 60% मुद्रास्फीति देखने को मिली। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि रही है। अनाज और उत्पादों में मुद्रास्फीति नकारात्मक रही। भारत अपने खाद्य तेलों की खपत का लगभग 60% आयात करता है।
ईंधन	अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों की उच्च कीमतें और उच्च कर।
विविध	परिवहन और संचार तथा उसके बाद स्वास्थ्य।
वस्त्र और जूते	उच्च उत्पादन और इनपुट लागत (आयातित इनपुट सहित), उपभोक्ताओं की मांग फिर से बढ़ना आदि।

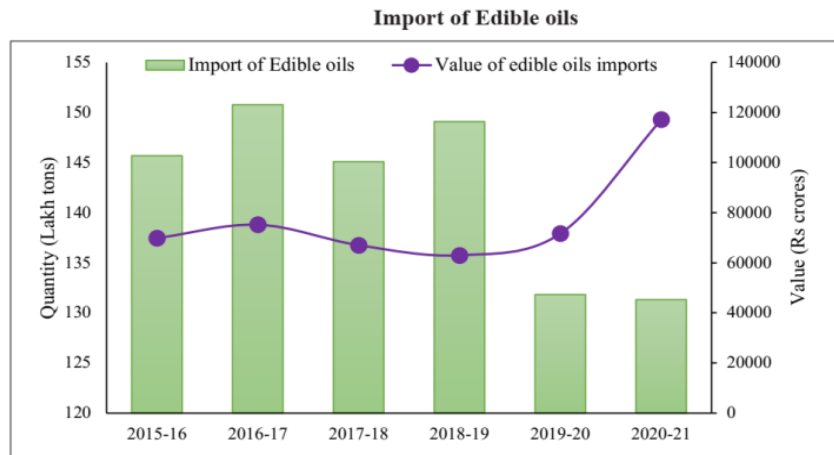
- मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम:
 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की गई। उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए अधिकांश राज्यों ने मूल्य वर्धित कर में कटौती की।

⁶⁷ Consumer Price Index-Combined: CPI-C

⁶⁸ Wholesale Price Index: WPI

- अधिकांश आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन। जैसे-
 - **प्याज:** मूल्य वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण।

- **दालें:** तुअर और उड़द को 'मुक्त' आयात श्रेणी में रखा गया। मसूर पर शून्य आयात शुल्क और उस पर लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना और विकास उपकरण में कमी की गई।
- **खाद्य तेल:** खाद्य तेलों पर मूल शुल्क में कमी, अटकलें और जमाखोरी को कम करने के उपाय, वैकल्पिक उत्पादों का उत्पादन और सोयामील को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया जाना।



Source: Solvent Extractors Association of India

- **जल्दी खराब होने वाली आवश्यक वस्तुएँ:** ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार कर इसे **TOP** (टमाटर, प्याज और आलू) से **TOTAL** (जल्दी खराब हो जाने वाली 41 वस्तुओं) के लिए लागू किया गया, किसान रेल आदि।

ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में अंतर

- ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के बीच जुलाई 2018 से दिसंबर 2019 तक बड़ा अंतर आया था। वर्ष 2020 में इस अंतर में गिरावट आई थी। अब CPI-शहरी CPI-ग्रामीण मुद्रास्फीति के करीब पहुंच गई है।
- दो मुख्य विचलन बिंदु 'नवंबर 2020-मार्च 2021' और 'सितंबर 2021 से आगे' देखे गए। यहां विचलन के पीछे मुख्य कारक खाद्य और पेय पदार्थ रहे थे।

मूल्य रुझान

कृषि जिस

- कृषि जिसों में, **मौसमी तत्व और अनियमित आघात** (बारिश, फसल में देरी आदि) **मूल्य में भिन्नता लाने वाले** मुख्य योगदानकर्ता हैं।
- यह **मौसमी तत्व** के कारण **जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं** जैसे टमाटर और प्याज में **अधिक प्रमुख** है।
 - टमाटर की कीमतों में हर वर्ष जुलाई से नवंबर तक वृद्धि होने और मार्च में गिरावट आने की प्रवृत्ति होती है।
 - रबी फसल (दिसंबर-जनवरी से मार्च-मई) के दौरान प्याज की कीमतों में गिरावट और शेष महीनों में कीमत तेज होने की प्रवृत्ति होती है।
- **समाधान:** कम उत्पादन वाले मौसम के दौरान उत्पादन को प्रोत्साहित करना; खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश करना; बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से उत्पादन की बर्बादी को कम करना आदि।
- **मौजूदा कदम:** एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH); कृषि विपणन अवसंरचना (AMI); बफर के लिए किसानों से प्याज की सीधी खरीद; ऑपरेशन ग्रीन्स; किसान रेल आदि।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

- भारत में **पेट्रोलियम उत्पादों** की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों की कीमतों से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए **तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG)** की कीमतें सऊदी अनुबंध मूल्य (CP) पर आधारित हैं। यह एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के लिए बेंचमार्क है।

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में रुझान

- जैसा कि पहले चर्चा की गई है, **थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति** ने एक **बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई है**। यह चालू वित्त वर्ष के दौरान उच्च रही। वर्ष 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान इसने 12.5% के उच्च स्तर को प्राप्त किया। यह निम्नलिखित से प्रेरित रही:
 - कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उप समूह में मुद्रास्फीति बहुत अधिक रही। यह दिसंबर 2021 में 55.7% थी।
 - खनिज और बुनियादी धातुओं के विनिर्माण में भी मुद्रास्फीति देखी गई।
 - विनिर्मित खाद्य उत्पादों में 36.4% के साथ खाद्य तेलों का प्रमुख योगदान था।

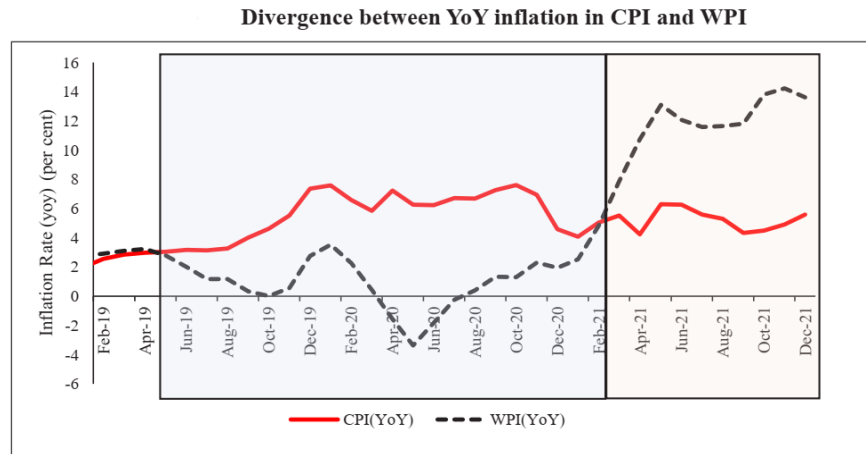
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति दरों के बीच विचलन

- WPI और CPI-C पर आधारित सलाना मुद्रास्फीति दर में जून 2019 से विचलन दर्ज किया गया है। इसमें WPI मुद्रास्फीति फरवरी 2021 तक खुदरा मुद्रास्फीति से कम रही। यह मई 2020 में 9.6 प्रतिशत अंक तक पहुंच गई।

- इस वर्ष दिसंबर 2021 में, थोक मुद्रास्फीति की तुलना में खुदरा मुद्रास्फीति में 8.0 प्रतिशत अंक की गिरावट होने से विचलन की प्रवृत्ति उलट गई।

- विचलन एवं WPI मुद्रास्फीति के CPI मुद्रास्फीति से अधिक होने के कारण:

- आधार प्रभाव के कारण भिन्नताएं: WPI का आधार कम होना, जबकि CPI मुद्रास्फीति उच्च बनी रही।



Source: NSO, MoSPI and OEA, DPIIT

- उद्देश्य और डिजाइन में अवधारणात्मक भिन्नता: CPI खुदरा स्तरों पर मूल्य संचलन को दर्शाता है, जबकि WPI थोक लेनदेन (फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल) का प्रतिनिधित्व करता है।
- वस्तुओं और विशेष वस्तुओं की भारिता में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ: CPI में, खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश सबसे अधिक (45.9) होता है, जबकि WPI में विनिर्मित समूह का भारांश सबसे अधिक (64.2) तथा खाद्य पदार्थों का भारांश 24.4 होता है। इसी तरह, CPI में ईंधन का भारांश 6.8 है, जबकि WPI में इसका भारांश 13.2 है आदि।
- मांग में कमी: वर्ष 2021-22 में उत्पादन धीरे-धीरे बढ़कर महामारी पूर्व स्तर तक पहुंचने की ओर अग्रसर हुआ है। लेकिन खपत की मांग अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है।
- WPI में आधार प्रभाव के धीरे-धीरे कम होने से, WPI और CPI मुद्रास्फीति के बीच अंतर कम होने की उम्मीद है।

वैश्विक कमोडिटी की कीमतें और घरेलू मुद्रास्फीति

कमोडिटी	वैश्विक मूल्य रुझान	प्रमुख कारण	घरेलू मुद्रास्फीति सहसंबंध (WPI के माध्यम से मापन किया जाता है)
एल्युमिनियम	वृद्धि	मांग में वृद्धि बनाम चीन (प्रमुख निर्यातक) से उत्पादन में कमी।	सकारात्मक और उच्च सहसंबंध
कॉपर	वृद्धि	मांग में वृद्धि बनाम चिली और पेरू की घटती निर्यात सूची तथा हड़ताल के खतरे।	सकारात्मक और उच्च सहसंबंध
कच्चा तेल	वृद्धि	मांग में वृद्धि बनाम ओपेक+ द्वारा उत्पादन में कटौती।	सकारात्मक और उच्च सहसंबंध
कपास	वृद्धि	कोविड -19 के बाद मांग में सुधार।	सकारात्मक और उच्च सहसंबंध

आवास की कीमतें

- कोविड -19 के कारण मांग और आपूर्ति में उल्लेखनीय गिरावट के बाद, मांग में वृद्धि तथा सामर्थ्य बढ़ाने के सरकारी उपायों के कारण आवास संपत्तियों की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- महामारी की दूसरी लहर के दौरान आवासीय संपत्तियों की बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण

- सस्ती दरों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सरकार औषध विभाग (DOP) के एक संलग्न कार्यालय राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण⁶⁹ के माध्यम से दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है।
- कोविड -19 पहलें:
 - वितरक हेतु मूल्य⁷⁰ स्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर व्यापार लाभ को अधिकतम 70% तक सीमित करना।

⁶⁹ National Pharmaceutical Pricing Authority: NPPA

⁷⁰ Price to Distributor: PTD

- पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर पर अधिकतम व्यापार लाभ को सीमित करना।
- कोविड प्रबंधन हेतु अनुसूचित दवाओं की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करना और कोविड के लिए कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं, जैसे- रेमेडीजविर पर निर्माताओं/विपणकों से मूल्य में स्वैच्छिक कमी का आह्वान करना आदि।
- रेमेडीजविर, टोसिलिजुमैब और अम्फोटेरिसिन आदि के समान वितरण की निगरानी एवं समन्वय के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण।

आपूर्ति पक्ष कारकों के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य

- भारत में मुद्रास्फीति के निर्धारण में आपूर्ति पक्ष कारकों की प्रबलता है। इसी कारण यह सर्वेक्षण मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिए कुछ दीर्घकालिक नीतियों का सुझाव देता है।
- **लाभ:**
 - **उत्पादन पैटर्न बदलना:** यह दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। फसलों का विविधीकरण करेगा। इसके अतिरिक्त, चावल एवं गेहूं का वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बफर स्टॉक बनाए रखने में सरकार की मदद करेगा।
 - **पहले:** उपज क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से दलहन और तिलहन उत्पादन को प्राथमिकता। उच्च उत्पादकता किस्मों (HYVs), न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समर्थन और खरीद के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना।
 - **कैलिब्रेटेड (अंशशोधित) आयात नीति:** दीर्घकालिक सुसंगत दृष्टिकोण से घरेलू उत्पादकों को गलत संकेत भेजे जाने और अनिश्चितता का परिवेश बनने से बचने में मदद मिलेगी।
 - **पहले:** दालों के आयात पर म्यांमार, मलावी और मोजाम्बिक के साथ 5-वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
 - **जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए परिवहन और भंडारण संबंधी बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाना:** बेहतर भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला से कम उपज वाले मौसम में उपलब्धता; उपज की कम बर्बादी, संकटपूर्ण बिक्री से बचाव और मौसमी उपभोक्ता मूल्य वृद्धि में कमी सुनिश्चित हो सकेगी।
 - **पहले:** ऑपरेशन ग्रीन्स, किसान रेल आदि।



शब्दावली	
मुद्रास्फीति	यह अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि को प्रदर्शित करती है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) या खुदरा मुद्रास्फीति	इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी किया जाता है। CPI, घरेलू खपत पैटर्न के आधार पर खुदरा स्तर पर मूल्य में बदलाव को दर्शाता है।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI)	इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), द्वारा जारी किया जाता है। WPI आधारित मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था में बिक्री के पहले बिंदु पर कुल थोक लेन-देन में संबंधित वस्तुओं की हिस्सेदारी पर आधारित होती है।

अध्याय एक नज़र में	
●	प्रभावी आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी हुई है। हेडलाइन CPI-संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-दिसंबर) में घटकर 5.2% हो गई।
●	थोक मुद्रास्फीति (WPI पर आधारित) में 12.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि देखी गई। इसका श्रेय निम्न आधार, आर्थिक गतिविधियों में तेजी और कच्चे तेल, खाद्य तेलों आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को दिया जाता है।

- WPI और CPI-C के बीच का अंतर मई 2020 में विचलन में उलटफेर के साथ 9.6 प्रतिशत अंक तक पहुंच गया।
- दोनों सूचकांकों के बीच के विचलन को दोनों सूचकांकों के आधार प्रभाव के साथ-साथ दायरे, कवरेज, कवर की गई वस्तुओं आदि में अंतर जैसे कारकों द्वारा समझाया जा सकता है।
- सरकार ने आवास और औषध मूल्य निर्धारण के प्रबंधन के लिए भी हस्तक्षेप किया है।
- परिस्थिति की अस्थिरता बनी हुई है, ऐसे में भारत को मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता है।

अध्याय-5



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. रिफाईंड या परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 द्वारा रचित एक नवीन पदावली है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका निर्माण वाहनों के लिए केवल पेट्रोल और डीजल ईंधन मदों को, औसत खुदरा कोर मुद्रास्फीति से अलग करके किया गया है।
2. खुदरा मुद्रास्फीति में ईंधन के पर्याप्त प्रभाव के कारण परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति, पारंपरिक कोर मुद्रास्फीति से नीचे है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Q2. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सी.पी.आई. मुद्रास्फीति की तुलना में डब्ल्यू.पी.आई. मुद्रास्फीति के अधिक होने के निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारण है/हैं?

1. पिछले वर्ष का निम्न आधार
2. विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोला जाना
3. उनकी रूपरेखाओं में अवधारणात्मक अंतर

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1 और 2
- (b) 1, 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) केवल 1 और 3

Q3. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने घरेलू मुद्रास्फीति और वैश्विक पण्य कीमतों के सकारात्मक एवं उच्च सहसंबंध का प्रकटीकरण किया है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

- | पण्य | उच्च कीमतों का कारण |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. एल्युमीनियम | : चिली और पेरू में हड़ताल की धमकियां |
| 2. तांबा | : चीन से उत्पादन में कटौती |
| 3. कच्चा तेल | : ओपेक+ द्वारा उत्पादन घटाया जाना |
| 4. कपास | : कोविड के बाद बेहतर मांग |

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

- (a) केवल 3 और 4
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

Q4. निम्नलिखित निकायों में से कौन-सा डब्ल्यू.पी.आई. जारी करता है?

- (a) नीति आयोग
- (b) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.)
- (c) आर्थिक सलाहकार विभाग, वित्त मंत्रालय
- (d) आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

Q5. जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 में उल्लेख किया गया है, सरकार ने देश में मुद्रास्फीति को सीमित करने के लिए अग्रसक्रिय कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में, सरकार के निम्नलिखित में से किस कदम ने मुद्रास्फीति को सीमित करने के लिए कुशलता से कार्य किया है?

1. राज्यों द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर में कमी
2. बफर स्टॉक का निर्माण
3. ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार
4. निःशुल्क आयात श्रेणी में अधिक मदें

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. खुदरा मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा, चर्चा कीजिए कि विगत वर्ष से खुदरा मुद्रास्फीति के चालक कैसे बदल गए हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं।

Q2. डब्ल्यू.पी.आई. और सी.पी.आई. आधारित मुद्रास्फीति दरों के बीच विचलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, मुद्रास्फीति में अस्थिरता के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव
असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

- ✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for PRELIMS 2022: **27 Feb**

प्रारंभिक 2022 के लिए **27 फरवरी**

for PRELIMS 2023: **20 Feb**

प्रारंभिक 2023 के लिए **6 मार्च**

मुख्य

- ✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for MAINS 2022: **26 Feb**

मुख्य 2022 के लिए **26 फरवरी**

for MAINS 2023: **27 FEB**

मुख्य 2023 के लिए **27 फरवरी**

Scan the QR CODE to
download **VISION IAS** app



अध्याय 6: संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन (Sustainable Development and Climate Change)

परिचय

- इस अध्याय में **सतत विकास लक्ष्यों**⁷¹ को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इसके लिए 'नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड' 2020-21 के निष्कर्षों का उपयोग किया गया है।
- गौरतलब है कि इस अध्याय में भारत में भूमि, जल और वायु के संबंध में पर्यावरणीय स्थिति की समीक्षा की गई है। साथ ही, भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, प्रगति और चुनौतियों का भी अध्ययन किया गया है।
- इसमें, संधारणीय वित्तपोषण के क्षेत्र में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर भी चर्चा की गई है।

सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

- वर्ष 2015 में भारत समेत 193 देशों ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। इन लक्ष्यों का विस्तृत विवरण संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव, "हमारी दुनिया का कायाकल्प: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा"⁷² में है।
- SDGs के तहत **17 लक्ष्य और 169 संबद्ध लक्ष्य**⁷³ शामिल हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को व्यापक रूप से कवर करते हैं। ये सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों⁷⁴ के आधार पर निर्मित हैं, जो वर्ष 2000 से 2015 तक की पंद्रह-वर्ष की अवधि को शामिल करते हैं।
- सहस्राब्दी विकास शिखर सम्मेलन, 2000** में 'MDGs की संकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य बेहतर स्त्री-पुरुष समानता, बेहतर विकास और विश्व को गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों आदि के अभिशाप से मुक्ति दिलाना था। इसके अलावा समान संवृद्धि और सतत विकास को अर्जित करने से संबंधित लक्ष्यों की भी संकल्पना की गई थी।

सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की प्रगति

नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड 2020-21, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाता है।

- यह SDG की प्रगति की दिशा में **विश्व का पहला** सरकारी उप राष्ट्रीय उपाय है।
- इसे **2018 से वार्षिक रूप से** प्रकाशित किया जा रहा है।
- नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स (2020-21) का तीसरा संस्करण प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए **16 SDGs पर लक्ष्यवार स्कोर** की गणना करता है और लक्ष्य

17 के गुणात्मक मूल्यांकन की गणना करता है।

- कुल मिलाकर, समग्र प्रदर्शन की माप के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 SDGs में प्रदर्शन के आधार पर इन्हें **0-100 के बीच स्कोर** दिए जाते हैं।

राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों का उनके स्कोर के आधार पर वर्गीकरण

नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के लाभ



राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक-दूसरे से सीखने में सक्षम बनाता है



सांख्यिकीय प्रणालियों में व्याप्त कमियों को उजागर करता है



प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद संबंधी नीति आयोग के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

स्कोर

श्रेणी

100

प्राप्तकर्ता (Achiever)

65-99

अग्रणी (Front Runner)

50-64

प्रदर्शनकर्ता (Performer)

0-49

आकांक्षी (Aspirant)

⁷¹ Sustainable Development Goals: SDGs

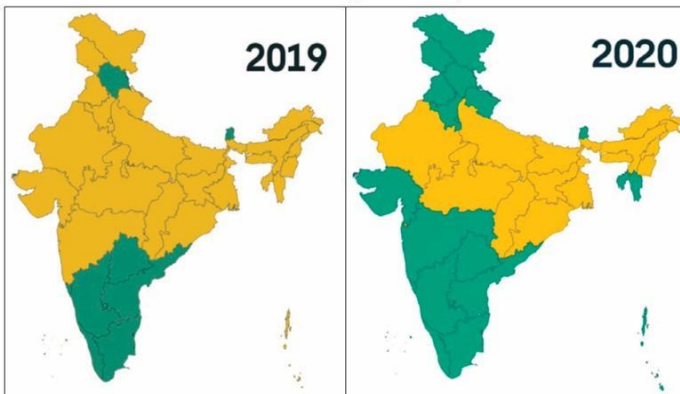
⁷² Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

⁷³ 17 Goals and 169 associated targets

⁷⁴ Millennium Development Goals: MDGs

नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स का विकास

बेसलाइन रिपोर्ट: 2018	द्वितीय संस्करण (V 2.0) रिपोर्ट: वर्ष 2019-20	बेसलाइन रिपोर्ट: 2018
13 लक्ष्य	16 लक्ष्य + लक्ष्य क्रमांक 17 पर गुणात्मक विश्लेषण	16 लक्ष्य + लक्ष्य क्रमांक 17 पर गुणात्मक विश्लेषण
39 टारगेट	54 टारगेट	70 टारगेट
62 संकेतक	100 संकेतक	115 संकेतक
राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की लक्ष्य-वार रैंकिंग	राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की लक्ष्य-वार रैंकिंग + राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों की प्रोफाइल	राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की लक्ष्य-वार रैंकिंग + राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों की प्रोफाइल
नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) से पहले	NIF के साथ व्यवस्थित / संरेखित: 68 संकेतक पूरी तरह से संरेखित; 20 संशोधित रूप से, और SGD के लक्ष्य 12, 13 एवं 14 को कवर करने हेतु 12 नये संकेतक	NIF के साथ संरेखित: 76 संकेतक पूरी तरह से संरेखित, 31 संशोधित रूप से और 8 संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से शामिल किए गए

मापदंड	उपलब्धियाँ
भारत का समग्र रूप से प्रदर्शन	- भारत का समग्र स्कोर, जो 2018-19 में 57 और 2019-20 में 60 था, 2020-21 में बढ़कर 66 हो गया है। - भारत ने 15 SDGs में से 8 में अच्छा प्रदर्शन किया है- 
राज्यों का प्रदर्शन	- फ्रंट रनर/अग्रणी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 2020-21 में बढ़कर 22 हो गई है, जो 2019-20 में 10 थी। (इन्फोग्राफिक्स देखें..) - अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश परफॉर्मर (निष्पादक) रहे। - सर्वाधिक स्कोर वाले 3 राज्य: केरल (75), तमिलनाडु (74), हिमाचल प्रदेश (74) - सबसे कम स्कोर वाले राज्य: बिहार (52), झारखंड (56), असम (57) - मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड, 2019 के स्कोर में सुधार के मामले में 2020-21 में शीर्ष स्थान पर रहे। Performance of States/UTs on the NITI Aayog SDG India Index (2019 and 2020)  Source: NITI Aayog Note: Yellow indicates Performer (Score 50-64), Green indicates Front Runner (Score 65-99)

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन	- आठ केंद्र शासित प्रदेशों में से सात अग्रणी श्रेणी में है। इस श्रेणी में शीर्ष पर चंडीगढ़ है जिसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हैं। - दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव परफॉर्मर श्रेणी में है।
SDG 14 पर प्रदर्शन (जलीय जीवों की सुरक्षा)	- तटीय राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश (अग्रणी) हैं, और तमिलनाडु ने सबसे कम स्कोर हासिल किया है। - SDG 14 के लिए केवल नौ तटीय राज्यों का स्कोर निकाला जाता है- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल।
पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रदर्शन	District-wise overall performance on the NITI Aayog NER District SDG Index 2021-22

पर्यावरण की स्थिति

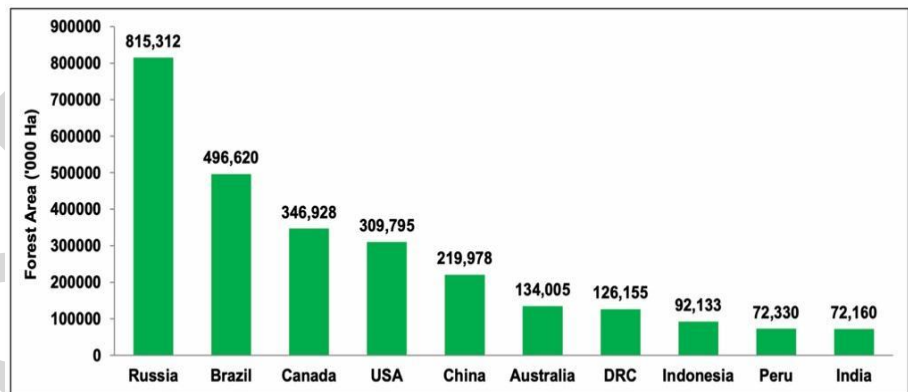
वन भूमि

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2021 के निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत ने पिछले दशक में अपने वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

वैश्विक स्थिति

- वैश्विक रैंकिंग: वर्ष 2020 में, भारत वन क्षेत्र के हिसाब दुनिया का दसवाँ सबसे बड़ा देश था।
- वन क्षेत्र: 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% हिस्सा वनाच्छादित था, जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है।
- वन में वृद्धि: भारत को 2010 से 2020 के बीच में वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि के लिए वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। इस अवधि के दौरान भारत में प्रत्येक वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्र

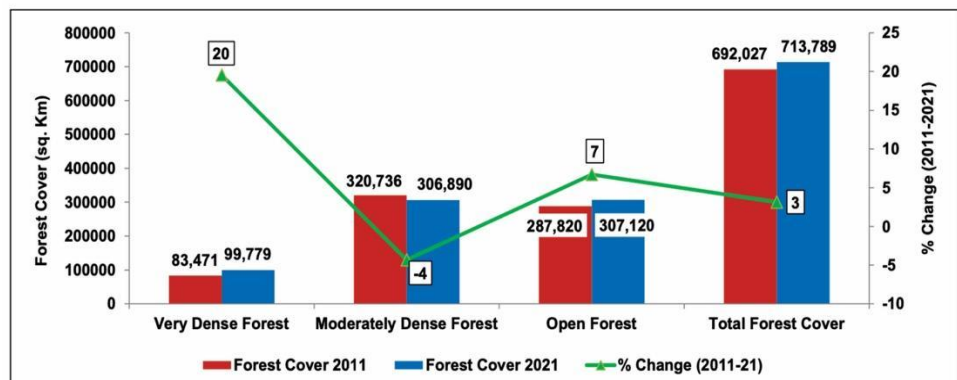
Top Ten Countries by Forest Area in 2020



Source: India State of Forest Report 2021

Note: DRC: Democratic Republic of the Congo

Forest Cover of India (2011 and 2021)



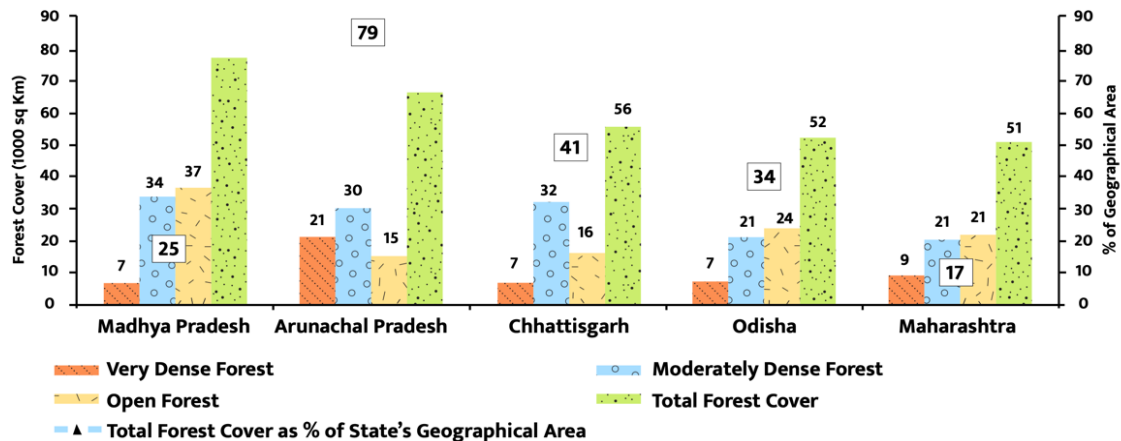
Source: India State of Forest Report 2021 and 2011

जुड़ा है।

घरेलू उपलब्धियाँ और निष्कर्ष

- **वन आवरण में वृद्धि:** भारत का कुल वन क्षेत्र वर्ष 2011 में देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.05 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2021 में 21.71 प्रतिशत (3.14% वृद्धि) हो गया है।
- यह वृद्धि मुख्य रूप घने जंगल में वृद्धि के कारण है। खुले जंगल में भी सुधार हुआ है, परंतु मध्यम घने जंगल में गिरावट आई है।
- **राज्यवार प्रदर्शन**

Top Five States in India by Forest Cover; 2021



प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और एकल उपयोग वाली चिन्हित प्लास्टिक का उन्मूलन

हालिया कार्रवाईयाँ

लक्ष्य: वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर चरणबद्ध प्रतिबंध।

- **2021 में घरेलू नियामक कार्रवाईयाँ:**
 - **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021:** इसके तहत 2022 तक एकल उपयोग वाली चिन्हित प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी उपयोगिता कम होती है और इनसे अधिक कचरा उत्पन्न होने की संभावना होती है।
 - 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है।
 - **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार,** पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के ऐसे कचरे जिन्हें 'चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं' के चरणबद्ध खात्मे के तहत शामिल नहीं किया गया है, उनका संग्रहण और प्रबंधन पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीके से करना होगा। ऐसा, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (PIBO) के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत किया जाएगा।
 - **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए दिशा-निर्देश** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के माध्यम से कानूनी शक्ति प्रदान की गई।
 - **प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर विनियम का मसौदा** अधिसूचित किया गया। इसमें कई प्रस्ताव दिए गए हैं, जैसे- पुनः उपयोग, अपशिष्ट की पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर, पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग आदि को अनिवार्य बनाना।
- **एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदम-**
 - सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एक विशेष कार्य बल गठित करने का अनुरोध किया गया।
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यबल गठित किया गया जिसमें समन्वित प्रयास हेतु सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सदस्यों को शामिल किया गया है।
- **अन्य कदम**
 - **संशोधित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016,** विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और निर्यात उन्मुख इकाइयों द्वारा देश में चिन्हित प्लास्टिक कचरे के आयात को विनियमित करते हैं।

- 2019 में संपन्न चौथे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव, “एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद के प्रदूषण का निपटान” को भारत द्वारा संचालित किया गया।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन।

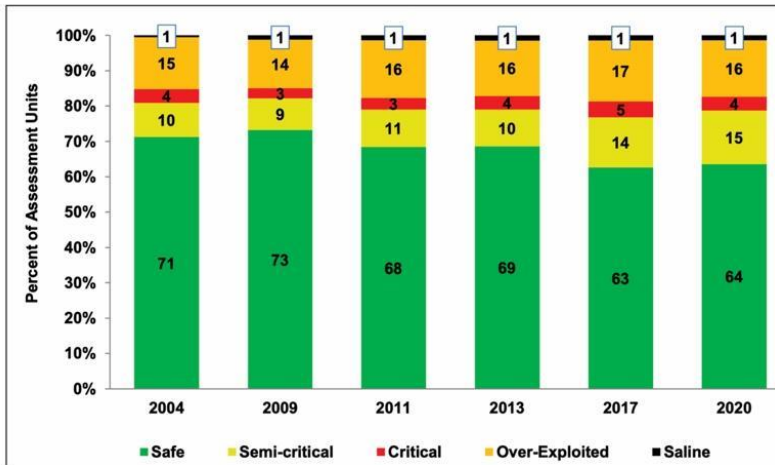
जल

भूजल: असतत निकासी के कारण खतरा उत्पन्न।

- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूजल संसाधन के मूल्यांकन के अनुसार, 2004-2020 के दौरान भारत में वार्षिक भूजल निष्कर्षण 58-63% की सीमा में रहा है।
- उत्तर-पश्चिम और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है।

विभिन्न भूजल मूल्यांकन मात्रकों के अनुसार भूजल निष्कर्षण की सीमा:

Categorization of Ground Water Resource Assessment Units (2004-2020)



Categorisation of ground water assessment units (blocks/ taluks/ mandals/ tehsil/ firkas etc.)	
Criteria	Category
Stage of Extraction (SoE) less than 70 %	Safe
SoE in the range of 70 % to 90 %	Semi-critical
SoE in the range of 90 % to 100 %	Critical
SoE greater than 100 %	Over-exploited
Unit in which the ground water resources are entirely saline	Saline

Source: National Compilation on Dynamic Ground Water Resources of India, 2020

जलाशय: मौसमी तत्वों पर निर्भर और वर्षाजल तथा तापमान पैटर्न से बहुत अधिक प्रभावित।

- मानसून के दौरान जल का भंडारण अपने चरम पर, जबकि गर्मी के महीनों में यह सबसे कम होता है। इसलिए जलाशय के भंडारण, जल निकासी तथा उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक योजना तैयार करने और समन्वय की आवश्यकता होती है।

नदियाँ: नमामि गंगे मिशन (NGM)

- लक्ष्य: गंगा नदी बेसिन की रक्षा, संरक्षण और पुनरुद्धार करना।

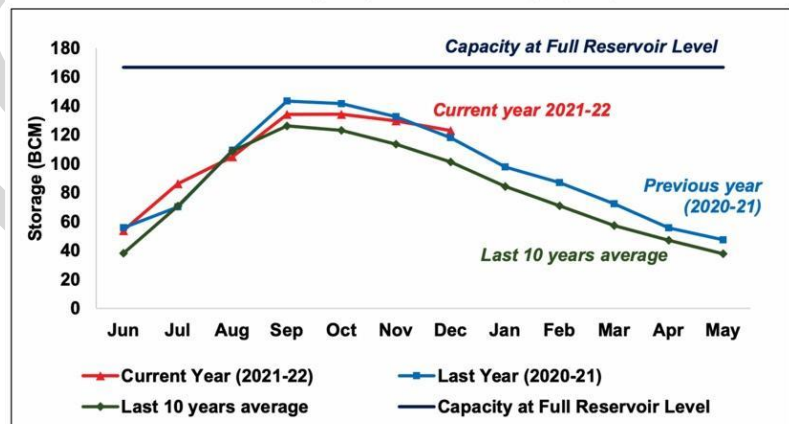
• प्रमुख उपलब्धियाँ:

- 2014: देश के निवासियों, NRI/PIO, कॉर्पोरेट्स और संगठनों से प्राप्त योगदान से स्वच्छ गंगा कोष (CGF) की स्थापना की गई।
 - CGF के तहत प्राप्त कुल धन (31 दिसंबर, 2021 तक): 561.58 करोड़ रुपये
- 2015: पांच साल की अवधि (2015-2020) के लिए मिशन को स्वीकृत
- 2016: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया। यह नमामि गंगे की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

नमामि गंगे के 4 स्तंभों के तहत उठाए गए कदम और उपलब्धियाँ

निर्मल गंगा (अप्रदूषित प्रवाह)	• 5,024 एमएलडी (2014 में 28 परियोजनाओं के माध्यम से 463 एमएलडी से दस गुना वृद्धि) की संचयी उपचार क्षमता का निर्माण करने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक 160 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। • गंगा नदी के किनारे घोर प्रदूषणकारी उद्योगों (Grossly Polluting Industries: GPIs) की नियमित
--------------------------------	---

Reservoir capacity and live storage (bcm)



Source: India Water Resources Information System, Ministry of Jal Shakti

	निगरानी के कारण- ○ अपशिष्ट निर्वहन में कमी आई है। ○ GPI की अनुपालन स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 2017 में यह 39 प्रतिशत थी, जो 2020 में 81 प्रतिशत हो गया है।
अविरल प्रवाह (निरंतर प्रवाह)	● गंगा के न्यूनतम प्रवाह को अनिवार्य करने वाली अधिसूचना 2016 में जारी। ● 29,000 हेक्टेयर का वनीकरण। ● गंगा नदी के मुख्य धारा के लिए अपनी तरह का पहला नदी जैव-विविधता मूल्यांकन। ● संरक्षण के लिए 279 आर्द्रभूमियों की पहचान। ● 118 आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार की गई।
जन गंगा (पीपल-रिवर कनेक्ट)	● गंगा क्रेस्ट 2021. ● गंगा उत्सव 2021 को पहली बार, गंगा बेसिन शहरों से परे नदी उत्सव के रूप में मनाया गया। ● 2021 में रिवर सिटी अलायंस को शुरू किया गया।
ज्ञान गंगा (अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन)	● एनएमसीजी की सहायता के लिए गंगा ज्ञान केंद्र की स्थापना। ● बेसिन के दीर्घकालीन अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास के लिए आई.आई.टी. कानपुर में गंगा प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई।

वायु

प्रमुख हस्तक्षेप

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP):** इसका लक्ष्य वर्ष 2017 को आधार वर्ष के रूप में लेते हुए, वर्ष 2024 तक देश भर में पार्टिकुलेट मैटर (PM) यानी कणिका कण सांद्रता में 20-30 प्रतिशत की कटौती करना है।
- **विस्तार:** यह कार्यक्रम 132 शहरों में लागू किया गया है। इसमें दस लाख से अधिक आबादी वाले ऐसे 34 शहर/शहरी समूह शामिल हैं, जिन्हें पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) द्वारा पहचान मिली। इसके अलावा, यह दस लाख से अधिक आबादी वाले आठ अन्य शहरों को भी शामिल करता है, जो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान पाने हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत आते हैं।

स्रोत के अनुसार पहल			
वाहन से उत्सर्जन	औद्योगिक उत्सर्जन	घूल और कूड़ा जलाने से वायु प्रदूषण	आस-पास के वायु की गुणवत्ता की निगरानी
○ ईंधन और वाहनों के लिए BS-IV से सीधे BS-VI मानदंडों को लागू किया गया। ○ सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ावा। ○ पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण, सी.एन.जी., और एल.पी.जी. जैसे तुलनात्मक रूप से स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना। ○ फेम (FAME) योजना के चरण- II को लागू करना।	○ कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड लागू करना। ○ आयातित पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। ○ अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी उपकरण स्थापित किए गए हैं। ○ ईट भट्टों में जिग-जैग तकनीक का उपयोग करना।	○ ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-विकल्पा अपशिष्ट, निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को कवर करते हुए छह अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाए गए हैं। ○ प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। ○ बायोमॉस / कचरा जलाने पर प्रतिबंध।	○ राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम जैसी योजनाओं के तहत वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार किया गया है। ○ दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में वायु गुणवत्ता से संबंधित पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गयी है।

दिल्ली/एनसीआर में वायु प्रदूषण में गिरावट के लिए प्रमुख उपाय

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग की स्थापना।
 - पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 'फसल अवशेषों के इन-सीटू (स्व-स्थाने) प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने' के लिए केंद्र सरकार की योजना।
 - 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध।
 - एक्सप्रेसवे और राजमार्गों को शुरू किया गया।
 - लाल श्रेणी में आने वाले उद्योगों में औद्योगिक उत्सर्जन और बहिःस्राव प्रणालियों की ऑनलाइन निगरानी तंत्र की स्थापना।
- वायु प्रदूषण को कम करने से जुड़ी उपलब्धियाँ**
- वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 96 शहरों में PM10 सांद्रता की घटती प्रवृत्ति को देखा गया।

- निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (PM10, 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम) के भीतर शहरों की संख्या वर्ष 2019-20 के 18 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 27 हो गई।
 - हालाँकि, 36 शहरों में 2019-2020 की तुलना में 2020-2021 में PM10 सांद्रता में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।
- दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार: 2016 के बाद से PM की वार्षिक सांद्रता में धीरे-धीरे कमी आई है, वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2021 में PM2.5 में लगभग 22 प्रतिशत की कमी और PM10 में 27 प्रतिशत की कमी देखी गई।

जलवायु परिवर्तन

NAPCC के तहत प्रमुख विकास

मिशन	प्रमुख उद्देश्य/लक्ष्य	प्रगति
राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM)	2014-15 से शुरू होकर सात वर्षों में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करना।	49.35 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता (दिसंबर 2021 तक) स्थापित की जा चुकी है।
संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMEEE)	- बड़े ऊर्जा खपत वाले उद्योगों में ऊर्जा खपत में कमी अनिवार्य करना। - नगरपालिका, भवनों और कृषि क्षेत्रों में मांग-पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा खपत को कम करने के लिए PPP हेतु वित्त पोषण करना। - ऊर्जा दक्ष उपकरणों पर कर को कम करते हुए ऊर्जा प्रोत्साहन प्रदान करना।	- PAT के पहले चक्र (2012-2015) के परिणामस्वरूप 8.67 मिलियन टन तेल समतुल्य (MTOE) की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई। - PAT के दूसरे चक्र (2016-17 से 2018-19) में 14.08 MTOE की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई। - PAT के तीसरे चक्र III के परिणाम प्रतीक्षित हैं और PAT के चौथे चक्र का कार्यान्वयन प्रगति में है।
हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (GIM)	वन/वृक्षों के आच्छादन को 5 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाकर और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर पर वनावरण की गुणवत्ता में सुधार करके पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार किया गया।	1,17,757 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण गतिविधियाँ शुरू की गईं।
राष्ट्रीय संधारणीय आवास मिशन (NMSH)	- स्थायी आवास मानकों का विकास। - मौजूदा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) का विस्तार करके शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देना। - ऑटोमोटिव ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों के प्रवर्तन को मजबूत करना। - ऊर्जा की बचत वाली गाड़ियाँ खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य निर्धारण उपायों का इस्तेमाल करना और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देना।	- इस मिशन को कई कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन। - स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2019 शुरू किया गया है। - शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को कार्यान्वित किया जाएगा। 100 किलोवाट या उससे अधिक भार वाले व्यावसायिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन नियम 2018 अनिवार्य कर दिया गया है।
राष्ट्रीय जल मिशन (NWM)	- भूजल की निगरानी, जलभृत मानचित्रण, क्षमता निर्माण, जल-गुणवत्ता की निगरानी और अन्य आधारभूत अध्ययनों पर ध्यान दिया जाता है। - अतिशोषित क्षेत्रों पर ध्यान देना। - बेसिन-स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन आदि को बढ़ावा देना।	- केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा 15640 भूजल प्रेक्षण कुओं की निगरानी की जा रही है। - पांच राज्यों ने जल क्षेत्रक के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना (SSAP) का पहला चरण पूरा कर लिया है।
संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन	कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु अनुकूल बनाकर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना।	जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित राष्ट्रीय नवाचार का निर्माण, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नेटवर्क परियोजना है।

हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को संपोषित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन	- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का निरंतर मूल्यांकन करना। - नीति निर्माता निकायों को नीति निर्माण कार्यों में सक्षम बनाना। - हिमानी विज्ञान (ग्लेशियोलोजी) में पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग।	- हिमानी विज्ञान में इंडो-स्विस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत हिमानी वैज्ञानिकों (Glaciologists) को प्रशिक्षित किया गया। - हिमालयी क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन पर 4 विश्वविद्यालयों के एक अंतर विश्वविद्यालय संघ का गठन किया गया। - सिक्किम के लिए भेद्यता मूल्यांकन हेतु हिमनद झील विस्फोट बाढ़ अनुसंधान और विकास अध्ययन आयोजित किये गए हैं।
जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (NMSKCC)	जलवायु विज्ञान की बेहतर समझ हासिल करने के लिए, अनुसंधान और विकास में कार्यरत मौजूदा ज्ञान संस्थानों के बीच ज्ञान नेटवर्क का निर्माण आदि।	12 में से 11 हिमालयी राज्यों में और 11 गैर-हिमालयी राज्यों में राज्य जलवायु परिवर्तन सेल स्थापित किये गए हैं। 6 प्रमुख संस्थान अब जलवायु परिवर्तन विज्ञान, प्रभाव और अनुकूलन पर प्रशिक्षण करवाते हैं।

अन्य प्रमुख पहलें और उपलब्धियाँ

- एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम (CCAP) को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।
- वर्ष 2015-19 तक जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) के तहत 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन: परिवहन ईंधन के साथ-साथ रिफाइनरियों के लिए एक औद्योगिक आगत के रूप में उपयोग के लिए, हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिश्रित किया जा रहा है।
- 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य: सितंबर 2021 तक 8.5 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
- भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया: इस पहल में शामिल हैं-
 - दिसंबर 2023 तक नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण।
 - रिजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए तीन चरणों वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग।
 - नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (133.26 मेगावाट सौर तथा 103 मेगावाट पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता) का उपयोग।
 - सभी रेलवे प्रतिष्ठानों आदि पर एलईडी लाइट की व्यवस्था।
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम): दिसंबर, 2021 तक 77000 से अधिक स्टैंड अलोन सोलर पंप, 25.25 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र और 1026 से अधिक पंपों को सौर ऊर्जा से चलने योग्य (सोलराइज़) बनाया गया।
 - आरबीआई ने वित्त की उपलब्धता को सरल बनाने के लिए अपने घटकों को 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशानिर्देशों' (Priority Sector Lending Guidelines) के तहत शामिल किया है।
- अन्य सौर ऊर्जा पहलें
 - सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास: 14 राज्यों में 33.82 गीगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है।
 - रूफ टॉप सौर कार्यक्रम चरण- II: कुल 5.87 गीगावाट सोलर रूफ टॉप परियोजनाएँ स्थापित की गईं।
 - सरकारी संस्थाओं द्वारा 12 गीगावाट ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी पावर परियोजनाएँ स्थापित करने की योजना के तहत लगभग 8.2 गीगावाट की परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं।
 - सौर स्ट्रीट लाइट, सौर अध्ययन लैंप आदि के लिए ऑफ-ग्रिड सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम का चरण-III
- अपतटीय पवन ऊर्जा नीति और पवन-सौर हाइब्रिड नीति की अधिसूचना: लगभग 4.25 गीगावाट पवन-सौर हाइब्रिड की क्षमता प्रदान की गई है।

COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन, ग्लासगो में लिए गए प्रमुख निर्णय

- भारत ने विकासशील देशों के लिए पर्याप्त समय सीमा के साथ न्यायसंगत परिवर्तन की मांग की ताकि हरित अर्थव्यवस्था के लाभ सभी के साथ साझा किये जा सकें।

- "पेरिस रूल बुक" के सभी लंबित मामलों से संबंधित परिणामों को अपनाया गया, जिसमें बाजार तंत्र, पारदर्शिता और NDCs के लिए सामान्य समय-सीमा शामिल हैं।
- वित्त संबंधी स्थायी समिति (UNFCCC के तहत एक तकनीकी समिति) को जलवायु वित्त की परिभाषा तय करने का अधिकार दिया गया।
- ग्लासगो जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो अनुकूलन, शमन, वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, हानि और क्षति पर जोर देता है।
- अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्य पर दो वर्षीय ग्लासगो-शर्म अल-शेख कार्य कार्यक्रम का शुभारंभ।
- जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान और क्षति की भरपाई के तरीकों का पता लगाने के लिए, नुकसान और क्षति पर पक्षकारों, संबंधित संगठनों और हितधारकों के बीच ग्लासगो वार्ता की व्यवस्था की गई।
- पूर्व 2030 महत्वाकांक्षा पर वार्षिक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय राउन्ड टेबल बैठक बुलाई गई, जो पेरिस समझौते की पार्टियों की बैठक के रूप में सेवारत पार्टियों के सम्मेलन (कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिस) के चौथे सत्र से शुरू हुई।

भारत और इसका राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)

- भारत के प्रधान मंत्री ने उत्सर्जन में अधिक कमी लाने के लिए 2030 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने की घोषणा की।
- उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी संस्थागत फ्रेमवर्क के तौर पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति (AIPA) की स्थापना की गई। यह समिति एक समन्वित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में भारत की प्रगति

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)	प्रगति
वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में सकल घरेलू उत्पाद का 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना।	2005-2016 की अवधि में, भारत ने अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 24 प्रतिशत तक कम किया है।
2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO ₂ के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।	2019 में किये गए अंतिम आकलन के मुकाबले, वनों में कार्बन भंडार में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा की क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, दिसंबर 2021 तक विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 40.20 प्रतिशत थी।

संधारणीय विकास के लिए वित्त

जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों से निपटना

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने विनियमन विभाग के अंदर एक नई इकाई 'संधारणीय वित्त समूह' (SFG) का गठन किया है। यह समूह स्थायी वित्त और जलवायु जोखिमों के क्षेत्रों में नियामक पहल का नेतृत्व करेगा।
- आरबीआई एक परामर्शी चर्चा पत्र तैयार कर रहा है, ताकि जलवायु जोखिम के प्रबंधन में अपनी विनियमित संस्थाओं की प्रगति का आकलन कर सके।

संधारणीय विकास के लिए वित्त संवर्द्धन

- भारत में संधारणीय वित्त का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संधारणीय वित्त पर कार्य बल का गठन किया गया।
- 2021 में आरबीआई वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क (NGFS) में सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है।
- आरबीआई के उदारीकृत बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) मानदंडों ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों और अन्य फर्मों को हरित बॉन्ड और टिकाऊ बॉन्ड के माध्यम से वित्त जुटाने में मदद की।
- द्विपक्षीय और वैश्विक संधारणीय वित्त पहल: आरबीआई, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा स्थापित 'जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर गठित कार्य बल' और 'सतत वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय मंच' का एक सदस्य है।

संघारणीय विकास के लिए तन्त्रकता में निवेश

- सेबी ने संघारणीयता की रिपोर्टिंग से जुड़ी नई शर्तें जारी की हैं। ये शर्तें, व्यावसायिक जवाबदेहिता और संघारणीयता रिपोर्ट (BRSR) के अनुसार जारी की गई हैं। यह मौजूदा व्यावसायिक जवाबदेहिता रिपोर्ट (BRR) को प्रतिस्थापित करेगी।
 - यह वित्त वर्ष 2022-23 से अनिवार्य रूप से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण के हिसाब से) पर लागू होंगी। संस्थाएँ इसे वित्त वर्ष 2021-22 से स्वैच्छिक आधार पर अपना सकती हैं।
 - इससे, ESG संबंधित सूचनाओं को प्रकट किया जा सकेगा और बाजार के भागीदार इसकी मदद से संघारणीयता से जुड़े जोखिमों और अवसरों की पहचान तथा आकलन कर सकेंगे। इससे, अधिक पारदर्शिता आएगी।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पहलें

लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट (Lifestyle for Environment: LIFE)	• ग्लासगो में COP 26 में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा वन वर्ड मूवमेंट के तौर पर इसे प्रस्तावित किया गया था। • इसमें, पर्यावरण के लिए जीवनशैली को एक अभियान और एक सामूहिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की कल्पना की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा देना है जिससे कई क्षेत्रों और विविध क्षेत्रों, जैसे- मत्स्य पालन, कृषि, वेलनेस (स्वास्थ्य संबंधी), आहार आदि में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकें।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)	हाल ही की प्रगतियों में शामिल है- • ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स समिट में ग्रीन ग्रिड पहल-वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (GGI-OSOWOG) का शुभारंभ। • संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया। • COP26 में UNFCCC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ताकि पेरिस समझौते के तहत संबंधित NDCs के लिए एक रोडमैप तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए ISA की सदस्यता लेने में सहायता मिल सके।
कोलिऐशन फॉर डिजास्टर रेज़िलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI)	• 2019 में इसके शुभारंभ के बाद से 28 देश और 7 बहुपक्षीय संगठन इसके सदस्य बने हैं। • CDRI के तहत शुरू की गई हालिया पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं- ○ भारत, ब्रिटेन, इटली और फिजी के प्रधानमंत्रियों द्वारा तृतीय 'इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेज़िलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर'⁷⁵ का शुभारंभ किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण अवसरचना क्षेत्रों की अनुकूलता के साथ-साथ शहरी अवसरचना प्रणाली और आपदा जोखिम वित्तपोषण के प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। ○ भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों द्वारा रेज़िलिएंट द्वीप राज्यों के लिए अवसरचना⁷⁶ पहल की गई। यह छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों⁷⁷ के लिए एक समर्पित पहल है। इसके तहत, SIDS के अवसरचना को जलवायु परिवर्तन और आपदा से संबंधित घटनाओं के प्रति लचीला बनाने में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। ○ आपदा और जलवायु सहाय अवसरचना पर CDRI की प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट का उद्देश्य आपदा और जलवायु सहाय अवसरचना की महत्वपूर्ण और बहुआयामी चुनौतियों पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना है और उन्हें इसमें शामिल करना है। ○ DRI कनेक्ट, नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसके तहत, हितधारकों को ऐसे ज्ञान संसाधन और सामूहिक अवसरों तक पहुँचाया जा सकेगा जो उनके साथियों और अन्य पक्षों के पास हैं।

⁷⁵ International Conference on Disaster Resilient Infrastructure: ICDRI

⁷⁶ Infrastructure for Resilient Island States: IRIS

⁷⁷ Small Island Developing States: SIDS

उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह (लीड-इट ग्रुप)	इसका शुभारंभ सितंबर, भारत-स्वीडन द्वारा 2019 में न्यू यॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में विश्व आर्थिक मंच की सहायता से किया गया। इसे पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए जलवायु संबंधित आकांक्षाओं और कार्रवाइयों को बढ़ावा देने शुरू किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा चिह्नित नौ ऐक्शन ट्रैक में से एक है।
--	--

सुझाव

- वन और वृक्षों के आवरण को और बढ़ाने की जरूरत है। सामाजिक वानिकी (सोशल फॉरिस्ट्री) इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए, भूजल के पुनर्भरण में सुधार करना होगा और आवश्यकता से अधिक दोहन को रोकना होगा। इसके अलावा, महत्वपूर्ण और अर्ध-महत्वपूर्ण मूल्यांकन इकाइयों को और अधिक विकृत होने से बचाना होगा।
- 2070 तक भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले देश बनने के लक्ष्य की घोषणा के बाद से, जलवायु से संबंधित कार्रवाई करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
- भारत सहित कई अन्य विकासशील देशों द्वारा सफल जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

शब्दावली	
वन क्षेत्र	वे क्षेत्र जिन्हें सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज किया गया है। इन्हें "अभिलेखित वन क्षेत्र" भी कहा जाता है।
वन आवरण	इसमें एक हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक वाली ऐसी सभी भूमि को शामिल किया जाता है जहाँ वृक्षों का वितान (कैनपी) घनत्व 10% से अधिक हो। इसका भूमि के स्वामित्व और कानूनी स्थिति से कोई लेन-देना नहीं होता है। इस तरह की भूमि के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह अभिलेखित वन क्षेत्र हों, उनमें बागान, बांस और ताड़ के वृक्ष भी होते हैं।
बहुत घना वन	70% और उससे अधिक के वृक्ष वितान घनत्व वाली समस्त भूमि।
मध्यम घने जंगल	40-70% के बीच वृक्ष वितान घनत्व वाली समस्त भूमि।
खुला जंगल	10-40% के बीच वृक्ष वितान घनत्व वाली समस्त भूमि।
निकासी का चरण (SoE)	वार्षिक भूजल निकासी और वार्षिक निकासी योग्य संसाधनों का अनुपात यानी उपयोग बनाम उपलब्धता को प्रतिशत में व्यक्त करना।
भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन	एक वर्ष में जितना भूजल पुनर्भरण हो सकता है उससे अधिक भूजल की निकासी।
पेरिस रूल बुक	इसमें पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

अध्याय एक नज़र में
नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन में सुधार आया है। वर्ष 2019-20 में भारत का इसमें समग्र स्कोर 60 था, जो 2020-21 में बढ़कर 66 हो गया है।
फ्रंट रनर राज्यों (65-99 के बीच स्कोर) और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2020-21 में बढ़कर 22 हो गई है, जो 2019-20 में 10 थी।
भारत अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत 2010-20 दशक के दौरान वन क्षेत्र में निवल वृद्धि के संदर्भ में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा।
नमामि गंगे मिशन (NGM) के तहत की गई पहलों की मदद से, गंगा नदी में अपशिष्ट निर्वहन 2017 में 349.13 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) से घटकर वर्ष 2020 में 280.20 MLD हो गया है।
भारत में वार्षिक भूजल निकासी 2004-2020 के दौरान 58-63% की सीमा में रही है।
2019-20 की तुलना में 2020-21 में 96 शहरों में PM10 सांद्रता की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई।
NDCs के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत में कई पहलें शुरू की गई हैं। इनमें, NAPCC, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, पीएम-कुसुम, रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम चरण-II आदि शामिल हैं।
COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन, ग्लासगो के प्रमुख परिणामों में शामिल हैं- "पेरिस नियमावली में लंबित विषयों को अंतिम रूप दिया गया",

ग्लासगो जलवायु समझौता, ग्लासगो-शर्म अल-शेख कार्य कार्यक्रम, हानि और क्षति पर ग्लासगो संवाद आदि।

वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सेबी द्वारा संधारणीय वित्त के क्षेत्र में कई पहलें की गईं।

भारत ने ISA, CDRI और लीड-इट ग्रुप के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जलवायु का नेतृत्व करना जारी रखा और पर्यावरण के लिए वन वर्ड मूवमेंट- लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरनमेंट (लाइफ) यानी पर्यावरण के लिए जीवनशैली का प्रस्ताव रखा।

अध्याय-6



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विगत दशक में विश्व स्तर पर वन क्षेत्र में भारत का औसत वार्षिक निवल बढ़ोतरी सर्वाधिक था।
2. कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण में वृद्धि मुख्य रूप से मध्यम सघन वन में बढ़ोतरी के कारण है।
3. राज्यों में, मध्य प्रदेश में वर्ग किलोमीटर के मामले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 3

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन कुल भूजल निष्कर्षण के चरण का सही वर्णन करता है?

- (a) यह वार्षिक भूजल निष्कर्षण और वार्षिक निष्कर्षण योग्य संसाधनों का अनुपात है।
- (b) यह भूजल संसाधनों का निष्कर्षण है, जो वार्षिक पुनर्पूर्ति योग्य भूजल पुनर्भरण से अधिक है।
- (c) यह वार्षिक भूजल पुनर्भरण और वार्षिक भूजल निष्कर्षण का अनुपात है।
- (d) यह वर्षा जल के माध्यम से फिर से भरने वाले भूमिगत जलभृतों से भूजल की निकासी है।

Q3. सेबी (SEBI) द्वारा जारी स्थिरता रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह वित्त वर्ष 2022-23 से अनिवार्य आधार पर बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होगा।
2. इसे मौजूदा व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (BRR) के अतिरिक्त लागू किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Q4. सतत विकास वित्तपोषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में सतत वित्त के लिए ढांचे को परिभाषित करने हेतु वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग द्वारा सतत वित्त पर कार्य दल का गठन किया गया है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सतत वित्त और जलवायु जोखिम के क्षेत्रों में विनियामक पहलों का नेतृत्व करने के लिए अपने विनियमन विभाग के भीतर 'सतत वित्त समूह' (SFG) का गठन किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Q5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के क्षेत्र में भारत की निम्नलिखित पहलों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
2. लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट
3. लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजीशन (लीडआई.टी. समूह)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) 1-3-2
- (b) 1-2-3
- (c) 3-1-2
- (d) 3-2-1



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

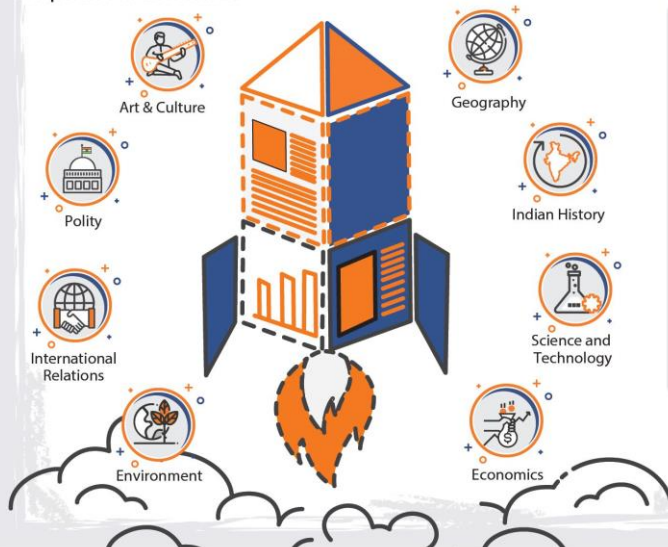
Q1. 'एकल उपयोग वाले प्लास्टिक' की उपयोगिता और आर्थिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए उन पर नीतिगत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में सरकार द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Q2. जलवायु कार्रवाई पर अत्यधिक बल देने के बावजूद, उसकी प्रभावशीलता गंभीर रूप से उसके वित्तपोषण पर निर्भर है। चर्चा कीजिए।

FAST TRACK COURSE 2022 GENERAL STUDIES PRELIMS

PURPOSE OF THIS COURSE

The GS Prelims Course is designed to help aspirants prepare for & increase their score in General Studies Paper I. It will not only include discussion of the entire GS Paper I Prelims syllabus but also that of previous years' UPSC papers along with practice & discussion of Vision IAS classroom tests. Our goal is that the aspirants become better test takers and can see a visible improvement in their Prelims score on completion of the course.



INCLUDES



Access to recorded live classes at your personal student platform.



Comprehensive, relevant & updated Soft Copy of the study material for prelims syllabus.



Access to PT 365 classes



Sectional mini test and Comprehensive Current Affairs.

**COURSE
BEGINS**

7 January

**TOTAL NO
OF CLASSES**

60

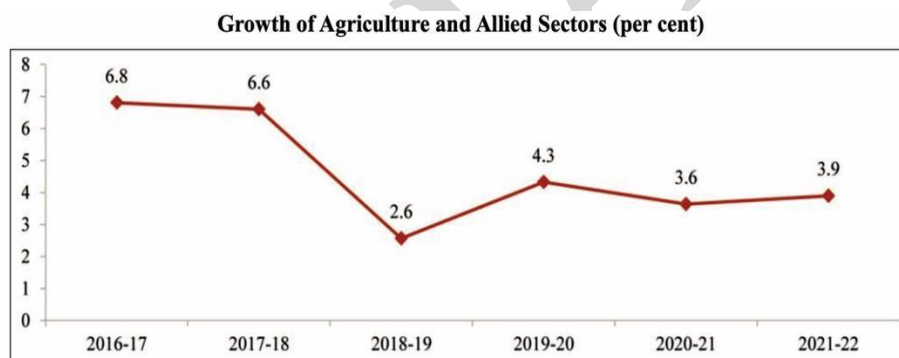
अध्याय 7: कृषि और खाद्य प्रबंधन (Agriculture & Food Management)

परिचय

- यह अध्याय भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करता है।
- यह तिलहन व खाद्य तेलों के उत्पादन और घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने, चीनी के क्षेत्र में किए गए हस्तक्षेप और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करता है।
- यह अध्याय संधारणीय कृषि के लिए सिंचाई के क्षेत्र में जल संरक्षण, प्राकृतिक कृषि और फसल उत्पादकता हेतु अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता तथा मशीनीकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- यह इस बात पर भी चर्चा करता है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति का उपयोग कैसे किया जा रहा है।
- इसके अलावा, नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण⁷⁸ के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर भी चर्चा की गई है।
- खाद्यान्न खरीद, आवंटन, भंडारण, और खाद्य सस्मिडी के मुद्दे सहित भारत के उर्वरक क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा के साथ-साथ प्रभावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी उपायों को भी अध्याय में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में समग्र संवृद्धि

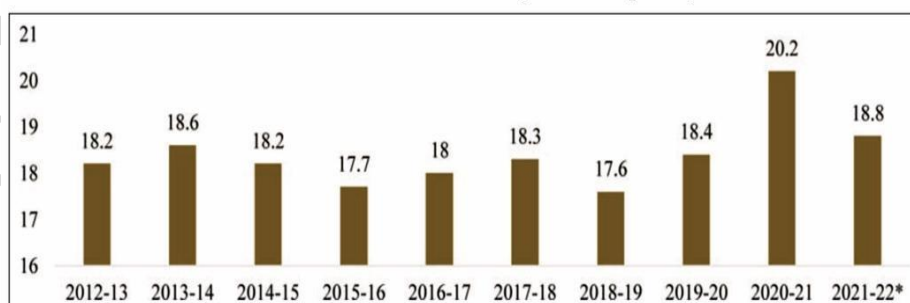
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2020-21 की अवधि में 3.6 प्रतिशत और 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की सकारात्मक दर से वृद्धि हुई।



Source: First Advance Estimates of National Income, 2021-22

- यह संवृद्धि अच्छे मानसून और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ-साथ ऋण उपलब्धता में वृद्धि, निवेश में सुधार, बाजार सुविधाओं में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण आगतों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न सरकारी उपायों का परिणाम थी।

Percentage Share of GVA of Agriculture & Allied Sector to Total GVA (at current prices)



Source: Based on data of DAFW.

*As per 1st Advance Estimates of National Income, 2021-22.

- पशुधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि ने इस क्षेत्र को अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की है।

○ उदाहरण के लिए, वित्तीय

वर्ष 2018-19 में कृषि

क्षेत्र में बेहतर वृद्धि

पशुधन और मत्स्य पालन

के उच्च प्रदर्शन के कारण

हुई थी, भले ही फसलों के लिए GVA की वृद्धि -1.6 प्रतिशत रही थी।

कृषि में सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added: GVA)

• रुझान:

- कुल GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी, 18% के आस-पास की दीर्घकालिक प्रवृत्ति से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 20.2% और 2021-22 में 18.8% हो गई।

⁷⁸ Situation Assessment Survey: SAS

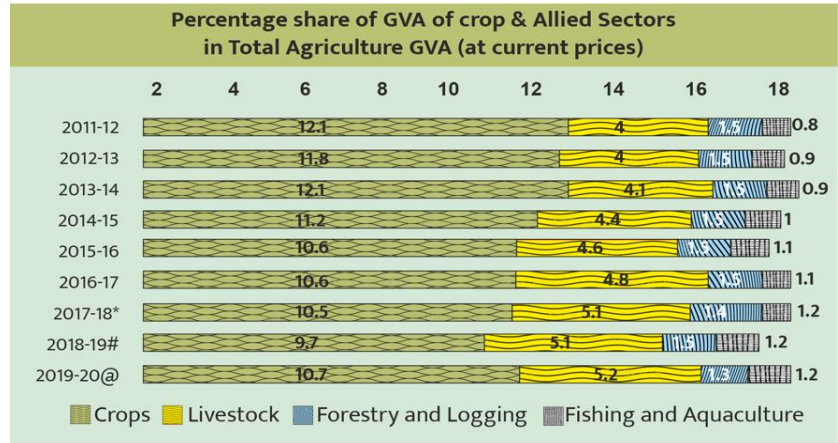
- कुल कृषि GVA में पशुधन व मछली पालन और जलीय कृषि की हिस्सेदारी में सुधार हो रहा है।

- किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति (DFI, 2018) की सिफारिशें भी सहवर्ती समर्थन प्रणालियों जैसे- डेयरी, पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और बागवानी आदि पर केंद्रित थीं।

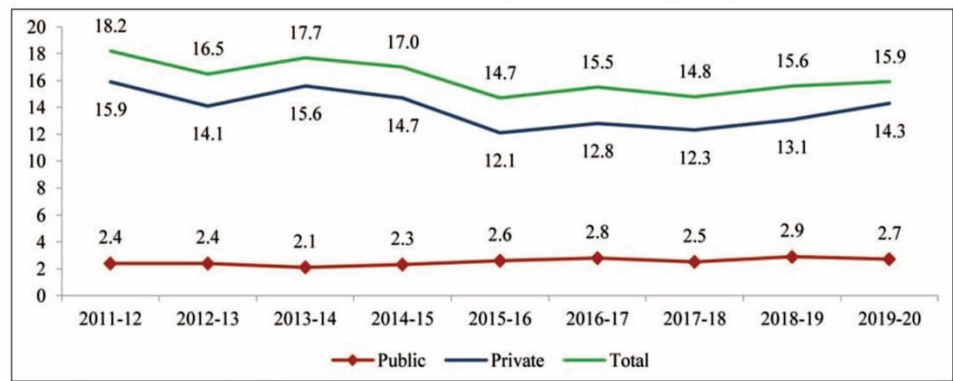
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निजी निवेश में व्यापक उतार-चढ़ाव के कारण GVA के सापेक्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण⁷⁹ में भी उतार-चढ़ाव हो रहा है।
- कृषि क्षेत्र में निजी निवेश में सुधार के लिए सुझाव:

- किसानों को रियायती संस्थागत ऋण की पर्याप्त उपलब्धता हो।
- निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी हो।
- एक उपयुक्त नीतिगत ढांचे का निर्माण करके और संपूर्ण कृषि मूल्य प्रणाली में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करके निजी कॉर्पोरेट निवेशों को प्रोत्साहित किया जाए।



Percentage Share of GCF in Agriculture and Allied Sectors Relative to Its GVA (at 2011-12 basic prices)



Source: Based on data of DAFW and Agricultural Statistics at a Glance, 2020.

कृषिगत उत्पादन

- देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन: 308.65 मिलियन टन (2019-20 की तुलना में 11.15 मिलियन टन अधिक)।
- वर्ष 2015-16 से

2020-21 की अवधि में चावल, गेहूं और मोटे अनाज के उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर⁸⁰ क्रमशः 2.7, 2.9 और 4.8 प्रतिशत थी।

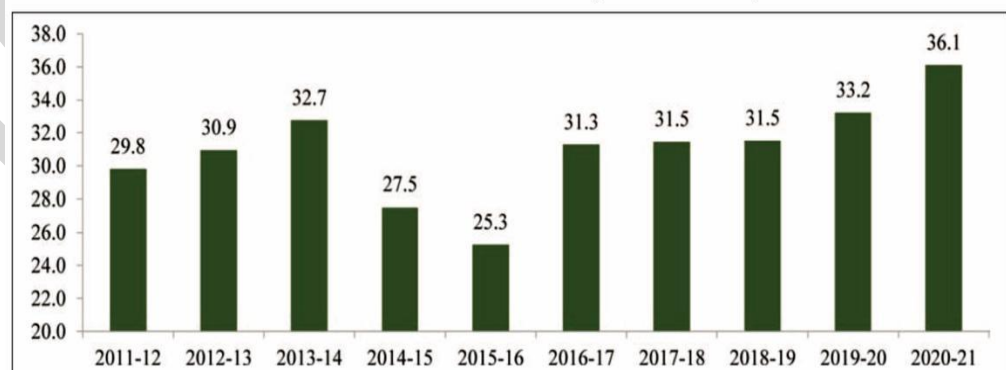
- वर्ष 2015-16 से 2020-21 की अवधि में दलहन, तिलहन

और कपास के लिए CAGR क्रमशः 7.9, 6.1 और 2.8 प्रतिशत थी।

खाद्य तेल: भारत, वनस्पति तेलों के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक है।

- रुझान: वर्ष 2016-17 के बाद से भारत में तिलहन उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।

Trend in Production of Oilseeds (Million Tonnes)



Source: Based on data of 4th Advanced Estimates as on Directorate of Economics & Statistics Website.

⁷⁹ Gross Capital Formation: GCF

⁸⁰ Compound Annual Growth Rate: CAGR

- तिलहन उत्पादन में वृद्धि: वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक लगभग 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- चिंताएं: तिलहन का उत्पादन इसके उपभोग की तुलना में कम रह जाता है जिसके कारण खाद्य तेलों का आयात आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए,

लगभग 98 प्रतिशत कच्चे पाम तेल⁸¹ का आयात किया जाता है।

- उठाए गए कदम और उपलब्धियां:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (NFSM-तिलहन):

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान

36 तिलहन बीज हब स्थापित किए गए।

- तिलहन के उत्पादन की दिशा में फसल विविधीकरण के लिए मूल्य संकेत प्रदान करने वाली MSP व्यवस्था।

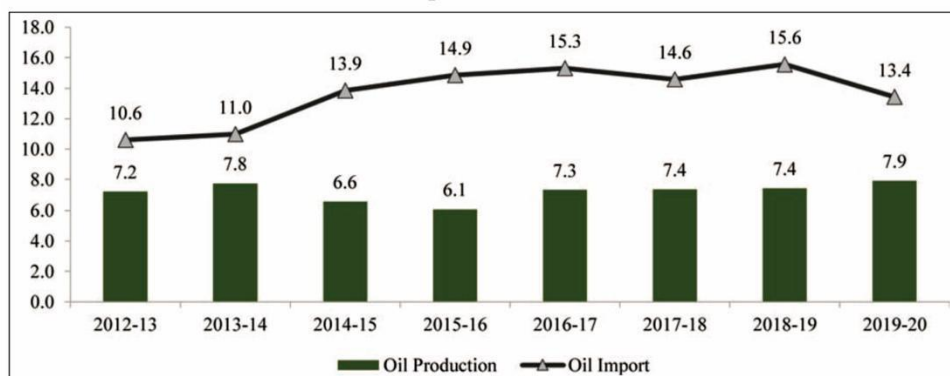
- खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम⁸² यह मिशन देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया

है। इसके तहत खाद्य तेल उत्पादन क्षेत्र का विस्तार और मूल्य प्रोत्साहन जैसे उपाय किये जा रहे हैं। मूल्य प्रोत्साहन के लिए व्यवहार्यता मूल्य⁸³ को अपनाया गया है ताकि किसानों को कच्चे पाम तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके।

चीनी क्षेत्र: भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी उद्योग कपास के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है।

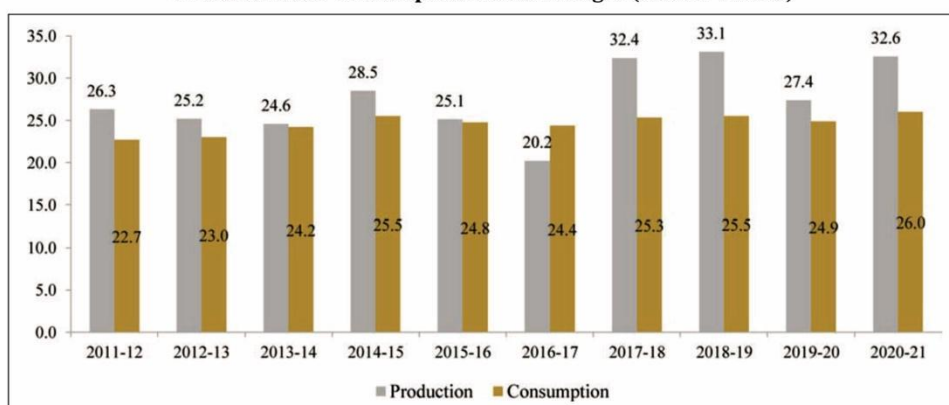
- गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 35.5 करोड़ टन है, जिसका उपयोग लगभग 3 करोड़ टन चीनी का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

- रुझान: वर्ष 2010-11 के बाद से, 2016-17 को छोड़कर उत्पादन खपत से अधिक रहा है (ग्राफ देखें)।



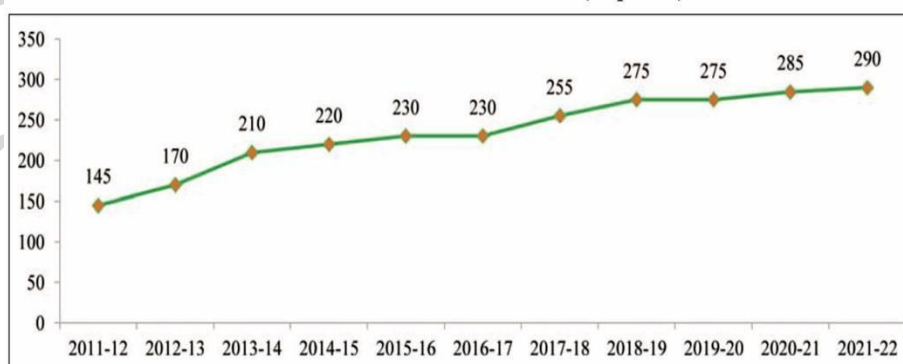
Source: Based on data of Agricultural Statistics at Glance, 2020.

Production and Consumption Levels of Sugar (Million Tonnes)



Source: Based on data of CACP Report on Sugarcane.

Trend in Fair & Remunerative Price (₹/quintal)



Source: Based on data of CACP website.

⁸¹ Crude Palm Oil: CPO

⁸² National Mission on Edible Oils - Oil Palm: NMEO-OP

⁸³ Viability Price: VP

- गन्ना किसानों को मूल्य जोखिम से बचाने के लिए उठाए गए कदम:
 - उचित और लाभकारी मूल्य⁸⁴ वर्ष 2011-12 से लगातार बढ़ा है और दस वर्षों की अवधि में दोगुना हो गया है।
 - राज्य सरकारों द्वारा FRP से अधिक स्तर पर घोषित राज्य परामर्श मूल्य⁸⁵।
 - चीनी मिलों को गन्ना आरक्षण क्षेत्र के रूप में नामित एक निर्दिष्ट दायरे के भीतर किसानों से गन्ने की फसल खरीदना अनिवार्य है।
- अधिशेष उत्पादन को संभालने और मिलों की तरलता बढ़ाने के लिए कदम:
 - चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ना/चीनी का इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
 - चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए चीनी मिलों को परिवहन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- उपलब्धियाँ:
 - चीनी सीजन 2019-20 में 59.60 लाख मीट्रिक टन (LMT) चीनी निर्यात के मुकाबले वर्ष 2020-21 में लगभग 70 LMT चीनी का निर्यात किया गया।
 - वर्ष 2020-21 को समाप्त हुए पिछले चार चीनी सीजनों में तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों/डिस्टिलरी को लगभग ₹35000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

क्या आप जानते हैं?



दूसरे तिलहन फसलों की तुलना में ऑयल पाम से प्रति हेक्टेयर 10 से 46 गुना अधिक तेल का उत्पादन होता है। इससे प्रति हेक्टेयर लगभग 4 टन तेल का उत्पादन होता है।

मूल्य नीति: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में स्थापित सिद्धांत के आधार पर (MSP को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखना) सरकार ने वर्ष 2021-22 की सभी अनिवार्य खरीफ और रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि की घोषणा की है।

MSP के बारे में

- सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विमर्श करने के बाद 22 अनिवार्य कृषि फसलों का MSP तय करती है।
- MSP की सिफारिश करते समय CACP कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जैसे-
 - उत्पादन की लागत,
 - समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति,
 - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें,
 - अंतर-फसल मूल्य समता,
 - कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें,
 - शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव,
 - भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना और
 - उत्पादन लागत पर लाभांश के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत।

22 MANDATED CROPS

14 Kharif crops

- Paddy
- Jowar
- Bajra
- Maize,
- Ragi Tur (arhar)
- Moong
- Urad
- Groundnut
- Soybean (yellow)
- Sunflower
- Seed
- Sesamum
- Nigerseed
- Cotton

6 Rabi crops

- Wheat
- Barley
- Gram
- Masur (lentil)
- Rapeseed and Mustard
- Safflower

2 Commercial crops

- Jute
- Copra

फसल विविधीकरण

- लाभ: जल उपयोग दक्षता और मृदा स्वास्थ्य की धारणीयता, आयात निर्भरता में कमी और किसानों के लिए उच्च आय के माध्यम से संधारणीय कृषि को बढ़ावा मिलता है।
- चिंताएं: मौजूदा फसल प्रणाली गन्ना, धान और गेहूं की खेती की ओर झुकी हुई है जिसके कारण कई हिस्सों में भू-जल संसाधनों में खतरनाक दर से कमी आई है।

⁸⁴ Fair and Remunerative Price: FRP

⁸⁵ State Advised Price: SAP

उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की उप-योजना फसल विविधीकरण कार्यक्रम⁸⁶ का उद्देश्य धान की खेती के अधीन क्षेत्रों

(पंजाब,

हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में) और तंबाकू की खेती के अधीन क्षेत्रों (तंबाकू उगाने वाले राज्यों में) को कम जल गहन फसलों जैसे- तिलहन, दलहन, मोटे

अनाज, पोषक-

अनाज, कपास आदि के

उत्पादन की ओर

स्थानांतरित करना है।

- MSP व्यवस्था के तहत प्रोत्साहन संरचना (इंसेंटिव स्ट्रक्चर) प्रदान की जा रही है।

कृषि ऋण

- वर्ष 2020-21 के लिए कृषि

ऋण प्रवाह ₹15,00,000

करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले

₹15,75,398 करोड़ रहा।

उठाए गए कदम:

- आत्मनिर्भर भारत घोषणा के एक भाग के रूप में घोषित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रियायती ऋण प्रोत्साहन।
- वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को KCC की सुविधा प्रदान की गई।

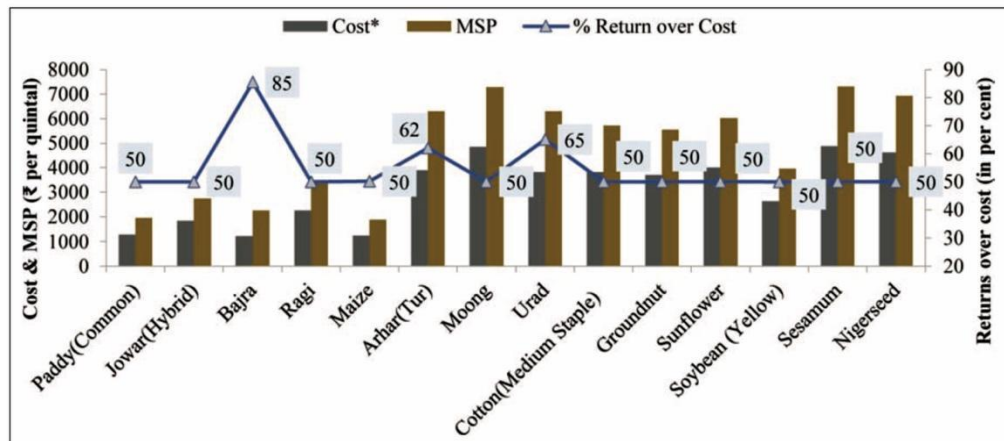
उपलब्धियां:

- 2.70 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया (17 जनवरी 2022 तक)।

पानी और सिंचाई

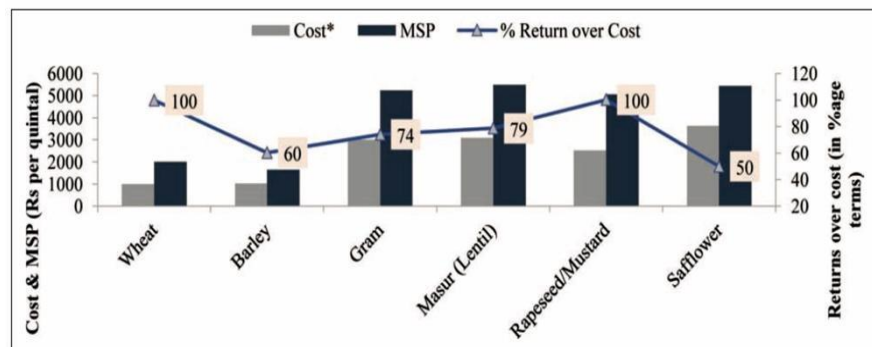
- देश में कुल वर्तमान जल उपयोग में कृषि का योगदान लगभग 80% है।
- निचल सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल बोए

Cost, MSP & Returns of Kharif Crops for the year 2021-22.



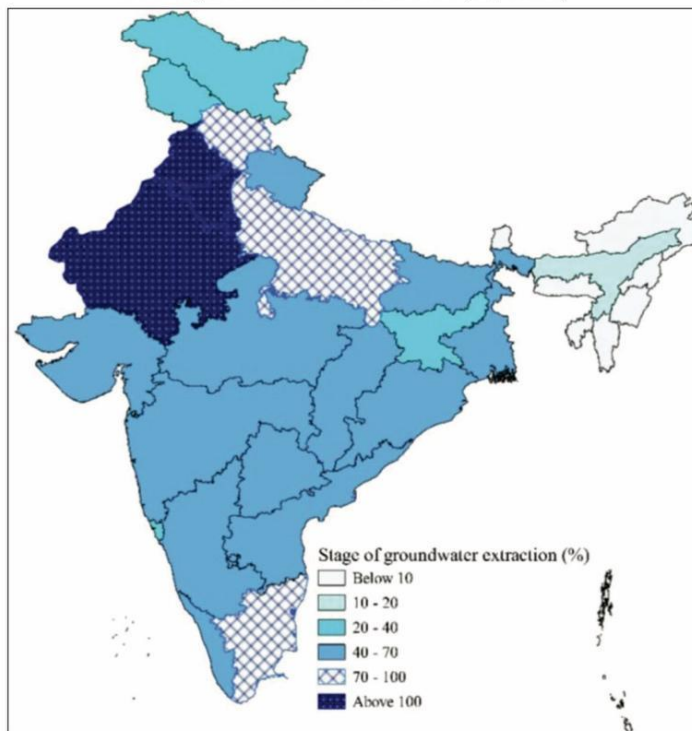
Source: DAFW

Cost, MSP & Returns of Rabi Crops of year 2021-22



Source: DAFW

State of groundwater extraction in 2020 (in per cent)*



Source: Ground water yearbook, 2019-20

⁸⁶ Crop Diversification Programme: CDP

गए क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है और इसमें से लगभग 40 प्रतिशत नहर प्रणाली के माध्यम से और 60 प्रतिशत भूजल के माध्यम से सिंचित है।

- चिंताएं: दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल की निकासी की दर बहुत अधिक (100 प्रतिशत से अधिक) है।
- उठाए गए कदम और उपलब्धियां:
 - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) के अंतर्गत 5000 करोड़ के सूक्ष्म सिंचाई कोष⁸⁷ का सृजन।
 - सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-PDMC) के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) घटक।

कृषि विपणन: थोक कृषि विपणन का कार्य राज्य कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम के प्रावधान के तहत स्थापित 6946 विनियमित थोक बाजारों के नेटवर्क द्वारा किया जाता है।

- उठाए गए कदम और उपलब्धियां:
 - APMCs को कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत एक पात्र इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। यह उन्हें विभिन्न अवसंरचनाओं से जुड़ी प्रत्येक परियोजना जैसे- कोल्ड स्टोरेज, छँटाई, ग्रेडिंग और परख इकाइयाँ, साइलो, आदि के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज पर अनुदान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
 - राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना: दिसंबर 2021 तक, 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों को e-NAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।
 - "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन और संवर्धन" की केंद्रीय क्षेत्र की योजना: FPO उत्पाद विशेषज्ञता को प्रभावी बनाने के लिए "एक जिला एक उत्पाद" पर केंद्रित है। जनवरी 2022 तक, कुल 1963 FPO पंजीकृत किए गए हैं।
 - सहकारिता के क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के लिए वर्ष 2021 में पूर्णतः समर्पित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।

मीठी क्रांति: राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM)

- तीन वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2022-23) के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के एक भाग के रूप में घोषित।
- उद्देश्य: राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन का समग्र प्रचार और विकास करना।
- मधुमक्खी पालन के लाभ: फसलों के परागण में उपयोगी, जिससे फसल की उपज बढ़ाने और शहद और अन्य उच्च मूल्य मधुमक्खी उत्पाद जैसे; मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी के डंक का जहर, आदि प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे किसानों/मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि की जा सकती है।

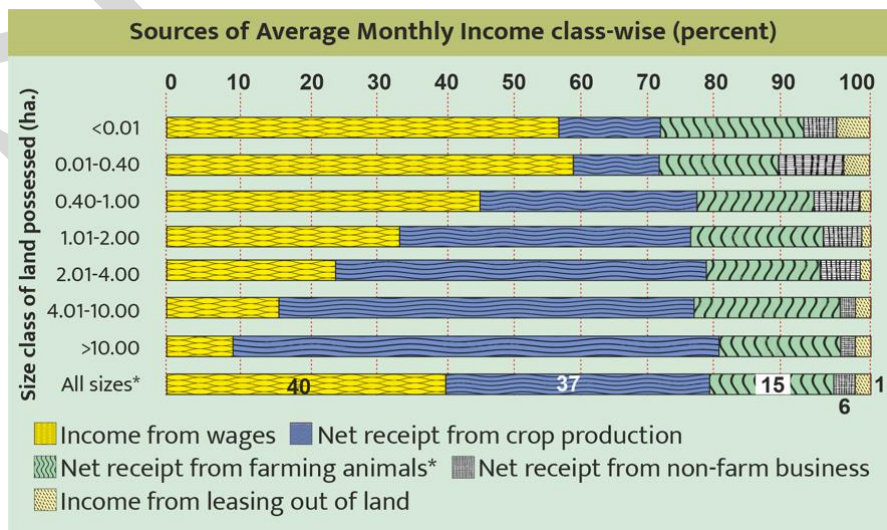
स्थिति आकलन सर्वेक्षण (Situation Assessment Survey: SAS):

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

द्वारा किए गए 77वें दौर के सर्वेक्षण में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में "परिवारों की भूमि और पशुधन स्वामित्व और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन" सर्वेक्षण को SAS के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह रिपोर्ट सितंबर 2021 में जारी की गई थी और इसके पूर्व SAS 2014 में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-

- भुगतान किए गए व्यय दृष्टिकोण के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय में वृद्धि:

SAS, 2014 के ₹6426 के मुकाबले SAS, 2021 में ₹10,218 है।



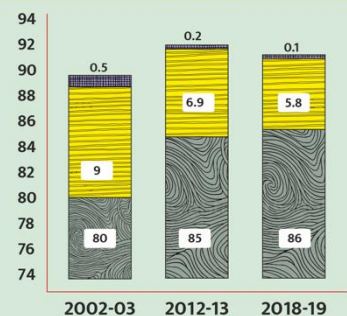
⁸⁷ Micro Irrigation Fund: MIF

- फसल आय किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है (37 प्रतिशत हिस्सा) हालांकि किसानों की आय के स्रोतों में विविधता दिखाई दे रही है।
- जोत का विखंडन: घरेलू स्वामित्व वाले जोत का औसत आकार 2003 में 0.725 हेक्टेयर से घटकर 2013 में 0.592 हेक्टेयर और 2019 में 0.512 हेक्टेयर हो गया है।
- सुझाव: लघु कृषि प्रौद्योगिकी के विकास, गैर-कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने और पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन सहित संबद्ध गतिविधियों के विकास जैसे उपायों पर ध्यान देना चाहिए।

संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन और डेयरी पशुधन क्षेत्र

- वृद्धि दर: 2014-15 से 2019-20 के दौरान CAGR 8.15 प्रतिशत (स्थिर कीमतों पर)।
- कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र का GVA में योगदान (स्थिर कीमतों पर): 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 29.35 प्रतिशत (2019-20) हो गया।
- कुल GVA में पशुधन का योगदान: 2019-20 में कुल GVA का 4.35 प्रतिशत।

Distribution of Household by size category of Ownership Holdings (percent)



डेयरी क्षेत्र: भारत दुग्ध

उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यह वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23 प्रतिशत का योगदान देता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत का योगदान करने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है।

- वृद्धि दर: 2020-21 में 6.2 प्रतिशत की

CAGR

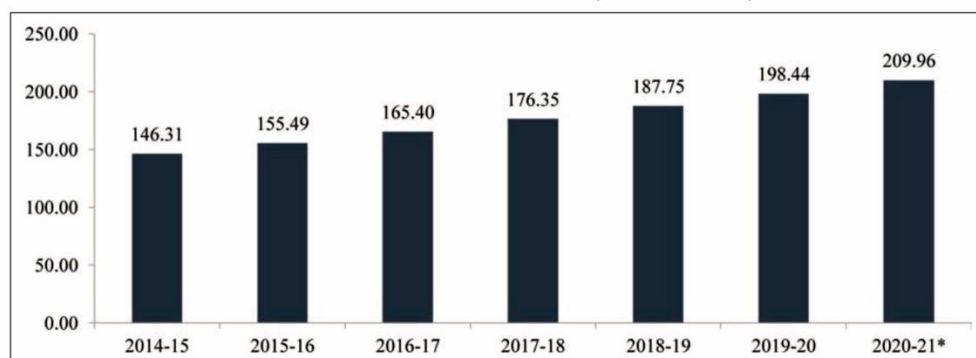
- रुझान: 2014-15 के बाद से दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।

अंडा और मांस उत्पादन: भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है।

- अंडे का उत्पादन 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर 2020-21 में 122.11 बिलियन हो गया।

- मांस का उत्पादन 2014-15 में 6.69 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 8.80 मिलियन टन हो गया।

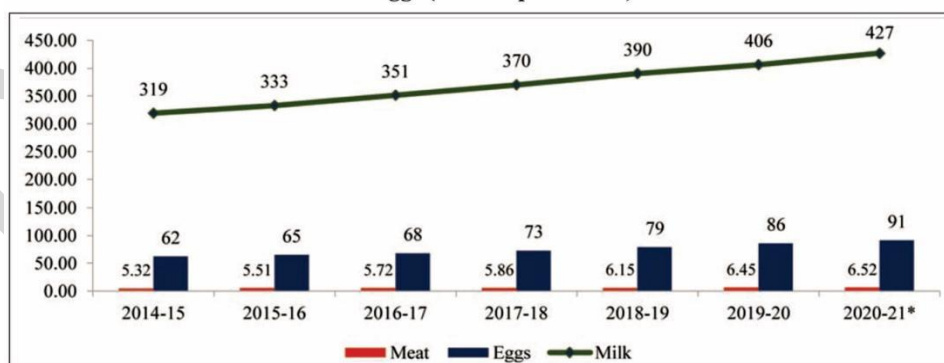
Trend of Milk Production in India (Million Tonnes)



Source: Based on data taken from the National Dairy Development Board and DAHD.

*Data is provisional

Per Capita Availability of Milk (gram per day), Meat (kg per year) and Eggs (number per annum)



Source: Based on data received from Department of Animal Husbandry & Dairying

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में हाल की पहल और उनकी उपलब्धियां

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम: 11 राज्यों में खुरपका मुंहपका रोग (FMD) का टीकाकरण पूरा कर लिया गया है, दिसंबर 2021 तक FMD के खिलाफ 5 करोड़ जानवरों और ब्रुसेल्लोसिस के खिलाफ 27.8 लाख जानवरों का टीकाकरण किया गया है।
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF): दिसंबर 2021 तक कुल 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत जारी व्याज अनुदान की राशि 2020-21 के दौरान ₹12.74 करोड़ और 2021-22 के दौरान ₹ 6.40 करोड़ थी।

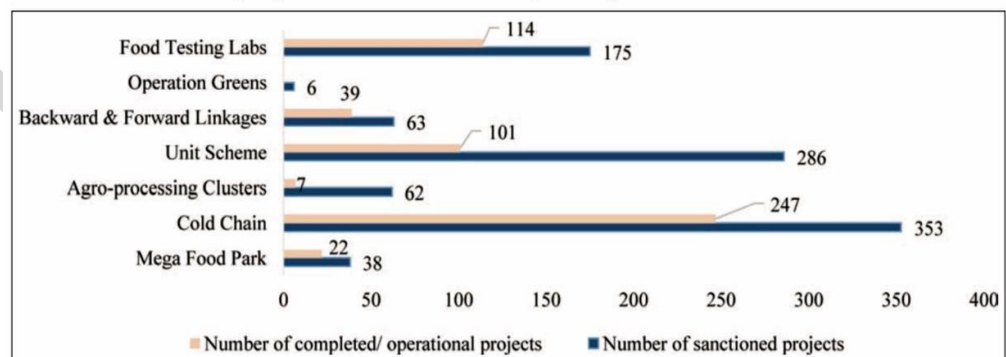
मत्स्य पालन: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 7.56 प्रतिशत हिस्सा है।

- भारत के GVA में योगदान: 1.24 प्रतिशत।
- कृषि GVA में योगदान: 7.28 प्रतिशत।
- औसत वार्षिक वृद्धि: वित्त वर्ष 2020-21 में 145 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन के साथ 2014-15 से 10.87 प्रतिशत।
- रोजगार: भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का साधन है।
- इस क्षेत्र से निर्यात आय: 2019-20 के दौरान ₹46,662.85 करोड़।
- उठाए गए कदम और उपलब्धियाँ:
 - मत्स्य पालन के लिए KCC की सुविधा का विस्तार: 31 दिसंबर 2021 तक मछुआरों और मछली पालने वाले किसानों को कुल 1,04,157 KCC जारी किए गए हैं।
 - प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMSY): कुल 5584.74 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले परियोजना प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

- भूमिका: पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय वैश्विक खाद्य प्रणाली का विकास, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं लागत को कम करके और उपज को अधिकतम करके कृषि आय में वृद्धि करना।
 - विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 1/5वां हिस्सा योगदान देती है।
- हालिया प्रगति:
 - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 2020 और 2021 के दौरान खेत फसलों की कुल 731 नई किस्मों/संकरों और 98 बागवानी फसलों को अधिसूचित/जारी किया।
 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) ने 2021-22 के दौरान खेत एवं बागवानी फसलों की बायोफोर्टिफाइड और तनाव-सहिष्णु किस्मों सहित 35 विशेष गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास किया।
 - ICAR ने एकल भूमि उपयोग प्रणाली से फसल उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए 105 kW की कृषि-वोल्टाइक प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया।
- मशीनीकरण: भारतीय ट्रैक्टर उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का एक-तिहाई है।
 - विभिन्न कृषि गतिविधियों में संचालित मशीनों का प्रवेश: लगभग 40 से 45 प्रतिशत।
 - उठाए गए कदम और उपलब्धियाँ:
 - कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM): 2014-15 से 2020-21 के दौरान कुल 27828 कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) और केवल 2020-21 के दौरान 9432 CHCs स्थापित किए गए।
 - किसानों को अपने क्षेत्र में CHC के माध्यम से किराए की कृषि मशीनरी और उपकरण प्राप्त करने में मदद करने के लिए फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस (FARMS) नामक बहुभाषी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।

Status of projects sanctioned and completed/operational under PMKSY



Source: Based on data received from MoFPI.

- फसल अवशेष प्रबंधन (CRM): 'पंजाब,

हरियाणा, उत्तर प्रदेश

और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

- औसत वार्षिक वृद्धि दर: लगभग 11.18 प्रतिशत।
- विनिर्माण क्षेत्र में GVA का योगदान: 2011-12 की कीमतों पर 2019-20 में 9.87 प्रतिशत।
- रोजगार: 2017-18 में सभी पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में सृजित रोजगार में 12.38 प्रतिशत की हिस्सेदारी।

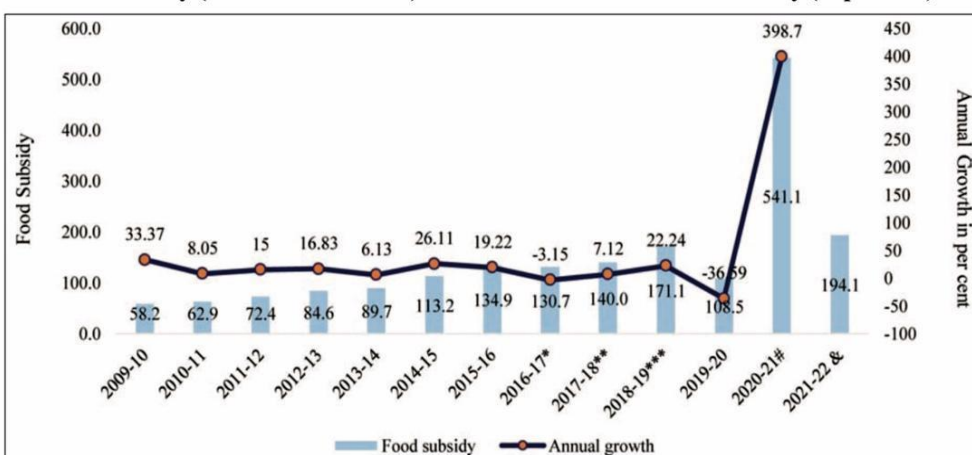
- **FDI:** अप्रैल 2014 से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इक्विटी अंतर्प्रवाह।
- **योजनाएं और उपलब्धियां:**
 - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (PM-FME) का औपचारीकरण: 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 710 जिलों में 137 अद्वितीय उत्पादों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है।
 - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY):
 - टमाटर, प्याज और आलू (TOP) योजना:
 - दीर्घकालीन वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट: इसके कार्यक्षेत्र को TOP से बढ़ाकर 22 खराब होने वाले उत्पादों तक कर दिया गया है।
 - अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपाय: योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को भी किसान रेल योजना तक बढ़ा दिया गया था। ANB घोषणा में अल्पकालिक उपायों का दायरा TOP से TOTAL (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ाया गया।

खाद्य प्रबंधन

- **उद्देश्य:** किसानों से लाभकारी कीमतों पर खाद्यान्न की खरीद; उपभोक्ताओं, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण और खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव।

क्षेत्र	पहल और उपलब्धियां
खाद्यान्नों का आवंटन	• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक के चरण-5 तक बढ़ा दिया गया है।
चावल का फोर्टिफिकेशन और उसका वितरण	• केंद्र प्रायोजित पायलट योजना, 'चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण' 15 जिलों में शुरू किया गया। • एकीकृत बाल विकास योजना और पीएम पोषण के तहत लगभग 19.79 LMT फोर्टिफाइड चावल की खरीद की गई है।
वन नेशन वन राशन कार्ड	• "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन" के तहत शुरू की गई एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) प्रणाली: लगभग 75 करोड़ लाभार्थियों (कुल NFSA आबादी का 94.3 प्रतिशत) को कवर करते हुए 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय/ अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू की गई है।
ओपन मार्केट सेल स्कीम	• वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति के कारण प्रवासी मजदूरों/कमजोर समूहों के लिए राहत या सामुदायिक रसोई चलाने वाले सभी धर्मार्थ या गैर-सरकारी संगठनों आदि को खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था की शुरुआत की गई थी।
खाद्य सब्सिडी	• गरीब हितैषी उपाय के रूप में, NFSA लाभार्थियों के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) को NFSA के प्रारंभ होने के बाद से संशोधित नहीं किया गया है।

Food Subsidy (in ₹ thousand crore) and Annual Growth in Food Subsidy (in per cent)



Source: Based on data received from DFPD.

इथेनॉल सम्मिश्रण	- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम: इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2019-20 के दौरान इथेनॉल की आपूर्ति 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2013-14 में 173.3 करोड़ लीटर हो गई है। - सरकार ने या तो चीनी मिलों से जुड़ी डिस्टिलरियों या स्टैंडअलोन डिस्टिलरियों द्वारा विभिन्न फीड स्टॉक जैसे- B-Hy और C-Hy शीरा, गन्ने का रस, चीनी सिरप, चीनी और अतिरिक्त FCI चावल, मक्का, आदि सहित क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है। - पात्र डिस्टिलरियों को ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
भंडारण	- निजी उद्यमी गारंटी योजना: PPP मॉडल पर गोदामों के निर्माण के माध्यम से 144.34 LMT की भण्डारण क्षमता निर्मित की गई। - गोदामों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना: 2017 से अब तक कुल 82,760 मीट्रिक टन क्षमता सृजित की गई है। - सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) में देश में स्टील साइलो के निर्माण के लिए कार्य योजना/रोड मैप: दिसंबर 2021 तक, पूरे देश में विभिन्न स्थानों में 29.25 LMT क्षमता का निर्माण किया गया है।

उर्वरक

- चिंताएं: आयात पर निर्भरता, बढ़ती सब्सिडी, पारदर्शिता की कमी।

उठाए गए कदम:

- स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने, उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत बनाने के लिए नई यूरिया नीति- 2015.

- यूरिया के सभी घरेलू उत्पादकों के लिए केवल नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करना अनिवार्य है।

- शीरा (गुड़ का) से व्युत्पन्न पोटैश (PDM) को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी

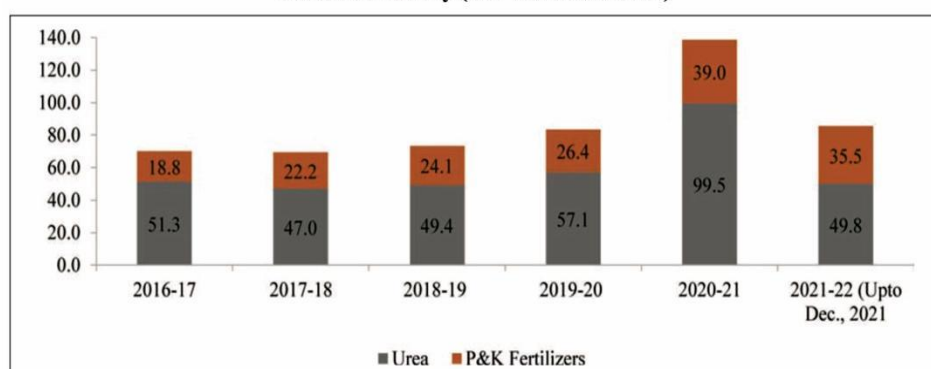
(NBS) योजना के तहत लाया गया है।

- नवीनतम प्रौद्योगिकियां जैसे- कोयला गैसीकरण; पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों आदि के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन।

निम्नलिखित अवलोकन और सुझाव दिए गए-

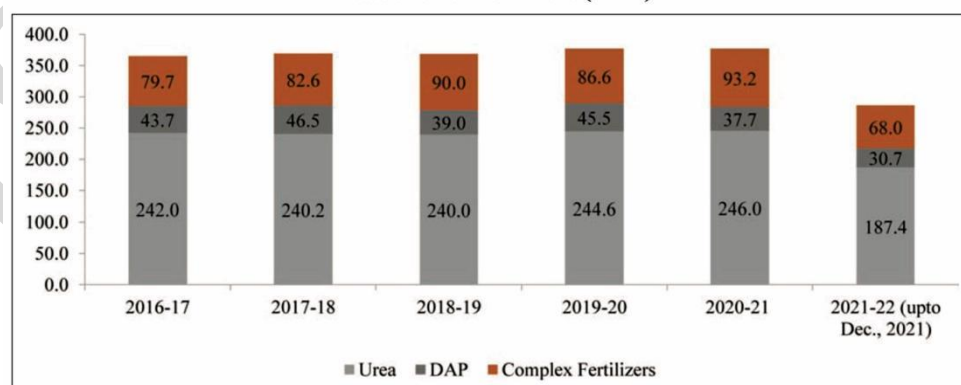
- संबद्ध गतिविधियों की क्षमता का उपयोग करने की ओर अधिक ध्यान देना।
- छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता में सुधार के लिए छोटी जोत वाली कृषि प्रौद्योगिकियों का विकास और कार्यान्वयन।
- सिंचाई, कृषि में निवेश, ऋण और बाजार जैसे मुख्य मुद्दों का समाधान कर तिलहन, दलहन और बागवानी की ओर फसल विविधीकरण को प्राथमिकता देना।

Fertilizer Subsidy (in ₹ thousand crore)



Source: Based on data received from the Department of Fertilizers.

Production of Fertilizers (LMT)



Source: Based on data received from the Department of Fertilizers.

- उच्च मूल्य और पानी की कम खपत वाली फसलों की ओर स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से समन्वित कार्रवाई।
- फसल और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि करना।
- विकल्पों की खोज करना और वैकल्पिक उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया और जैविक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना जो मिट्टी की रक्षा करते हैं, अधिक उत्पादक हैं और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता में योगदान करते हैं।
- ड्रोन और AI आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियों सहित नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी और कम लागत वाले जैविक साधनों का उपयोग और नवाचारों के लिए स्टार्टअप्स का समर्थन करना।

अध्याय एक नज़र में
कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 2020-21 में 3.6 प्रतिशत और 2021-22 में सुधर कर 3.9 प्रतिशत हो गई।
पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि इस क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख चालक रहे हैं।
निजी निवेश में व्यापक उतार-चढ़ाव के कारण GVA के सापेक्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (GCF) में भी अस्थिरता रही है।
2016-17 के बाद से भारत में तिलहन उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।
2010-11 के बाद से, 2017-17 को छोड़कर चीनी उत्पादन सदैव खपत से आगे रहा है।
मौजूदा फसल पैटर्न गन्ना, धान और गेहूं की खेती की ओर झुका हुआ है जिसके कारण भूजल संसाधनों में कमी आई है।
सिंचाई, निवेश, ऋण और बाजारों के मुख्य मुद्दों का समाधान करते हुए तिलहन, दलहन और बागवानी के पक्ष में फसल विविधीकरण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
नवीनतम SAS के अनुसार यह क्षेत्र कृषि परिवारों के समूहों में आय का स्थिर स्रोत रहा है, जो उनकी औसत मासिक आय का लगभग 15 प्रतिशत है।
भूमि जोत के बढ़ते विखंडन को देखते हुए, छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता में सुधार हेतु छोटी जोत वाली कृषि प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और लागू करने की आवश्यकता है।
2019-20 के पहले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा है।
2014-15 से दुग्ध उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।
मत्स्य पालन क्षेत्र ने 2014-15 के बाद से 10.87 प्रतिशत की उत्कृष्ट दोहरे अंकों की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है।
सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) जैसी योजनाओं के ज़रिए खाद्यान्न के अतिरिक्त वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क के कवरेज को और बढ़ा दिया है।

अध्याय-7



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. देश में निवल सिंचित क्षेत्र का हिस्सा कुल निवल बोए गए क्षेत्र के 30 प्रतिशत से कम है।
2. निवल सिंचित क्षेत्र में से, नहर प्रणाली की तुलना में भूजल के माध्यम से सिंचित क्षेत्र अधिक है।
3. पंजाब और हरियाणा में भूजल के निष्कर्षण की दर 100 प्रतिशत से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Q2. निम्नलिखित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन को विश्व में भारत की रैंकिंग के अनुसार बेहतर (निम्न) रैंक से उच्चतर रैंक तक व्यवस्थित कीजिए:

1. मांस उत्पादन
2. दुग्ध उत्पादन
3. अंडा उत्पादन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) 2-3-1
- (b) 2-1-3
- (c) 3-2-1
- (d) 3-1-2

Q3. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतर सकारात्मक दर से वृद्धि हुई।
2. कुल जी.वी.ए. में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के हिस्से की तुलना में वर्ष 2021-22 में बढ़ी है।
3. कुल कृषि जी.वी.ए. में पशुधन और मत्स्यन व जलीय कृषि की हिस्सेदारी में सुधार हो रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

Q4. स्थिति आकलन सर्वेक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) द्वारा किया गया 'परिवारों की भूमि और पशुधन धारिता तथा कृषक परिवारों की स्थिति का आकलन' सर्वेक्षण है।
2. सर्वेक्षण ने प्रति कृषक परिवार की औसत मासिक आय में कमी की सूचना दी है।
3. घरेलू स्वामित्व जोत के औसत आकार में गिरावट आई है, इससे भूमि जोत का विखंडन हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Q5. एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई.बी.पी.) कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अधिशेष चावल को एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए उपयोग करने की अनुमति दी है।
- पात्र आसवनियों को ब्याज परिदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. आयात निर्भरता को कम करने तथा सब्सिडी व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस संबंध में और क्या उपाय किए जाने चाहिए।

Q2. फसल विविधीकरण को टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता में कमी करने और किसानों के लिए उच्चतर आय को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा कीजिए।

Emphasis on conceptual clarity to train the aspirants for developing an understanding to solve ethics case study from basic to advance level

Case studies covers all the exclusive topics from contemporary and current issues as well as previous Year UPSC Paper Case studies

To discuss on Various techniques on writing scoring answers.

One to one mentoring session

ETHICS

Case Studies Classes

ADMISSION OPEN

Focus on contemporary issues and interlinking case studies with topics of current interest.

Regular Doubts clearing session and personal guidance for the ethics paper throughout your preparation

Daily Class assignment and discussion

Comprehensive & updated ethics material

अध्याय 8: उद्योग और अवसंरचना (Industry and Infrastructure)

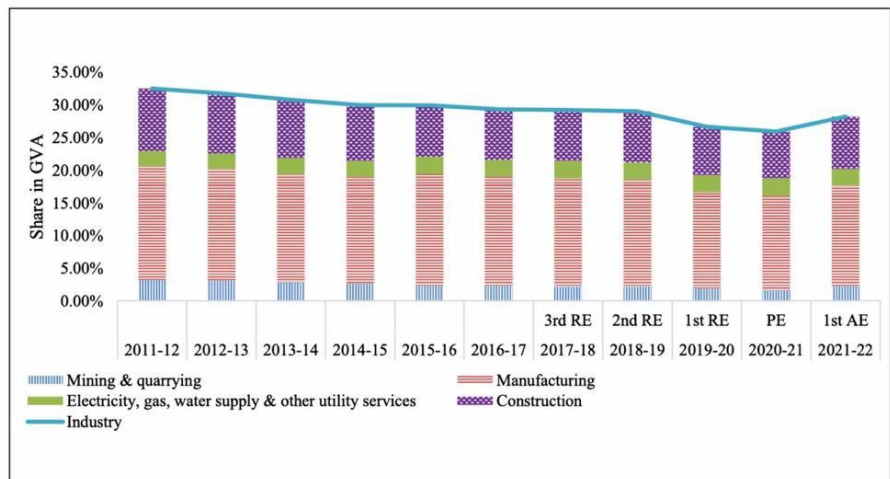
परिचय

- इस अध्याय में इस्पात, कोयला, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों के क्षेत्र-वार विश्लेषण के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र की समग्र स्थिति के संदर्भ में चर्चा की गई है।
- इसमें अवसंरचना क्षेत्रक से जुड़े उपक्षेत्रों जैसे कि सड़क, रेलवे, नागरिक उड्डयन, बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्ग, दूरसंचार, पेट्रोलियम, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है।

औद्योगिक क्षेत्रक का अवलोकन

- वर्ष 2020-21 के दौरान नॉमिनल सकल मूल्य वर्धन या GVA (मौजूदा कीमतों पर) में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 25.9 प्रतिशत रही है।

Share of Industry and its components in Gross value added



Source: Survey calculations based on MoSPI data. Data at current prices.

- वर्ष 2020-21 में केवल विद्युत, गैस, जल-आपूर्ति और अन्य यूटिलिटी सेवाओं जैसे उप-क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।
- औद्योगिक क्षेत्रक की वृद्धि: वर्ष 2020-21 की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए पूर्वानुमान: 11.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ GVA में उद्योग की हिस्सेदारी बढ़कर 28.2 प्रतिशत होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):
 - वर्ष 2020-21 में वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण IIP में 8.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
 - वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार: पिछले वर्ष की समान अवधि (-15.3%) की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021-22 में IIP की वृद्धि दर 17.4 थी।
- आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक⁸⁸: पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि (-11.1 प्रतिशत) की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021-22 के दौरान ICI की वृद्धि दर 13.7 प्रतिशत थी।
 - इस वृद्धि के कारण: यह मुख्य रूप से स्टील, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कोयला और विद्युत के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के कारण संभव हुआ।
 - जबकि उर्वरक और कच्चे तेल में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- क्षमता उपयोग (Capacity utilization: CU): कोविड-19 वैश्विक महामारी के आलोक में लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान इसमें (CU) अत्यधिक गिरावट आई। हालांकि, कोविड-19 की दूसरी लहर (अर्थात् वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही) के दौरान लचीले लॉकडाउन उपायों के कारण यह कम प्रभावित हुआ।
- RBI का कारोबार प्रत्याशा सूचकांक (Business Expectation Index: BEI): वर्ष की पहली तिमाही में वैश्विक महामारी की शुरुआत के कारण वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में यह केवल मामूली गिरावट के साथ स्थिर रहा है। हालांकि, इसके बाद से यह वृद्धिशील बना हुआ है।

⁸⁸ Index of Eight Core Industries: ICI

- **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF):** वर्ष 2019-20 में समग्र GFCF (स्थिर कीमतों पर) और औद्योगिक GFCF में क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- **औद्योगिक क्षेत्र के सकल बैंक ऋण में अक्टूबर 2021 (वर्ष-दर-वर्ष) में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।** हालांकि, अक्टूबर 2020 में 0.7% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।
 - खनन, वस्त्र, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन, रबर, प्लास्टिक और अवसंरचना जैसे कुछ उद्योगों की ऋण संबंधी मांग में वृद्धि की स्थिति में सतत सुधार हुआ है।
- **उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):**
 - वर्ष 2020-21 में 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अनंतिम) का अब तक का उच्चतम वार्षिक FDI अंतर्वाह (inflow) पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान FDI नीति में किए गए सुधार तथा अन्य उपाय	
अधिक विदेशी भागीदारी को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय	• रक्षा क्षेत्र: नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्ति की इच्छुक कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत (पहले 49% थी) तक के FDI की अनुमति प्रदान की गई है। • 74 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक के FDI को सरकारी मार्ग के तहत अनुमति प्रदान की जाएगी।
	• बीमा क्षेत्र: स्वचालित मार्ग के तहत स्वीकृत FDI की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।
	• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र: ऐसे मामलों में जहां सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, वहां स्वचालित मार्ग (automatic route) के तहत 100 प्रतिशत तक FDI की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
	• दूरसंचार क्षेत्र: इस क्षेत्र हेतु स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
अवसरवादी अधिग्रहण / नियंत्रण पर अंकुश	• निवेश करने वाली इकाई या निवेश संबंधी स्वामित्व से लाभप्रद होने वाला कोई भी, जो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश में स्थित हैं, केवल सरकारी मार्ग के तहत ही भारत में निवेश कर सकते हैं। • भारत स्थित किसी इकाई/निकाय में मौजूदा या भावी FDI के स्वामित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करने के लिए भी सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी।
अन्य उपाय	• FDI प्रस्तावों से संबंधित प्रक्रिया / क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया⁸⁹ में संशोधन किया गया है। • आवेदक/निवेशक के साथ आगे की कार्रवाई करने तथा पहचान और बाधाओं, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए FDI निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। • उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य विलंबित प्रस्तावों और प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों द्वारा आगे बढ़ाए गए प्रस्तावों पर उचित निर्णय लेना है।

- **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) का प्रदर्शन:** वर्ष 2019-20 के दौरान 256 CPSEs का निवल परिचालन लाभ 93,295 करोड़ रुपये रहा है।

⁸⁹ Standard Operating Procedure: SOP

नई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSE) नीति के तहत चिन्हित रणनीतिक क्षेत्रक: परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष और रक्षा; परिवहन और दूरसंचार; विद्युत; पेट्रोलियम; कोयला और अन्य खनिज; बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

- सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश के लिए फरवरी 2021 में नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (PSE) नीति को अधिसूचित किया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं-
 - CPSE का वर्गीकरण:
 - रणनीतिक क्षेत्रक (Strategic Sectors): ऐसा क्षेत्रक जहाँ CPSEs की केवल न्यूनतम उपस्थिति को बनाए रखा जाना है।
 - गैर-रणनीतिक क्षेत्रक (Non-Strategic Sectors): जिनका निजीकरण किया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा।
 - इस नीति के दायरे से कुछ CPSEs जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गैर-लाभकारी कंपनियों के रूप में स्थापित CPSEs या समाज के सुभेद्य और कमजोर वर्गों का समर्थन करने वाले CPSEs को छूट प्रदान की गई है।

क्षेत्र-वार प्रदर्शन और पहल

क्षेत्रक	क्षेत्रक से संबंधित विकास	आरंभ की गई पहल
इस्पात	- वर्ष 2021-22 में कच्चे और तैयार इस्पात (स्टील) के संचयी उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 25 प्रतिशत और 28.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। - तैयार इस्पात (स्टील) की खपत में भी इस अवधि में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।	विशिष्ट इस्पात के लिए PLI योजना; घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद⁹⁰ नीति; गुणवत्ता नियंत्रण आदेश⁹¹ जिसमें कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, टिन प्लेट, टिन मुक्त स्टील और स्टेनलेस स्टील शामिल हैं; तथा लौह और "इस्पात क्षेत्रक में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए" एक अनुसंधान एवं विकास योजना को भी आरंभ किया गया है।
कोयला	- यह भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति में इसकी हिस्सेदारी 55% रही है। - अप्रैल-अक्टूबर 2020 में 3.91 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2021 में कोयला उत्पादन में 12.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।	- लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (PSU) द्वारा अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। - निजी क्षेत्र के लिए कोयला खनन को खोलना: 27 कोयला खदानों की नीलामी निजी कंपनियों को की जा चुकी है।
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम	वर्ष 2019-20 के लिए कुल GVA (चालू मूल्य पर) में MSME GVA की हिस्सेदारी लगभग 33.08 प्रतिशत रही है।	- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में MSMEs की परिभाषा में संशोधन किया गया है; - जुलाई 2020 में एक नया उद्यम पंजीकरण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है; - स्ट्रीट वेंडरों या पथ विक्रेताओं सहित खुदरा और थोक व्यापारों को MSMEs के तहत शामिल किया गया है। साथ ही, उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान की गई है और वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण से संबंधित लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। - चैंपियंस पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। यह एक ICT आधारित प्रौद्योगिकी प्रणाली है। इसका उद्देश्य छोटी इकाइयों को

⁹⁰ Domestically Manufactured Iron and Steel Products: DMI&SP

⁹¹ Quality Control Order: QCO

		आवश्यक सहायता प्रदान कर उनके आकार में वृद्धि करना है।
कपड़ा	- यह क्षेत्रक कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता रहा है, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 105 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। - अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान विकास में 3.6 प्रतिशत, जैसा कि IIP से पता चलता है, के योगदान के साथ इस क्षेत्रक ने उल्लेखनीय सुधार को दर्शाया है।	मानव निर्मित फाइबर (MMF) के क्षेत्र और तकनीकी वस्त्रों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को शुरू किया गया है; इसके अतिरिक्त सात प्रधान मंत्री मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क (PM MITRA) की भी स्थापना की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स	लॉकडाउन अवधि के दौरान इस क्षेत्रक से संबंधित मांग में कमी आई थी, हालांकि उसके बाद से यह पुनरुद्धार की दिशा में अग्रसर है।	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 (NPE- 2019) जारी की गई है; - बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना को अधिसूचित किया गया है; - इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमीकंडक्टर विनिर्माण संवर्धन योजना⁹² को आरंभ किया गया है; - संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना को भी लागू किया गया है; - परख - एक एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क: इसके तहत देश में प्रमाणित और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के आधार पर एकीकृत किया गया है।
औषध / फार्मास्युटिकल	- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर फार्मास्युटिकल उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान पर है। वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी के साथ भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। - पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 200% की आकस्मिक वृद्धि देखी गई है। - उच्चतर निर्यात: वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल औषध आयात 7.0 बिलियन यू.एस. डॉलर तथा निर्यात 24.4 बिलियन यू.एस. डॉलर रहा है।	बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने हेतु योजना; बल्क ड्रग, औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को आरंभ किया गया है।

अवसंरचना: यह सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार लाने वाला एक साधन है।

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन⁹³: इसे देश भर में विश्व स्तरीय अवसंरचना या बुनियादी ढांचा प्रदान करने और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आरंभ किया गया है।
 - वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 के दौरान वितरित कुल व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण⁹⁴ की राशि 2,943 करोड़ रुपये है।

⁹² Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors: SPECS

⁹³ National Infrastructure Pipeline: NIP

⁹⁴ Viability Gap Funding: VGF

- राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline NMP): केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए NMP का कुल सांकेतिक मूल्य चार वर्षों की अवधि में 6.0 लाख करोड़ रुपये (NMP के तहत परिकल्पित कुल अवसंरचना निवेश का 5.4 प्रतिशत) रहने का अनुमान लगाया गया है।

क्षेत्र-वार विकास (Sectoral Developments)

सड़क परिवहन:

- सड़क नेटवर्क: मार्च 2019

तक, सड़कों (राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, जिला,

ग्रामीण, शहरी और परियोजनागत सड़कों) का 63.71 लाख कि.मी. का नेटवर्क मौजूद है। इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान रहा है।

- सड़क निर्माण की गति वर्ष 2019-20 में 28 कि.मी. प्रतिदिन थी, जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 36.5 कि.मी. प्रतिदिन हो गई है। यह लगभग 30.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक व्यय में 29.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

- रेलवे: भारतीय रेलवे 68,102 कि.मी.से अधिक मार्गों के साथ तथा एकल प्रबंधन के अधीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है।

- ट्रैफिक: वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, भारतीय रेलवे के माध्यम से 1.23 बिलियन टन माल और 1.25 बिलियन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है।

- सुरक्षा: रेल दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2018-19 में 59 से घटकर 2019-20 में 55 (प्री-कोविड) और पिछले वर्ष 2020-21 में 22 हो गई है।

- वित्त वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़कर 2,15,058 तक कर दिया गया है।

- भारतीय रेलवे (IR) को अपग्रेड करने के लिए आरंभ की गई पहल:

- नई स्वदेशी तकनीकों को अपनाना: जैसे कवच (KAVACH), वंदे भारत ट्रेन और स्टेशनों का पुनः विकास करना।
- किसान रेल: दिसम्बर 2021 तक लगभग 1,841 किसान रेल आरंभ की जा चुकी है और इनके माध्यम से अनुमानित: 6.0 लाख टन फल और सब्जियों सहित शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया गया।
- दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने वाली परियोजनाएं: इसके तहत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन तथा पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए परियोजनाएं चल रही हैं।
- वाई-फाई सुविधा: दिसंबर 2021 तक, कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- राष्ट्रीय रेल योजना: इसके तहत माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 26-27 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 40-45 प्रतिशत तक करना और दिसंबर 2023 तक रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करना है।

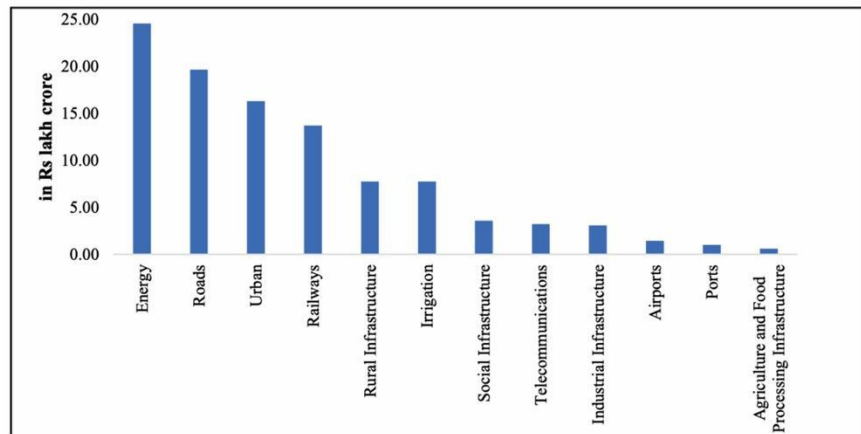
- नागरिक उड्डयन (Civil Aviation): वैश्विक स्तर पर भारत सर्वाधिक तीव्र वृद्धि करने वाले विमानन बाजारों में से एक है।

- घरेलू हवाई यातायात वर्ष 2013-14 में लगभग 61 मिलियन की तुलना में दोगुना से अधिक होकर वर्ष 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया है, जो प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

- उड्डयन/विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई पहल:

- एयर ट्रांसपोर्ट बबल या विशिष्ट देशों के साथ हवाई यात्रा व्यवस्था की शुरुआत;

Industry wise breakup of pipeline



Source: Survey calculations based on data from the Report of the Task Force on National Infrastructure Pipeline for 2019-2025

- एयर-इंडिया का विनिवेश;
- हवाई अड्डों का निजीकरण और आधुनिकीकरण/विस्तार करना;
- क्षेत्रीय संपर्क योजना - UDAN को बढ़ावा देना;
- रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार (MRO) संबंधी परिचालन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना।

विमानन क्षेत्र में निजीकरण

- **एयर इंडिया का विनिवेश:** एयर इंडिया की 100% इक्विटी शेयरधारिता तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एयर इंडिया SATS की इक्विटी शेयरधारिता को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को प्रदान किया गया है।
- **हवाई अड्डों का निजीकरण:**
 - परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और बंगलुरु नामक 6 हवाई अड्डों को सबसे ऊँची बोली लगाने वालों को प्रदान किया है।
 - राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (NMP) के अनुसार, 25 AAI हवाई अड्डों को वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक संपत्ति मौद्रिकरण के लिए चिह्नित किया गया है।

पत्तन या बंदरगाह

- मार्च 2021 के अंत तक 13 प्रमुख पत्तनों की क्षमता मार्च 2014 की तुलना में 79 प्रतिशत बढ़कर 1,560.61 MTPA हो गई है।
- वैश्विक महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वव्यापी व्यवधान के कारण वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के मध्य प्रमुख पत्तनों के माध्यम से होने वाले यातायात में 4.57 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- प्रमुख पत्तनों का औसत टर्नअराउंड समय (बंदरगाह पर पोत के आगमन और प्रस्थान के बीच लगने वाला समय) वर्ष 2019-20 में 62.11 घंटे से घटकर वर्ष 2020-21 में 55.99 घंटे हो गया है।
- भारतीय पोतों का बेडा, विश्व के पोत बड़े का मात्र 1.2 प्रतिशत है और भारत के आयात-निर्यात व्यापार में इसकी भागीदारी केवल 7.8 प्रतिशत (2018-19 के लिए) है।
- **सरकार द्वारा की गई पहल:**
 - भारत में वाणिज्यिक पोतों की कैलेगिंग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और CPSEs द्वारा जारी की गई वैश्विक निविदाओं में भारत की शिपिंग/पोत-परिवहन कंपनियों को पांच वर्षों की अवधि के दौरान सब्सिडी सहायता प्रदान करने वाली योजना को आरंभ किया गया है।
 - **सागरमाला** नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह का विकास करना, कनेक्टिविटी में वृद्धि करना, बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण, तटीय सामुदायिक विकास, तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना है।
 - प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और नियोजन के लिए **प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021** को अधिनियमित किया गया है।
 - रियायत अवधि के नवीनीकरण, विस्तार के दायरे और गतिशील कारोबारी माहौल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए **बंदरगाह निर्भर उद्योगों के लिए कैप्टिव नीति** तैयार की गई है।
 - अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित और त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में **मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (MIV 2030)** को जारी किया गया है।

पी.एम. गति शक्ति

- यह लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए मल्टी-मॉडल और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाली एक एकीकृत योजना है।
- इसमें 16 मंत्रालय और अवसंरचना से संबंधित पहल जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/स्थल बंदरगाह, उड्डान आदि शामिल हैं।
- इसमें अस्पतालों और विश्वविद्यालयों जैसे सामाजिक अवसंरचना को भी शामिल किए जाने की सम्भावना है।

- **अंतर्देशीय जलमार्ग:** इसके संबंध में उठाए गए कदम-
 - अंतर्देशीय जल के माध्यम से किफायती, सुरक्षित परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए **अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021** के माध्यम से **विनियामक संबंधी संशोधन** किए गए हैं। यह अधिनियम अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेगा।
 - राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (NW -1) की नौपरिवहन क्षमता में वृद्धि के लिए गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के वाराणसी से हल्दिया खंड तक **जल मार्ग विकास परियोजना** को लागू किया जा रहा है।
 - इसके तहत वाराणसी और साहिबगंज में **मल्टी-मॉडल टर्मिनलों** के निर्माण किया जा चुका है।
 - हल्दिया में **मल्टीमॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक** में पर्याप्त प्रगति हुई है।
- **दूरसंचार (Telecom):** भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है।
 - भारत में कुल टेलीफोन ग्राहक आधार: यह मार्च 2021 तक 1200.88 मिलियन हो गया है।
 - ग्रामीण-शहरी भागीदारी: मार्च 2021 में 45 प्रतिशत ग्राहक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और 55 प्रतिशत ग्राहक शहरी क्षेत्रों में थे।
 - **नैरोबैंड-ब्रॉडबैंड की भागीदारी:** जून 2021 में केवल 4 प्रतिशत उपभोक्ताओं / ग्राहकों के पास नैरोबैंड और 96 प्रतिशत के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध थे।
 - **औसत वायरलेस डेटा उपयोग:** वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह डेटा उपयोग बढ़कर 14.1 GB हो गया है, हालांकि यह वित्तीय वर्ष 2018 की पहली तिमाही में केवल 1.24 GB प्रति माह प्रति उपयोगकर्ता था।
 - **पहल:**
 - **भारतनेट परियोजना:** 5.46 लाख कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है और कुल 1.73 लाख ग्राम पंचायतों (GP) को ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) से जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, **4173 ग्राम पंचायतों को उपग्रह आधारित मीडिया के माध्यम से जोड़ा जा चुका है।**
 - पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ और वंचित गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (Comprehensive Telecom Development Plan: CTDP)** और द्वीपों के लिए **व्यापक दूरसंचार विकास योजना (CTDP)** को आरंभ किया गया है।

दूरसंचार क्षेत्र में सुधार

संरचनात्मक सुधार:

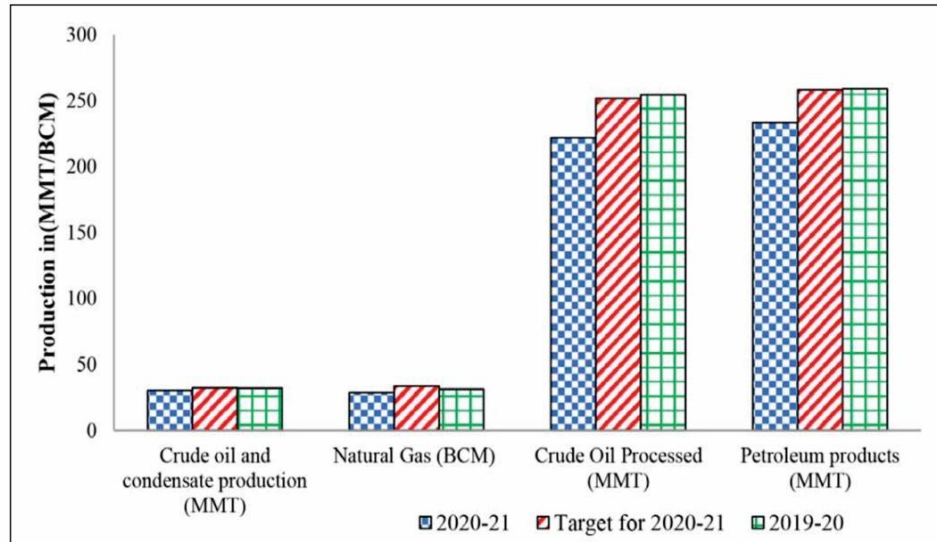
- समायोजित सकल राजस्व, बैंक गारंटी (BG) से संबद्ध लाइसेंस शुल्क (LF), व्याज दरों और दंड को **युक्तिसंगत** बनाया गया है।
- **भविष्य की नीलामी में सुधार:**
 - किस्त भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए किसी बैंक गारंटी (BG) की अनिवार्यता नहीं होगी।
 - स्पेक्ट्रम आवंटन की अवधि को 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष किया गया है।
 - नीलामी में हासिल किए गए स्पेक्ट्रम के लिए 10 वर्षों की अवधि के बाद स्पेक्ट्रम का समर्पण करने की अनुमति होगी।
 - नीलामी में हासिल किए जाने वाले स्पेक्ट्रम पर कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) आरोपित नहीं किया जाएगा।
- **स्पेक्ट्रम साझाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा:** स्पेक्ट्रम साझाकरण पर आरोपित 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त SUC को हटा दिया गया है।

प्रक्रियात्मक सुधार:

- **कारोबार करने की सुगमता (Ease of doing business):** नीलामी कैलेंडर का निर्धारण, सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत वायरलेस उपकरणों के लिए लाइसेंस के स्व-घोषणा पत्र की अनुमति प्रदान की गई है।
- अपने ग्राहकों को जानने (KYC) सम्बन्धी सुधार: ऐप आधारित स्व-के.वाई.सी. की अनुमति प्रदान की गई है।
- ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र (Customer Acquisition Forms: CAF) का डिजिटलीकरण किया गया है।
- रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन (SACFA) संबंधी स्थायी सलाहकार समिति ने दूरसंचार टावरों के लिए मंजूरी में ढील प्रदान की है।
- **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) की चलनिधि संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करना:**
 - AGR निर्णय से उत्पन्न होने वाले देय राशि के वार्षिक भुगतान में चार वर्ष तक का स्थगन/मोहलत प्रदान की गई है।
 - उक्त स्थगन/मोहलत के तहत TSPs को मूलधन और व्याज राशि का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया गया है इसके तहत TSPs इक्विटी के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं।

- पेट्रोलियम, कच्चा और प्राकृतिक गैस (Petroleum, Crude and Natural gas): भारत अपनी 80 प्रतिशत से अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है।

Production of Petroleum, crude and natural gas

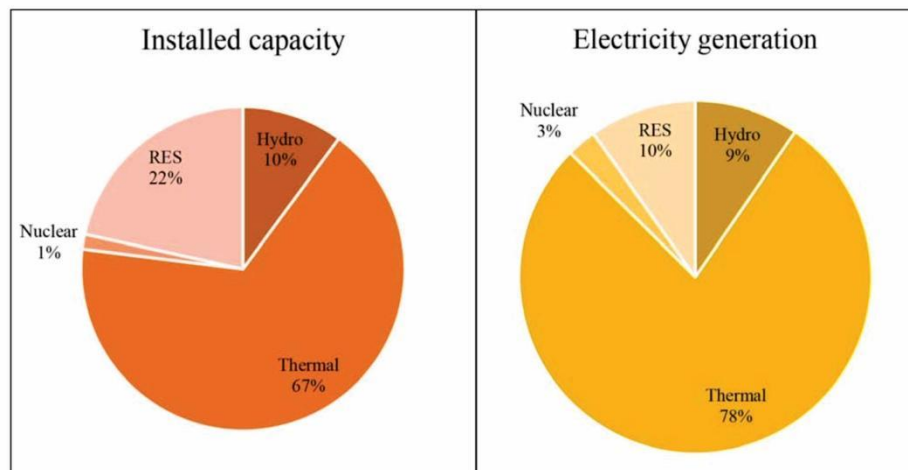


Source: M/o PNG

अनियोजित कामबंदी और कुछ उत्पादक कुओं से परिचालन संबंधी घाटा और COVID-19 के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी को उत्तरदायी माना जा सकता है।

- पहल:

Source of Installed Capacity and electricity generation 2020-21



Source: Survey Calculations based on data from Central Electricity Authority. Includes both Utilities and captive plants. Thermal includes gas, steam and diesel.

- उज्ज्वला 2.0 को अखिल भारतीय स्तर पर आरंभ किया गया है जिसके तहत अतिरिक्त एक करोड़ LPG कनेक्शन मुफ्त फर्स्ट रिफिल और स्टोव के साथ प्रदान किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड और शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ना: विश्व बैंक की रिपोर्ट 'मिनरल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन'

- निवल-शून्य कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शमन कार्रवाई हेतु सुझाव:
 - ऑन-डिमांड ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौर फोटोवोल्टिक और पवन ऊर्जा से क्रमिक (intermittent) विद्युत उत्पादन के लिए भंडारण क्षमता का सृजन करना।
 - आवश्यक खनिजों की आपूर्ति के लिए तैयार रहना: खनिज और धातु जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, लोहा, मैंगनीज, निकल आदि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
 - ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने की दिशा में सहज बदलाव सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही, खनिजों के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और पुनः प्रयोज्यता को सुनिश्चित करने वाली विकासशील प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
 - ऊर्जा के स्रोतों के विविधीकरण मिश्रण को बढ़ावा देना चाहिए।

• विद्युत (Electricity):

- वर्ष 2021 में कुल स्थापित विद्युत क्षमता और कैप्टिव पावर प्लांट (1MW और उससे अधिक की मांग वाले उद्योग) क्षमता लगभग 459.15 GW थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.87 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा: देश की स्थापित कुल विद्युत क्षमता में नवीकरणीय उर्जा अर्थात सौर, पवन, बायोमास और लघु जलविद्युत ऊर्जा की हिस्सेदारी 24.71 प्रतिशत से अधिक है तथा वर्ष 2020-21 के दौरान विद्युत ऊर्जा उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी लगभग 10.7 प्रतिशत रही है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान रूपांतरण, पारेषण और वितरण में ऊर्जा हानि अखिल भारतीय स्तर पर 20.46 प्रतिशत थी (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह उच्चतम अर्थात 29.98 प्रतिशत थी)।
- पहल:
 - हरित ऊर्जा गलियारा⁹⁵ को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर और पवन से उत्पादित विद्युत को ग्रिड के माध्यम से पारंपरिक विद्युत स्टेशनों के साथ सिंक्रनाइज़ करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है।
 - सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक के माध्यम से तिमाही ऊर्जा लेखांकन को अनिवार्य कर दिया है।

शब्दावली	
आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) का सूचकांक	यह कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत जैसे निर्धारित आठ प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के सामूहिक रूप से और एकल आधार पर प्रदर्शन को मापता है। IIP भारांश में इनकी हिस्सेदारी 40.27 प्रतिशत है।
क्षमता का उपयोग (CU)	विद्युत उत्पादन के संदर्भ में क्षमता उपयोग वह प्रतिशत है जो दर्शाता है कि एक उत्पादन इकाई ने विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अपनी क्षमता को किस सीमा तक पूरा किया है।
आर.बी.आई. का कारोबार प्रत्याशा सूचकांक (BEI)	यह सूचकांक मापदंडों के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थिति की झलक प्रदान करता है। इन मापदंडों में समग्र व्यावसायिक स्थिति, उत्पादन, ऑर्डर बुक, कच्चे माल की सूची और तैयार माल, लाभ संबंधी मार्जिन, रोजगार, निर्यात और क्षमता का उपयोग शामिल होते हैं।
सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF)	यह मशीनरी और उपकरण, अमूर्त संपत्ति जैसी अचल संपत्तियों का सकल योग है जो अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थिति को इंगित करता है।

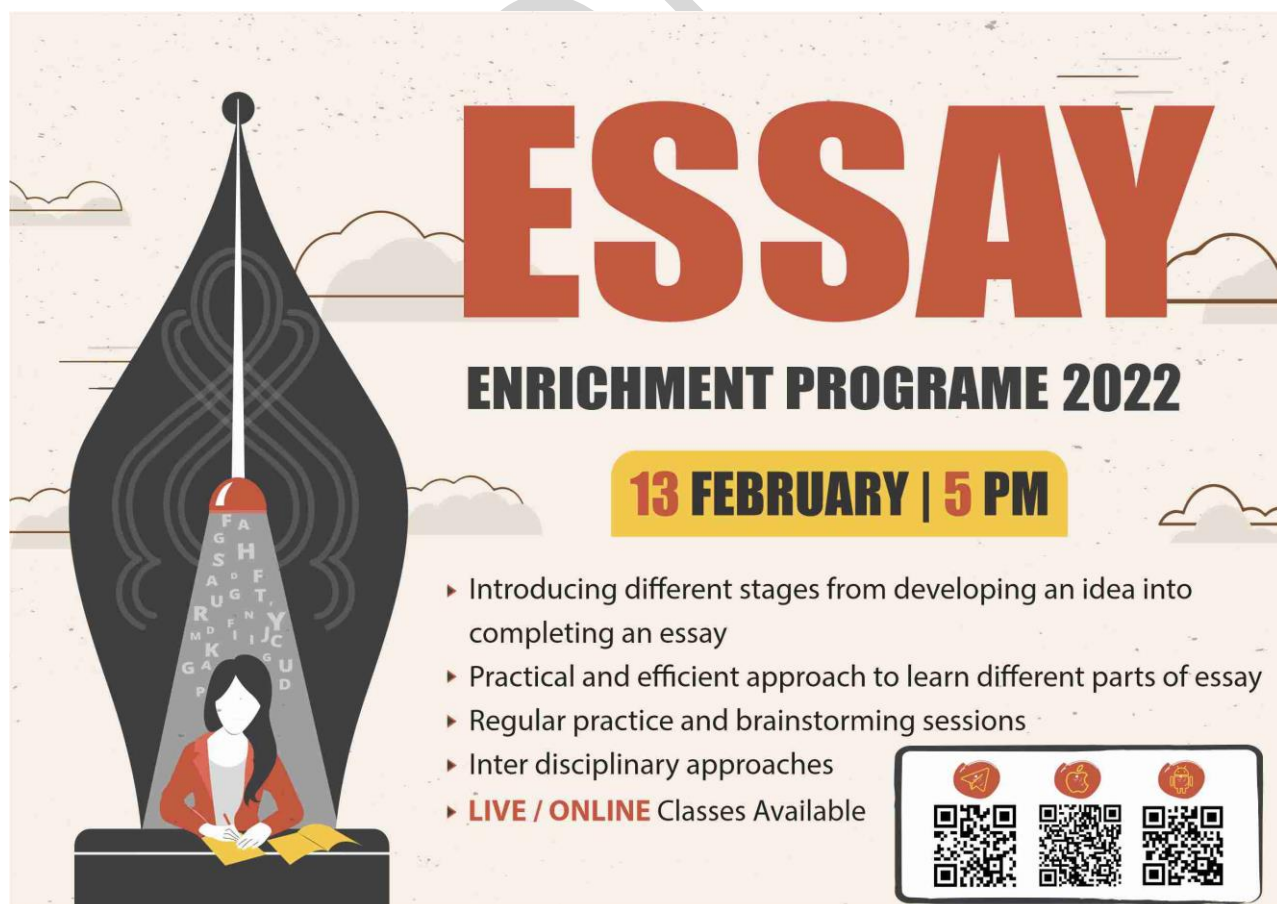
अध्याय एक नज़र में
अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे खुलने, रिकॉर्ड टीकाकरण, उपभोक्ता मांग में सुधार, आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में सरकार द्वारा उद्योगों को निरंतर नीतिगत समर्थन और वर्ष 2021-22 में आगे सुदृढीकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
जैसा कि IIP की संचयी वृद्धि में परिलक्षित होता है औद्योगिक प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
समग्र कारोबारी धारणा में सुधार के साथ उच्च FDI अंतर्वाह, उद्योग के लिए सकारात्मक परिदृश्य की संभावना को इंगित करते हैं।
उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को आरंभ करना; आधारभूत संरचना- भौतिक एवं डिजिटल दोनों आधार पर-को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों; साथ ही लेन-देन की लागत को कम करने और कारोबार करने की सुगमता में सुधार के लिए किए जाने वाले निरंतर उपायों से अंततः पुनर्बहाली की गति को सहायता मिलेगी।

⁹⁵ Green Energy Corridor: GEC

अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP), राष्ट्रीय मुद्राकरण योजना (NMP) जैसी कई पहलों को आरंभ किया गया है।

भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि की गई है।

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया है और दूरसंचार क्षेत्र में भी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार किए गए हैं।



ESSAY

ENRICHMENT PROGRAMME 2022

13 FEBRUARY | 5 PM

- ▶ Introducing different stages from developing an idea into completing an essay
- ▶ Practical and efficient approach to learn different parts of essay
- ▶ Regular practice and brainstorming sessions
- ▶ Inter disciplinary approaches
- ▶ **LIVE / ONLINE** Classes Available



अध्याय-8



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसने विगत पांच वर्षों में सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) में ऋणात्मक वृद्धि नहीं दर्शाई है?

- (a) खनन और उत्खनन
- (b) विनिर्माण
- (c) विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता आधारित सेवाएं
- (d) निर्माण कार्य

Q2. कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कई सुधार कार्य किए गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस/किन क्षेत्र/क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की सीमा 49 प्रतिशत से अधिक कर दी गई है?

- 1. रक्षा क्षेत्र
- 2. बीमा क्षेत्र
- 3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Q3. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के संचालन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. वर्ष 2019-20 के दौरान CPSEs का निवल लाभ पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
- 2. वर्तमान में देश में 100 से भी कम CPSEs संचालन में हैं।
- 3. नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (PSE) नीति के अनुसार, बैंकिंग को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Q4. औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. औद्योगिक क्षेत्र जी.वी.ए. में निर्माण का हिस्सा खनन और उत्खनन क्षेत्र से अधिक है।
- 2. औद्योगिक क्षेत्र जी.वी.ए. में विनिर्माण का सबसे बड़ा हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Q5. भारत में फार्मास्युटिकल क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा की दृष्टि से फार्मास्युटिकल उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। दी है।
2. वैश्विक आपूर्ति में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
3. वर्ष 2020-21 के लिए फार्मा निर्यात का मूल्य 20 अरब डॉलर से अधिक रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

Q6. भारत में पोत परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्तमान में भारत में 11 प्रमुख पत्तन हैं।
2. विश्व के कुल बेड़े के प्रतिशत के रूप में भारतीय पोत परिवहन बेड़े का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत तक है।
3. पत्तन आश्रित उद्योगों के लिए कैप्टिव नीति को समाप्त कर दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 3

Q7. बिजनेस एक्सपेक्टेडेशन इंडेक्स (बी.ई.आई.) विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थिति का एक अनुमान प्रदान करता है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है?

- (a) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
- (b) भारतीय रिज़र्व बैंक
- (c) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
- (d) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. दूरसंचार क्षेत्र ने कोविड काल के दौरान चुनौतियों का सामना करने में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि न केवल दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार करने की आवश्यकता है, बल्कि इसमें संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार लाने के लिए कई उपाय करने की भी आवश्यकता है।

Q2. विदेशी भागीदारी में सुधार, अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने और निगरानी एवं कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और युक्तिकरण बढ़ाने हेतु एफ.डीआई. नीति में लाए गए सुधारों पर टिप्पणी कीजिए।

अध्याय 9: सेवाएं (Services)

परिचय

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, कोविड-19 के कारण सभी क्षेत्रों की तुलना में यह क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। साथ ही, सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव सेवाओं की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग रहा है। ध्यातव्य है कि समग्र रूप से अब सेवा क्षेत्र कोविड-19 संबंधी प्रभावों से काफी हद तक उबर चुका है और इसमें वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 10.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, कुछ उप-क्षेत्र अब भी प्रभावित हैं।

कोविड-19 का प्रभाव और क्रमिक पुनर्हाली

- उप-क्षेत्रों पर विविध प्रभाव: कोविड-19 के दौरान संपर्क-रहित सेवाएं जैसे कि सूचना, संचार, वित्तीय, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाएं लचीली बनी रहीं, जबकि पर्यटन, खुदरा व्यापार, होटल, मनोरंजन और मनोविनोद आदि जैसी संपर्क-आधारित सेवाओं पर कोविड-19 का प्रभाव अत्यंत गंभीर रहा है।
- सेवा क्षेत्र में संकुचन: 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं' से संबंधित सेवा उप-क्षेत्रों में 18.2 प्रतिशत का तीव्र संकुचन दर्ज किया गया है। इसके कारण वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत का संकुचन हुआ।
- सेवा क्षेत्र द्वारा सकल मूल्य वर्धन (GVA): भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के 55 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 53 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, निकट अवधि में ओमीक्रॉन वेरिएंट के प्रसार एवं व्यापक अनिश्चितता के बावजूद भी वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र के GVA में 8.2 प्रतिशत बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है।
 - कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी व्यय में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं' सहित सेवा उप-क्षेत्र के GVA में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

उच्च आवृत्ति संकेतकों से संबंधित रुझान (Trends in High Frequency Indicators)

- क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI), सेवा सूचकांक, माल यातायात (रेल, हवाई और बंदरगाह) और यात्री यातायात जैसे संकेतकों में हुई वृद्धि की स्थिति आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता को इंगित करती है। इसी संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:
 - सेवा संबंधी क्रय प्रबंधक सूचकांक (Services PMI): मार्च 2020 के शुरुआती संकुचन के बाद, विगत 10 वर्षों में सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन करते हुए सेवा संबंधी PMI अक्टूबर 2021 में 58.4 हो गया और दिसंबर 2021 में थोड़ी गिरावट के साथ यह 55.5 हो गया।
 - माल ढुलाई: भारतीय रेलवे ने वैश्विक महामारी-पूर्व (वर्ष 2019-20) अवधि की तुलना में माल ढुलाई में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
 - यात्री यातायात: जहाँ हवाई यात्री यातायात धीरे-धीरे वैश्विक महामारी-पूर्व के स्तर की ओर अग्रसर है वहीं रेलवे यात्री यातायात अभी भी वैश्विक महामारी-पूर्व के स्तर से काफी नीचे बना हुआ है।
- सेवा क्षेत्र के तहत बैंक से ऋण लेने संबंधी वृद्धि में गिरावट देखी गई है। इसके लिए मुख्य रूप से 'पर्यटन, होटल और रेस्तरां', 'ट्रांसपोर्ट संचालकों' और व्यापार (खुदरा और थोक दोनों) की ऋण संबंधी मांग में कम वृद्धि उत्तरदायी है।
- कॉर्पोरेट्स ने अब तक (वर्ष 2021-22 में) बैंकिंग पूंजी की तुलना में पूंजी बाजारों के माध्यम से अधिक धन जुटाया है। (अधिक विवरण/जानकारी के लिए अध्याय 4- मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता का संदर्भ ले सकते हैं)।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी (Services Sector Share at the State and UT Level)

33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि कोविड-19 वैश्विक महामारी और आवाजाही संबंधी प्रतिबंधों के कारण, वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र GSVA में गिरावट आई है।

- सेवा GSVA में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शीर्ष योगदानकर्ता हैं।

सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह (FDI Inflows into Services Sector)

- सेवा क्षेत्र, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत वर्ष 2020 में FDI का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। इस प्रकार भारत ने वर्ष 2019 की (नौवें स्थान से) अपनी रैंकिंग में चार स्थानों का सुधार करते हुए पांचवां स्थान प्राप्त किया है।

सेवा क्षेत्र में व्यापार (Trade in Services Sector)

सेवा निर्यात (Services Exports)

- वैश्विक परिदृश्य और भारत की हिस्सेदारी: वर्ष 2020 में वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक व्यापार में गिरावट दर्ज की गई है।

विश्व व्यापार

संगठन (WTO) ने

यह संभावना व्यक्त

की है कि वर्ष

2021 में वैश्विक

सेवाओं का

व्यापार, वस्तु

व्यापार की तुलना

में धीमी गति से

वढेगा।

- वैश्विक

सेवाओं के

निर्यात (4.1% हिस्सेदारी) में भारत का प्रमुख स्थान रहा है। यह वर्ष 2020 के शीर्ष दस सेवा निर्यातक देशों में शामिल रहा है।

- विभिन्न सेवाओं पर प्रभाव: भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात (कुल सेवाओं के निर्यात में 48.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ) कोविड-19 अवधि के दौरान अपेक्षाकृत लचीला रहा है। यह स्थिति वैश्विक महामारी संबंधी नई चुनौतियों के लिए डिजिटल समर्थन, क्लाउड सेवाओं और अवसंरचना के आधुनिकीकरण की उच्च मांग के कारण थी। हालाँकि, आवागमन संबंधी प्रतिबंधों के कारण यात्रा निर्यात पर इसका प्रभाव 2020-21 में लगभग 72 प्रतिशत की गिरावट के साथ बेहद गंभीर रहा है।

- समग्र रूप से, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में सेवाओं के निर्यात में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- सेवा निर्यात बनाम पण्य निर्यात: वस्तु (पण्य) निर्यात की तुलना में भारत के सेवाओं के निर्यात पर कोविड -19 का प्रभाव कम गंभीर रहा है।

- सेवा आयात: मुख्य रूप से यात्रा और परिवहन भुगतान में गिरावट के कारण सेवा निर्यात की तुलना में वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा सेवाओं के आयात में 8.4 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख सेवाएं: उप-क्षेत्रवार प्रदर्शन और हालिया नीतियां

उप-क्षेत्र	प्रदर्शन	प्रमुख सरकारी नीतियां/पहल
पर्यटन	यात्रा संबंधी प्रतिबंध, उपभोक्ता विश्वास में कमी और कोविड -19 प्रसार को रोकने के लिए किए गए वैश्विक प्रयास के चलते वर्ष 2020-21 में विदेशी पर्यटकों के आगमन तथा पर्यटन से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा आय में लगभग 75% की कमी आई है।	- बंदे भारत मिशन: प्रवासियों को स्वदेश वापसी में मदद करने के लिए इस मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की गई हैं। - ट्रांसपोर्ट बबल (Transport Bubble): भारत ने 35 देशों के साथ ट्रांसपोर्ट बबल जैसी व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत 47,000 से अधिक इनबाउंड और आउटबाउंड उड़ानों के माध्यम से 63.55 लाख से अधिक यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान की गई है। - ट्रांसपोर्ट बबल वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन की स्थिति में दो देशों के मध्य की गई अल्पकालिक हवाई यात्रा व्यवस्था को संदर्भित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी-व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन (IT-BPM Services)	NASSCOM के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान IT-BPM राजस्व में 2.26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ IT-BPM राजस्व (ई-वाणिज्य को छोड़कर) बढ़कर 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही इस दौरान इसमें 1.38 लाख कर्मचारी भी शामिल हुए हैं।	- अन्य सेवा प्रदाता संबंधी विनियमों में छूट दी गई है (अधिक विवरण के लिए बॉक्स 1 का संदर्भ लें), - दूरसंचार क्षेत्रक में सुधार किए गए हैं, - उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 को लागू किया गया है।
अंतरिक्ष	- अंतरिक्ष क्षेत्रक से संबंधित सभी क्षेत्रों की क्षमताओं को विकसित करने के प्रयास किए गए हैं। इसमें स्वदेशी अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली; अंतरिक्ष संपत्ति उपग्रह संचार मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और नेविगेशन; जमीनी अवसंरचना आदि शामिल हैं। - इस क्षेत्रक में, निजी क्षेत्रक की भागीदारी बढ़ रही है। यह बढ़ती न केवल पारंपरिक विक्रेता भूमिका में बल्कि एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में भी हो रही है। - अंतरिक्ष क्षेत्रक में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2019 में 11 से बढ़कर वर्ष 2021 में 47 हो गई है। - अंतरिक्ष संबंधी अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत है। यह प्रमुख अभिकर्ताओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत कम है।	- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को सशक्त बनाया जा रहा है। यह अंतरिक्ष क्षेत्रक में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। NSIL को इसरो के परिचालनरत प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष संपत्तियों का 'स्वामित्व' प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। - अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACE) का गठन किया गया है। यह NGPEs (गैर-सरकारी / निजी संस्थाओं) के सहयोग के साथ भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रमोटर और विनियामक के रूप में कार्य करेगा। - स्पेसकॉम और स्पेस रिमोट सेंसिंग (SpaceCom and SpaceRS) नीतियों द्वारा पारंपरिक उपग्रह संचार और सुदूर संवेदन क्षेत्रों में और अधिक उदारीकरण किया गया है। - उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 (विवरण के लिए बॉक्स 2 देखें)।
स्टार्टअप	- वर्ष 2021 के दौरान, सरकार ने 14,000 से अधिक नए स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की है। (कुल 61,400 से अधिक स्टार्टअप) - मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की सर्वाधिक संख्या (11,308) महाराष्ट्र में है। - यू.के. को पीछे छोड़ते हुए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद यूनिफॉर्म स्टार्टअप्स की तीसरी सर्वाधिक संख्या वाला देश बन गया है।	- स्टार्ट अप इंडिया के तहत हैंड होल्डिंग, कर संबंधी लाभ, आर्थिक प्रोत्साहन और इनक्यूबेशन संबंधी अवसर शामिल हैं। - अन्य योजनाओं में स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, अटल नवप्रवर्तन/इनोवेशन मिशन आदि शामिल हैं।
पेटेंट	- भारत में दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या वर्ष 2010-11 में 39,400 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 58,502 हो गई है और इसी अवधि के दौरान भारत में प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या 7,509 से बढ़कर 28,391 हो गई है। - इसके अलावा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजाए भारतीय निवासियों द्वारा किए गए पेटेंट आवेदनों की संख्या में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है। - परिणामस्वरूप, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 35 स्थान का सुधार हुआ है। इस प्रकार भारत की रैंकिंग वर्ष 2015-16 में 81वें स्थान से वर्ष 2021 में 46वीं हो गई है।	- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति: रचनात्मक भारत, अभिनव भारत पहल। - स्टार्ट-अप को बौद्धिक संपदा संरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए योजना को आरंभ किया गया है। - राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद, रक्षा उत्पादन विभाग और फिक्की में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र की स्थापना।

बॉक्स 1

अन्य सेवा प्रदाता (OSPs) से संबंधित विनियमों में ढील

OSPs के बारे में: अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके टेली-मेडिसिन, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जैसी सेवाओं और अन्य आई.टी. सक्षम सेवाओं को संचालित करने वाली आई.टी. और आई.टी. आधारित सेवा कंपनियों को अन्य सेवा प्रदाता (OSPs) के रूप में पंजीकृत किया जाता था। इन अन्य सेवा प्रदाताओं को OSP विनियमों के कठोर दायित्वों का अनुपालन करना होता था।

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है:

- **OSP की स्पष्ट परिभाषा:** नए दिशा-निर्देश केवल उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो अपने ग्राहकों को "वॉयस आधारित बी.पी.ओ. सेवाएं" प्रदान करती हैं।
- OSP केंद्रों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- बैंक गारंटी की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
- एक एकल OSP श्रेणी की शुरुआत के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय OSPs के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया है।
- घर से कार्य करने और दूरस्थ स्थानों से कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- OSP के मध्य इंटरकनेक्टिविटी की अनुमति प्रदान की गई है।
- अवसंरचना का साझाकरण: अब OSPs को आपस में अवसंरचना को साझा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

बॉक्स 2

ड्रोन नियम, 2021

सरकार ने मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2021 को अत्यधिक कठोर और प्रतिबंधात्मक के आधार पर निरस्त कर दिया था।

हालांकि अब इसकी जगह उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 को लागू किया गया है।

ड्रोन नियम 2021 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विनिर्माण प्रमाण पत्र आदि जैसी कई अनुमोदन आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, भरे जाने वाले कुल प्रपत्रों (फार्मों) की संख्या को 25 से घटाकर 5 कर दिया गया है।
- शुल्क की संख्या को 72 से घटाकर 4 कर दिया गया है।
- नियम के लागू होने के दायरे को बढ़ाया गया है: इसके तहत 500 किलोग्राम तक के ड्रोन को अब नियमों के अधीन लाया गया है, जबकि पहले निर्धारित सीमा 300 किलोग्राम थी।
- सरलीकृत और सुलभ प्रमाणन प्रक्रिया: डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस को जारी करने से पहले सुरक्षा संबंधी मंजूरी (security clearance) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- ड्रोन संचालन क्षेत्र का विस्तार किया गया है: ग्रीन श्रेणी के तहत स्वतंत्र रूप से सुलभ हवाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए रेड, येलो और ग्रीन जोन की परिधि को उदार बनाया गया है।
- भारत में ड्रोन संचालन करने के लिए विदेशी कंपनियों को छूट प्रदान की गई है।
- माइक्रो ड्रोन और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- आर्थिक दंड को कम करते हुए 5 लाख रुपये से 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

अध्याय एक नज़र में

- कोविड-19 के कारण सेवा क्षेत्रक सबसे अधिक प्रभावित हुआ है साथ ही सेवा संबंधी उप क्षेत्रों पर भी इनका विविध प्रभाव रहा है। हालांकि, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में समग्र रूप से 10.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस क्षेत्रक के तहत अधिकांश क्षेत्रों में सुधार हुआ है।
- वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्रक के GVA में 8.2% की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- वर्ष 2020-21 में विदेशी पर्यटकों के आगमन और पर्यटन से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा संबंधी आय दोनों में लगभग 75% की कमी आई है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र वाला देश बन गया है।

- वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग वर्ष 2015-16 में 81 से बेहतर होकर वर्ष 2021 में 46वें स्थान पर पहुंच गई है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान 1.38 लाख कर्मचारियों को शामिल करते हुए IT-BPM राजस्व में 2.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- भारत में दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या वर्ष 2010-11 में 39,400 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 58,502 हो गई है। इसी अवधि के दौरान प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या 7,509 से बढ़कर 28,391 हो गई है।

अध्याय-9



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सेवा क्षेत्र 25 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है।
 2. वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत है।
 3. सेवा क्षेत्र, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डीआई.) अंतर्वाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 2 और 3
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

Q2. भारत में स्टार्ट-अप्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कर्नाटक में भारत के सबसे अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स हैं।
 2. यूनिफॉर्म स्टार्ट-अप्स की संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

Q3. भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पिछले दो वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स की संख्या 11 से बढ़कर 49 हो गई है।
 2. निजी संस्थाओं द्वारा भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) की स्थापना की गई है।
 3. वर्तमान में विश्व की अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान मात्र 10 प्रतिशत है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Q4. भारत में अनुसंधान और विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाल ही में, भारत में विदेशी कंपनियों की तुलना में भारतीय निवासियों से पेटेंट आवेदनों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है।
 2. भारत में दायर पेटेंट की संख्या वर्ष 2021 में 50,000 से अधिक हो गई थी।
अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान मात्र 10 प्रतिशत है।
 3. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (वर्ष 2021) में भारत को शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Q5. ड्रोन नियम, 2021 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अब 500 किलोग्राम तक के ड्रोन विनियमों के अधीन हैं।
2. विदेशी कंपनियां भारत में ड्रोन संचालन नहीं कर सकती हैं।
3. भारत में नैनो ड्रोन प्रतिबंधित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में सेवा क्षेत्र के भीतर, कोविड-19 महामारी का प्रभाव सेवा की प्रकृति के आधार पर विविध रहा है। विस्तार से चर्चा कीजिए।

Q2. भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण दीजिए और इससे संबंधित सरकारी नीतियों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, ड्रोन नियम, 2021 की प्रमुख विशेषताएं भी वर्णित कीजिए।



CSAT
वलासेस
2022

ENGLISH MEDIUM 11 January
हिन्दी माध्यम 22 December

लाइव/ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

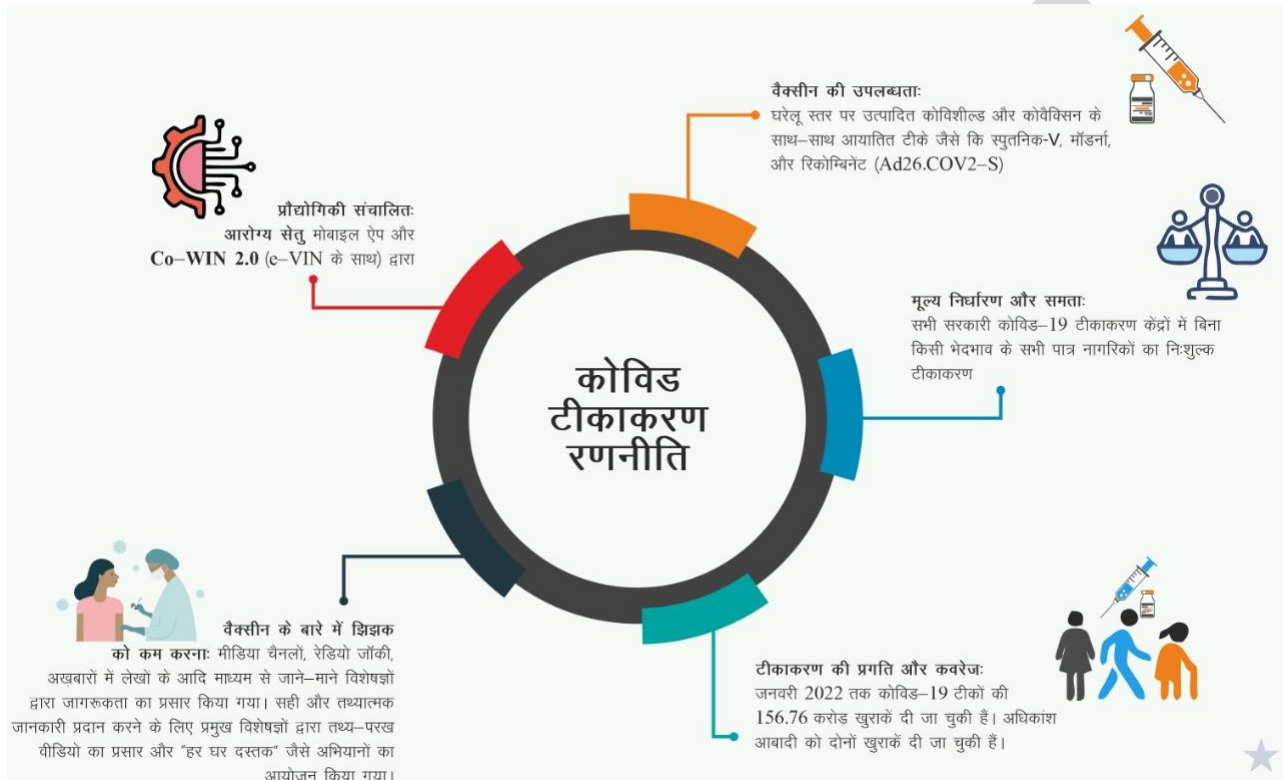
The banner features a central illustration of a human brain with various icons representing different fields of study and technology, including a globe, a lightbulb, a calculator, a clock, a book, a person, a trophy, a rocket, and a computer monitor. Arrows indicate a flow of information and learning.

अध्याय 10: सामाजिक अवसंरचना और रोजगार (Social Infrastructure and Employment)

परिचय

कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए एक मजबूत और लचीली सामाजिक अवसंरचना की अनिवार्यता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, इस दौरान जीवन और आजीविका के संरक्षण हेतु भारत ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है।

कोविड 19 के प्रति भारत की स्वास्थ्य प्रतिक्रिया (India's Health Response to the Covid-19)



कोविड 19 की रोकथाम हेतु आरंभ की गई अन्य पहलें

- लैब नेटवर्क:** भारत ने अब तक 70 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट किए हैं।
- चिकित्सकीय/मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र:** इन संयंत्रों को भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के 'ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम (OBOGS)' की स्पिन-ऑफ तकनीक के आधार पर डिजाइन और विकसित किया गया है।
- ऑक्सी-केयर प्रणाली:** कोविड-19 मरीजों के लिए उपलब्ध मेडिकल ऑक्सीजन का बेहतर रूप से उपयोग करने हेतु रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) ने SPO2 आधारित ऑक्सीजन सिलेंडर कंट्रोलर⁹⁶ सुविधा से युक्त मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर विकसित किए हैं। यह प्रणाली व्यक्ति के SPO2 स्तर के आधार पर ऑक्सीजन की मात्रा की आपूर्ति करती है।
- कोविड-रोधी दवा:** हैदराबाद की डॉ. रेड्डी लैबॉरेटरीज़ के सहयोग से 2 डीऑक्सी-डी-ग्लूकोस (2 DG) नामक दवा को तैयार किया गया है।

सामाजिक क्षेत्रक व्यय से संबंधित रुझान (Trends in Social Sector Expenditure)

- वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान: BE) में,** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्रक पर व्यय हेतु **72 लाख करोड़ रुपए** (सरकार के कुल व्यय का 27 प्रतिशत) निर्धारित किए गए थे। हालांकि, यह व्यय वर्ष 2020-21 की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है।

⁹⁶ SPO2 based Oxygen Cylinder Controller: SPOCC

- पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार के कुल व्यय (केंद्र और राज्यों दोनों को मिलाकर) में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत रहा है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किया गया व्यय (स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य) वर्ष 2014-15 में 6.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 (BE) में 8.6 प्रतिशत हो गया है।

शिक्षा

वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्रक पर व्यय में लगभग 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी (मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.1 प्रतिशत) हुई है।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

विद्यालयों का बुनियादी ढांचा	प्रमुख उपलब्धियां: ● शौचालय (लड़कों या लड़कियों के लिए), पेय जल, और हाथ धोने की सुविधा लगभग अब अधिकतर सरकारी स्कूलों (10.32 लाख) में उपलब्ध है। ● विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और ICT प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और पढ़ाने के लिए ई-सामग्री जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। ● वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2019-20 तक शिक्षकों की उपलब्धता (इसका मापन छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर किया जाता है) में सभी स्तरों पर लगातार सुधार हुआ है।
स्कूल ड्रॉपआउट	● एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) के डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2019-20 में प्राथमिक, उच्चतर-प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूल ड्रॉपआउट की दर में गिरावट दर्ज की गई है। चूंकि शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े केवल वर्ष 2019-20 तक ही उपलब्ध हैं, अतः ऐसे में, वैश्विक महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्रक पर पड़े प्रभावों का आकलन करने के लिए वर्ष 2021 के शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) के आंकड़ों का संदर्भ लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ● वैश्विक महामारी के दौरान ऐसे बच्चों (6-14 वर्ष की आयु), जो वर्तमान में विद्यालय में नामांकित नहीं हैं, की संख्या वर्ष 2018 में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021 में 4.6 प्रतिशत हो गई है। ● ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे निजी विद्यालयों से सरकारी विद्यालयों में चले गए। इसके संभावित कारण कम लागत वाले निजी स्कूलों का परिचालन बंद होना, माता-पिता की आर्थिक तंगी और परिवारों का अपने गांवों में वापस जाना है। ● उच्चतर कक्षा के छात्रों की तुलना में निम्नतर कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन कार्यकलाप करना मुश्किल रहा है।
कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान विद्यार्थियों के लिए प्रमुख पहलें	● पी.एम.-ई विद्या: यह शिक्षा के लिए सुसंगत बहुआयामी पहुंच को सक्षम बनाने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। ● दिव्यांग जनों के लिए: विशिष्ट DTH चैनल और डिजिटल रूप से सुगम्य सूचना प्रणाली⁹⁷ और सांकेतिक भाषा (sign language) जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ● राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला⁹⁸ के ब्लूप्रिंट/रूपरेखा को जारी किया गया या डिजिटल आधारभूत संरचना का सृजन किया गया है। ● विद्याजली पोर्टल: यह समुदाय/स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने के लिए विद्यालयों से संपर्क स्थापित करने और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने में सक्षम बनाता है। इसके साथ ही यह उन्हें विद्यालयों को संपत्ति/सामग्री/उपकरण के रूप में योगदान करने का विकल्प भी प्रदान करता है।

उच्चतर शिक्षा (Higher Education)

उच्चतर शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में आंशिक सुधार के साथ यह वर्ष 2018-19 के 26 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर वर्ष 2019-20 में 27 प्रतिशत हो गया है।

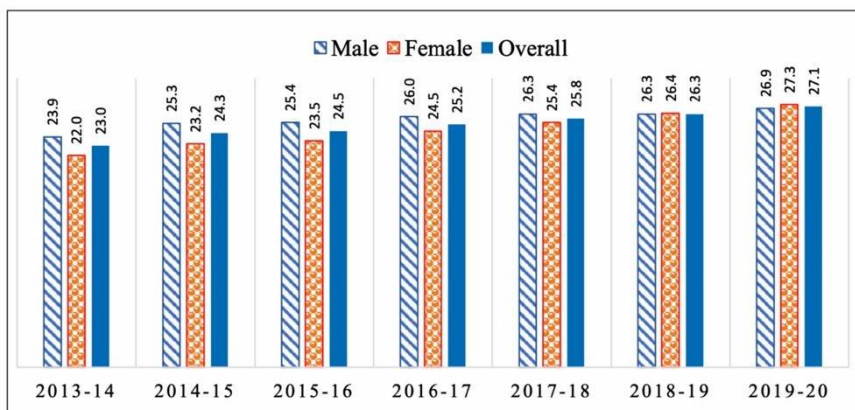
⁹⁷ Digitally Accessible Information System: DAISY

⁹⁸ National Digital Education Architecture: NDEAR

उच्चतर शिक्षा से संबंधित हालिया पहल (Recent Initiatives in Higher Education)

- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना⁹⁹ को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है: यह योजना उभरती तथा अग्रणी तकनीक के क्षेत्र जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तकनीक आदि में प्रशिक्षुता प्रदान करती है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों के अलावा मानविकी, वाणिज्य तथा विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों को भी प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए NATS के दायरे को बढ़ाया गया है।
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट: इस योजना को वर्ष 2021 में आरम्भ किया गया है। यह विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) से अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित करेगी, ताकि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा डिग्री प्रदान करने में इस तरह के अर्जित क्रेडिट की गणना की जा सके।
- ई-पीजी पाठशाला से व्यापक ऑनलाइन मुक्त पाठ्यक्रम (MOOCs) को बढ़ावा मिला है।
- उन्नत भारत अभियान: इस योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षण संस्थानों (केंद्र और राज्य; सार्वजनिक और निजी) को ग्रामीण क्षेत्रों को समझने और वहां काम करने के लिए जोड़ना है।
- कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति जैसी पहल।

Gross Enrolment Ratios in Higher Education for age 18-23 years (in percent)



Source: All India Survey on Higher Education (AISHE) report 2019-20, Ministry of Education

उच्चतर शिक्षा में अग्रतत्पूर बदलाव लाने के लिए पहल सरकार द्वारा की गई

- उच्चतर शिक्षा में व्यावसायीकरण को सक्षम करना
- व्यापक स्तर पर बहु-विषयक शोध को बढ़ावा
- प्रवेश और निकास के कई विकल्प प्रदान करना
- शिक्षा के वैश्वीकरण को बढ़ावा देना
- सभी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण और लर्निंग की प्रक्रिया में ICT की क्षमता का उपयोग करना

कौशल विकास (Skill Development)

वर्ष 2019-20 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण¹⁰⁰ के अनुसार युवाओं (आयु 15-29 वर्ष) और कामकाजी जनसंख्या (आयु 15-59 वर्ष) के मध्य औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार हुआ है, यह वर्ष 2018-19 के 2.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 3.2 प्रतिशत हो गया है।

प्रमुख पहलें (Major initiatives)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मुख्य लक्ष्य	- वर्ष 2025 तक कम से कम 50% स्कूली विद्यार्थियों को व्यावसायिक/पेशेवर शिक्षा प्रदान करना। - ITIs, पॉलीटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ माध्यमिक विद्यालय की भागीदारी को बढ़ाना। - उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशलों में अल्पकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करना। - व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकरण- 'लोक विद्या' के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यावसायिक ज्ञान को विकसित करने हेतु।
--	---

⁹⁹ National Apprenticeship Training Scheme: NATS

¹⁰⁰ Periodic Labour Force Survey: PLFS

	- मुक्त दूरस्थ शिक्षा¹⁰¹ मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। - शिक्षा मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण हेतु राष्ट्रीय समिति¹⁰² का गठन करना। - प्रत्येक विषय, व्यवसाय एवं पेशे के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की स्थापना करना।
स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रमुख व्यवसाय में पुनः कौशल और कौशल वर्धन (re-skilling and up-skilling) पर केंद्रित महत्वपूर्ण पहल।	- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2021-22 के बीच, प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों (PMKKs) के तहत 16.35 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया एवं उनमें से 78 प्रतिशत से अधिक को प्रमाणित किया गया है। - PMKVY के तहत कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों (प्रवासी मजदूरों) को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। (1.26 लाख प्रवासियों को प्रशिक्षित/पुनः व्यवसाय में संलग्न हेतु सक्षम बनाया गया।) - जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना: JSS का उद्देश्य गैर-साक्षर, अल्प साक्षर, शिक्षा के प्राथमिक स्तर तक अर्थात आठवीं तक शिक्षित व्यक्तियों तथा 15-45 आयु-वर्ग में 12वीं तक स्कूल ड्रॉप आउट को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। - राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) - शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS)
आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (Aatmanirbhar Skilled Employees Employer Mapping: ASEEM) पोर्टल	- इसे बाज़ार की मांग के अनुसार कुशल कार्यबल की आपूर्ति को संभव करने के लिए सृजित किया गया था। यह कुशल कार्यबल की डायरेक्टरी के रूप में कार्य करता है। 31.12.2021 तक इस पोर्टल पर लगभग 26.7 लाख प्रवासियों सहित 1.38 करोड़ उम्मीदवारों को पंजीकृत किया जा चुका है।
इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर (IISC) नेटवर्क	यह भारतीय कार्यबल की मांग वाले देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसके द्वारा यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर वृद्धिशील कौशल प्रशिक्षण तथा विदेशी रोज़गार के लिए कौशल संबंधी मूल्यांकन प्रदान करके किया जा रहा है।
प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (PM-DAKSH) योजना	पी.एम. दक्ष योजना अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा सफ़ाई कर्मचारियों सहित वंचित लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए संचालित एक राष्ट्रीय कार्य योजना है।

रोजगार संबंधी रुझान

तिमाही PLFS आंकड़ों पर आधारित शहरी रोजगार संबंधी रुझान {Trends in Urban employment using Quarterly Periodic Labour Force Survey (PLFS) data}

- वर्ष 2021-21 की पहली तिमाही (Q1) में शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी दर बढ़कर 20.8% पहुंच गई थी। हालांकि, वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही तक अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली के साथ बेरोजगारी दर धीरे-धीरे कम होकर 9.3% हो गई है।
 - शहरी क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में भी पहली तिमाही के दौरान भारी गिरावट (क्रमशः 36.4% और 43.7%) दर्ज की गई थी, बाद की तिमाहियों के दौरान इनमें तीव्र सुधार (क्रमशः 47.5% और 43%) हुआ है।
- वर्ष 2020-21 के PLFS आंकड़ों की अनुपलब्धि के कारण, इस सर्वेक्षण में EPFO योजना के तहत सदस्यता और MNREGA के तहत कार्य की मांग जैसे अन्य समरूप घटकों का उपयोग किया गया था।

¹⁰¹ Open Distance Learning: ODL

¹⁰² National Committee for the Integration of Vocational Education: NCIVE

श्रम बल भागीदारी दर¹⁰³: इसे देश की कुल जनसंख्या में श्रमबल के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। श्रम बल का तात्पर्य उन लोगों से है जो या तो कार्यरत (नियोजित) हैं या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिए उपलब्ध (गैर-नियोजित) हैं।

श्रमिक जनसंख्या अनुपात¹⁰⁴: इसे कुल जनसंख्या में रोजगार में संलग्न (नियोजित) व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

बेरोजगारी दर¹⁰⁵: इसे श्रमबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेरोल डेटा पर आधारित शहरी रोजगार संबंधी रुझान {Trends in Urban Employment using Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) Payroll Data}

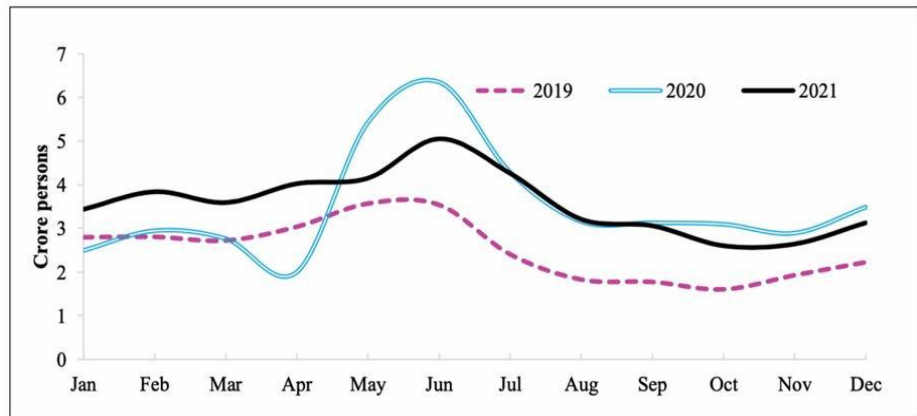
- EPFO आंकड़े के तहत औपचारिक क्षेत्र के मध्यम एवं बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को शामिल किया जाता है। EPFO की सदस्यता में निवल वृद्धि वस्तुतः रोजगार बाज़ार के औपचारिकरण की सीमा और संगठित/अर्द्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभों की पहुंच का संकेतक होता है।
 - EPFO के नवीनतम आंकड़े दर्शाते हैं कि नवंबर 2021 में EPF की सदस्यता में 14 लाख की निवल वृद्धि हुई है। यह नवंबर 2020 की तुलना में 109% की वृद्धि को दर्शाता है।

मनरेगा के तहत कार्य की मांग पर आधारित रोजगार संबंधी रुझान (Trends in data on demand for work under MGNREGS)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्य की मांग वस्तुतः ग्रामीण श्रम बाजारों का सूचक रहा है। हाल ही में, इसमें निम्नलिखित रुझान देखे गए हैं:

- दूसरी कोविड लहर के बाद मनरेगा के तहत कार्य की मांग कम हो गई है।
- कुल मनरेगा रोजगार अभी भी वैश्विक महामारी-पूर्व के स्तर से अधिक है।

Persons demanded work under MGNREGS (in Crores)



Source: MGNREGA portal, D/o Rural Development

वार्षिक PFLS आंकड़ों पर आधारित दीर्घकालिक रोजगार संबंधी रुझान

वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के बीच, लगभग 4.75 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति कार्यबल में शामिल हुए



¹⁰³ Labour force participation rate: LFPR

¹⁰⁴ Worker-population ratio: WPR

¹⁰⁵ Unemployment rates: UR

ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं (Policy responses to boost rural livelihood)

रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY): इसे कोविड के बाद पुनर्बहाली संबंधी चरण में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। ABRY के तहत, भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों और नियोक्ताओं के भविष्य निधि अंशदान हिस्सेदारी में योगदान दिया गया है।
दिहाड़ी / दैनिक रोजगार	- महात्मा गांधी नरेगा के लिए आवंटन को वित्त वर्ष 2020-21 के 62,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2021-22 में 73,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। - वित्त वर्ष 2021-22 में अभी तक 8 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। - अपने मूल स्थान को लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार तथा आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है।
स्वरोजगार को बढ़ावा देना	- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM): इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़कर, ग्रामीण निर्धनता के स्तर को कम करना है। - दिसम्बर 2021 तक, 8 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित कर लिया गया है।
सामाजिक सुरक्षा	- प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन (PM-SYM) योजना: यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर 3000 रुपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। - ई श्रम पोर्टल: असंगठित कामगारों (UW) के एक राष्ट्रीय डेटाबेस सृजित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि केंद्र और राज्य मंत्रालयों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। - जनवरी 2022 तक, 22 करोड़ से अधिक कामगार ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

श्रम सुधारों की स्थिति

- 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को समामेलित, युक्तिसंगत, सरलीकृत करते हुए चार श्रम संहिताओं में एकीकृत किया गया है:
 - वेतन संहिता, 2019
 - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
 - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य की परिस्थितियां संहिता, 2020
- नए कानूनों को बदलते श्रम बाज़ार की प्रवृत्ति के अनुरूप तैयार किया गया है। साथ ही, इन कानूनों में स्वरोजगार तथा प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी संबंधी अनिवार्यता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य

- वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्रक पर व्यय (कोविड के दौरान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रक) में लगभग 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, स्वास्थ्य क्षेत्रक से संबंधित व्यय वर्ष 2019-20 में 1.3% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 2.1% तक हो गया है। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के इसे वर्ष 2025 तक GDP का 2.5% करना है।)

स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए कार्यक्रम और योजनाएं

आयुष्मान भारत	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने के लिए, इसके तहत सतत देखभाल दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसमें दो परस्पर-संबंधित घटक शामिल हैं: - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र¹⁰⁶: इसके तहत 1,50,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। - आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना¹⁰⁷: जनवरी, 2022 तक AB-
---------------	--

¹⁰⁶ Ayushman Bharat Health and Wellness Centres: AB-HWCs

	PMJAY के तहत कुल 17.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
प्रधान मंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission: PM-ABHIM)	यह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणालियों की क्षमता को विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने तथा नए उभरते रोगों का पता लगाने और उनका उपचार प्रदान करने के लिए नए संस्थानों के निर्माण हेतु संचालित एक मिशन है।
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana: PM-SSY)	इसे एक किफायत तथा विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने तथा देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इसे आरंभ किया गया है।
ई-संजीवनी (e-Sanjeevani)	ई-संजीवनी एप्लीकेशन वस्तुतः रोगी और चिकित्सक के मध्य टेली-परामर्श की सुविधा प्रदान करती है। इसकी मदद से सभी नागरिकों को घर बैठे ही निरंतर देखभाल और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

स्वास्थ्य परिणाम संकेतक (Health Outcome Indicators)

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कुल जन्म दर, लिंगानुपात तथा स्वास्थ्य परिणाम संकेतकों जैसे शिशु मृत्यु दर, पाँच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर, संस्थागत जन्म दर में वर्ष 2015-16 से लेकर अब तक सुधार हुआ है।

बाल स्वास्थ्य संकेतक

संकेतक	वर्ष 2015 -16	वर्ष 2019-20
पाँच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (USMR)	49.7 प्रतिशत	41.9 प्रतिशत
शिशु मृत्यु दर (IMR)	40.7 प्रति हजार जन्मे बच्चों पर	35.2 प्रति हजार जन्मे बच्चों पर
ठिगनापन (Stunting)	38 प्रतिशत	36 प्रतिशत
दुबलापन (Wasting)	21 प्रतिशत	19 प्रतिशत
सामान्य से कम वजन (Underweight)	36 प्रतिशत	32 प्रतिशत

मुख्य पहल: पोषण अभियान, स्वस्थ भारत मिशन (SBM), विशेष टीकाकरण अभियान जैसे मिशन इंद्रधनुष, ग्राम स्वराज अभियान (GSA), विस्तारित GSA आदि।

जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)

वर्ष 2014-18 की अवधि के दौरान जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष (वर्ष 2013-17 की तुलना में 0.4 वर्ष की वृद्धि) थी।

छत्तीसगढ़ में सबसे कम (65.2), केरल और दिल्ली में सर्वाधिक (75.3)	ग्रामीण (68.0 वर्ष) की तुलना में शहरी क्षेत्रों (72.6 वर्ष) में अधिक रही है।	पुरुषों (68.2 वर्ष) की तुलना में महिलाओं (70.7 वर्ष) की जीवन प्रत्याशा अधिक रही है।
--	--	---

कुल जनन दर (Total Fertility Rate)

देश में कुल जनन दर, जनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर (2.1 बच्चे प्रति महिला) से भी नीचे आ गई है।	मणिपुर, मेघालय, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ कर सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने जनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर को हासिल कर लिया है।
--	--

कारण: यह स्थिति गर्भ निरोधकों के बढ़ते उपयोग, बेहतर परिवार नियोजन तथा बालिका शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना तक पहुंच और संस्थागत प्रसव में वृद्धि के कारण है।

- वर्ष 2015-16 के 78.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-21 में संस्थागत प्रसव बढ़कर 88.6 प्रतिशत हो गया है।

लिंगानुपात

	वर्ष 2015-16	वर्ष 2019-20
लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)	991	1020
जन्म के समय लिंगानुपात (प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या)	919	929
कारण: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना		

पेयजल एवं स्वच्छता (Drinking Water and Sanitation)

प्रमुख पहल

- जल जीवन मिशन (JJM):** JJM के तहत वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू जल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
 - वर्ष 2022 तक, ग्रामीण क्षेत्रों के 18.93 करोड़ परिवारों में से लगभग 5.5 करोड़ (30 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को नल से पेय जल की सुविधा प्रदान की गई है।
 - जल जीवन मिशन की प्रमुख विशेषताएं:
 - इसके तहत जल आपूर्ति संबंधी दृष्टिकोण में बदलाव करते हुए बस्तियों (उचित दूरी पर हैंडपंप, सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट आदि की सुविधा) के बजाय घरों में (घर तक कार्यात्मक नल) जल आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - यह केवल जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत प्रत्येक घर में पीने योग्य जल की सुनिश्चित आपूर्ति- 'सेवा वितरण' तथा 'कार्यात्मकता-' करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - प्रत्येक घर में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय ग्राम समुदाय को जल आपूर्ति प्रणाली के स्वामित्व, संचालन और रखरखाव आदि दायित्व प्रदान किया गया है।
 - महिलाओं की केंद्रीय भूमिका सुनिश्चित की गई है इसके तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति¹⁰⁸ / पानी समिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।
 - तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाएगी।
 - राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
 - जल की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM-G)

- ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और 2000 से अधिक गांवों को ओ.डी.एफ. (खुले में शौच से मुक्त) प्लस घोषित किया गया है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के पाँचवें दौर के अनुसार, बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली आबादी वर्ष 2015-16 में 48% से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 70% हो गई है।

विद्युत और स्वच्छ रसोई ईंधन (Electricity and Clean Cooking Fuel)

- NFHS-5 के अनुसार, वर्ष 2019-21 के दौरान 59% घरों में स्वच्छ रसोई ईंधन का उपयोग किया जा रहा था, जो वर्ष 2015-16 में 44% की तुलना उल्लेखनीय वृद्धि है।
- NFHS-5 के अनुसार, विद्युत् की सुविधा से युक्त घरों की संख्या वर्ष 2015-16 के 88 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 97% हो गई है। इसमें सभी के लिए विद्युत सुनिश्चित करने की दिशा में सौभाग्य योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

¹⁰⁸ Village Water & Sanitation Committee: VWSC

ग्रामीण और मानव विकास संबंध

विश्व बैंक ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के मूल्यांकन के दौरान पाया कि इस योजना के तहत निर्मित सड़कों का ग्रामीण भारत में मानवीय पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- वर्ष 2017 में माध्यमिक और हाई स्कूल के बच्चों की स्कूली शिक्षा में 0.7 वर्ष की वृद्धि हुई;
- संबंधित बस्तियों में घर में होने वाले प्रसव में 30% की गिरावट देखी गई;
- चार वर्ष की कम आयु के बच्चों के टीकाकरण में 15% की वृद्धि देखी गई, जिसमें लड़कों और लड़कियों को समान रूप से लाभ हुआ।

ग्रामीण विकास

- **प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G):** इसका उद्देश्य 2.95 करोड़ घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 2.17 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही, वर्ष 2021-22 तक 2.63 करोड़ घरों का निर्माण करने के लक्ष्य में से 1.69 करोड़ घरों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):** वर्ष 2022 तक 7,82,844 किलोमीटर की लम्बाई वाले कुल 1,82,506 सड़कों को मंजूरी प्रदान की गई है और 6,84,994 किलोमीटर की लम्बाई वाली 1,66,798 सड़कों के काम को पूर्ण कर लिया गया है।
- **बहुआयामी निर्धनता (Multidimensional Poverty):** नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2015-16 में भारत में 25% परिवार बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित पाए गए हैं। बिहार सर्वाधिक (51.91%) इसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित पाए गए हैं।

अध्याय एक नज़र में

- कोविड-19 प्रकोप के दौरान, जीवन और आजीविका के संरक्षण हेतु भारत ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। इस संबंध में सरकार का मुख्य ध्यान, वंचित/कमजोर वर्गों को सुरक्षा कवच प्रदान करना और वैश्विक महामारी जनित स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के लिए एक सुसंगत प्रतिक्रिया करना रहा है।
- कोविड के विरुद्ध भारत की स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं में मजबूत टीकाकरण रणनीति, कोविड परीक्षण के लिए आधारभूत ढांचा, मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और कोविड-रोधी दवाओं का विकास शामिल रहा है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य) से संबंधित व्यय वर्ष 2014-15 के 6.2% से बढ़कर वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) में 8.6% हो गया है।
- TFR वर्ष 2015-16 के 2.2 से गिरकर वर्ष 2019-21 में 2 हो गई है।
- स्कूल नामांकन में बढोतरी और ड्रॉपआउट में गिरावट के साथ स्कूल के आधारभूत ढांचे में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2019-20 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात भी बढ़कर 27.1% तक पहुँच गया है।
- जल जीवन मिशन (JJM) के अधीन 83 जिले 'हर घर जल' जिले बन चुके हैं।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के लिए निधि आवंटन में वृद्धि हुई है।

अध्याय-10



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. भारत में उच्चतर शिक्षा की प्रवृत्ति (18–23 वर्ष) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- वर्तमान में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है।
- महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात पुरुषों की तुलना में अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

Q2. जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) में दर्शाया गया है, भारत ने पिछले दो दशकों में अपने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस संदर्भ में, भारत के स्वास्थ्य परिणाम संकेतकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- शिशु मृत्यु दर 20 से कम है।
- बच्चों के ठिगनापन, दुर्बलता और कम वजन के संकेतक 30 प्रतिशत से ऊपर हैं।
- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बिहार में सबसे कम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

Q3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

- | पहल: | लक्ष्य |
|---|--|
| 1. असीम पोर्टल..... | : कुशल कार्यबल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए |
| 2. इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर (IISC) नेटवर्क..... | : अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और विदेशी रोजगार के लिए कौशल का आकलन करने के लिए |
| 3. पी.एम.-दक्ष योजना..... | : अल्पसंख्यकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए |

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

Q4. सरकार के सामाजिक व्यय की प्रवृत्तियों (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- विगत पांच वर्षों के दौरान कुल सरकारी व्यय में सामाजिक सेवाओं का योगदान लगभग 25 प्रतिशत था।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय 2 प्रतिशत से कम है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय 3 प्रतिशत से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

Q5. निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त नहीं किया गया है?

- (a) राजस्थान
- (b) मेघालय
- (c) गुजरात
- (d) असम



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में युवाओं में व्यापक हताशा के पीछे बेरोजगारी को एक प्रमुख कारक माना जाता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस हताशा को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को भी लिखिए।

Q2. संपूर्ण देश में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने में भारत द्वारा उपयोग की जाने वाली बहुआयामी रणनीति पर चर्चा कीजिए।

ADVANCED COURSE GS MAINS



Targeted towards those students who are aware of the basics but want to improve their understanding of complex topics, inter-linkages among them, and analytical ability to tackle the problems posed by the Mains examination.



Covers topics which are conceptually challenging.



Approach is completely analytical, focusing on the demands of the Mains examination.



Mains 365
Current Affairs
Classes (Offline)



Comprehensive current affairs notes



Sectional Mini Tests



Duration: 12 weeks, 5-6
classes a week (If need
arises, class can be held
on Sundays also)

Scan the QR CODE to
download VISION IAS app



**ADMISSION
OPEN**



**LIVE/ONLINE
CLASSES AVAILABLE**

अध्याय 11: उपग्रह से प्राप्त छवियों और मानचित्रण द्वारा विकास की निगरानी (Tracking Development Through Satellite Images & Cartography)

परिचय

भारत में भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रण (कार्टोग्राफिक) तकनीकों का उपयोग आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रखने, दीर्घकालिक विकास का आकलन और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है।

भू-स्थानिक मानचित्र द्वारा उपयोगकर्ता न केवल डेटा उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि इससे उपयोगकर्ताओं को रुझानों, संबंधों और प्रतिरूपों को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। दूसरी ओर मानचित्रण तकनीक सूचना के बेहतर प्रदर्शन की भी सुविधा प्रदान करती है।

प्रमुख अवलोकन इस प्रकार हैं:

संकेतक	वर्तमान में	रुझान
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई	1.4 लाख कि.मी. (अगस्त, 2021)	वर्ष 2011 से वर्ष 2021 के मध्य लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है।
भारत में संचालित हवाई अड्डों की संख्या	130 (दिसंबर, 2021)	वर्ष 2016 से वर्ष 2021 के मध्य दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है।
वाणिज्यिक बैंक शाखाएँ	1.2 लाख (मार्च, 2021)	वर्ष 2011 से वर्ष 2021 के मध्य 1.65 गुना वृद्धि हुई है।
भारत में कुल बोया गया क्षेत्र	157 मिलियन हेक्टेयर (2020-21)	वर्ष 2006 से वर्ष 2021 के मध्य 1.25 गुना वृद्धि हुई है।

भू-स्थानिक डेटा प्राप्त करने और प्रकाशित करने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश

भू-स्थानिक डेटा को पूर्व में अत्यधिक विनियमन के अधीन रखा जाता था एवं इसके उपयोग हेतु लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। स्वतंत्र एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भू-स्थानिक डेटा और सेवाओं में वृद्धि को देखते हुए पूर्ववर्ती प्रतिबंध अनावश्यक हो गए थे। इन प्रतिबंधों ने इस क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को गंभीर रूप से बाधित किया था। उल्लेखनीय है कि इन प्रतिबंधों के कारण घरेलू अभिकर्ता भी विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं।

जारी किये गए नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एक अधिक अनुमोदित व्यवस्था का निर्माण करना है, ताकि इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय कंपनियों को समर्थन प्रदान करते हुए उद्योग के मध्य सहभागिता और उनकी प्रगति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। **दिशा-निर्देशों के तहत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:**

- **स्व-प्रमाणन व्यवस्था की शुरुआत:** पूर्व अनुमोदन या लाइसेंस प्राप्त करने के स्थान पर इस व्यवस्था की शुरुआत की गई है।
- **प्रतिबंधित क्षेत्रों में छूट:** अत्यधिक संवेदनशील स्थानों से संबंधित विशिष्ट विशेषताओं के लिए ही अब मानचित्रण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
- **भारतीय संस्थाओं/संस्थानों के लिए विशेष अनुमति:** भू-स्थानिक डेटा से संबंधित गतिविधियों को गैर-भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता, यह अनुमति केवल भारतीय संस्थाओं/संस्थानों को प्रदान की गई है।
- **निर्यात प्रतिबंधों पर छूट:** संशोधित दिशा निर्देश 1:100 रिज़ॉल्यूशन तक के मानचित्रों को तैयार करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यह 1:250000 की पिछली सीमा की तुलना में थोड़ी राहत प्रदान करता है।
- **वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित भू-स्थानिक डेटा तक खुली पहुँच की सुविधा प्रदान की गई है।**

अध्याय-11



स्मरण और समझ संबंधी कौशल का परीक्षण

Q1. मानचित्रण (कार्टोग्राफी) और उपग्रह से प्राप्त चित्रों के माध्यम से एकत्रित भारत से संबंधित जानकारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वर्ष 2011 से वर्ष 2021 के बीच चार गुनी हो गई है।
2. निवल बोया गया क्षेत्र पिछले पंद्रह वर्षों में 1.25 गुना बढ़ा है।
3. विगत पांच वर्षों में भारत में परिचालित विमान पत्तनों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 2 और 3
- (b) केवल 1
- (c) 1, 2 और 3
- (d) केवल 2



स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. भू-स्थानिक डेटा प्राप्त करने और उत्पादन करने के दिशा-निर्देशों को समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया गया है। चर्चा कीजिए।

Q2. भू-स्थानिक डेटा और कार्टोग्राफिक तकनीक आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विस्तार से चर्चा कीजिए।

PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र

by

ANOOP KUMAR SINGH

Classroom Features:

- ✓ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- ✓ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- ✓ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- ✓ Effective Answer Writing
- ✓ Revision Classes
- ✓ Printed Notes
- ✓ All India Test Series Included

Offline Classes @

JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD

हिन्दी माध्यम
में भी उपलब्ध

Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

Daily Tests:

- ✓ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
- ✓ Focus on Concept Building & Language
- ✓ Introduction-Conclusion and overall answer format
- ✓ Doubt clearing session after every class

Mini Test:

- ✓ After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
- ✓ Copies will be evaluated within one week

ANSWER KEY

Chapter 1

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
b	c	d	b	a

Chapter 2

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
b	b	c	c	d

Chapter 3

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
b	d	a	c	d

Chapter 4

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
d	a	c	d	a

Chapter 5

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
b	b	a	d	d

Chapter 6

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
b	a	a	b	a

Chapter 7

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
c	a	a	c	c

Chapter 8

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
c	d	b	c	d	b	b

Chapter 9

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
a	b	a	b	a

Chapter 10

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
b	d	b	a	b

Chapter 11

Q1
a

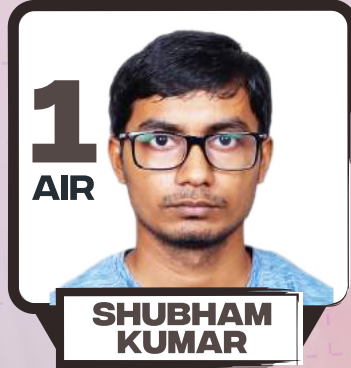
Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Heartiest Congratulations to all successful candidates

▶ **10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020**

FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS



8468022022

WWW.VISIONIAS.IN



DELHI | JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | HYDERABAD | CHANDIGARH | LUCKNOW | GUWAHATI